जने पन्यास
JNPT

INDIA'S
NO.1
CONTAINER
PORT

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST (JNPT)

SUSTAINABILITY REPORT 2020-21

INDIA'S
NO.1
CONTAINER
PORT

JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST (JNPT)

SUSTAINABILITY REPORT 2020-21

CONTENTS

ABOUT THE REPORT	04
MESSAGE FROM THE CHAIRMAN	06
JNPT FY2020–21 PERFORMANCE SNAPSHOT: ECONOMIC, ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND OPERATIONAL	10
INTRODUCTION	12
SUSTAINABILITY AT JNPT	30
ECONOMIC PERFORMANCE	48
OPERATIONAL EXCELLENCE	54
ENVIRONMENT MANAGEMENT	76
SOCIAL AND HUMAN CAPITAL	102
ANNEXURES	134
GRI CONTENT INDEX	140

विषय-वस्तु

रिपोर्ट के बारे में	05
जनेप न्यास अध्यक्ष का संदेश	07
जेएनपीटी वित्तीय वर्ष 2020–21 कार्यप्रदर्शन की झलकियां: आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रचालन संबंधी	11
परिचय	13
जेएनपीटी में सस्टेनेबिलिटी	31
आर्थिक निष्पादन	49
प्रचालनीय उत्कृष्टता	55
पर्यावरण प्रबंधन	77
सामाजिक और मानवीय पूँजी	103
अनुलग्नक	135

About the Report

This is the first Sustainability Report of Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). The report reflects JNPT's commitments and achievements in fostering leadership in sustainability and creating value while adhering to the economic, social, and environmental parameters of the Global Reporting Initiative (GRI) Standards 2020. This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Option. The GRI Content Index guides readers to the sections where information on the relevant indicators, as defined by the GRI Standards, is given in this report. The report boundary is Jawaharlal Nehru Port Trust, Sheva, located in Navi Mumbai, Maharashtra for the period April 2020-March 2021. The entities covered in the report boundary are terminals including JNPCT, NSICT, NSIGT, GTI-APM, BMCT, and BPCL in addition to a liquid bulk terminal, a shallow water berth, and a JNPT township. Going forward, JNPT will maintain an annual reporting cycle to share insights on its sustainability performance.

The information in the Economic Performance section has been reported with reference to JNPT's Annual Report 2019-20. The financial statements in the Annual Report have been prepared in accordance with the requirements as stated under Section 102 (1) of the Major Ports Trusts Act, 1963. The data and information on environment and social parameters have been derived from official JNPT documents, along with the Administration Report and the Annual Report for the reporting period.

The Energy and Resources Institute (TERI) has evaluated and analyzed the results to ensure that the report adheres to the principles of Report Contents viz. Stakeholder Inclusiveness, Sustainability Context, Materiality, and Completeness; and the principles of Report Quality viz. Balance, Comparability, Accuracy, Timeliness, Clarity and Reliability.

Contact Information

The JNPT Sustainability Report FY2020-21 and additional information on the Port's sustainability journey are available on JNPT's official website. The point of contact for the information in this report is Shri G. Vaidyanathan (Chief Manager, Port Planning Development Department, JNPT). Any query or suggestions with respect to this report may be addressed to Shri G. Vaidyanathan at the registered office address or via email to cmppd@jnport.gov.in.

GRI 102-1 | GRI 102-3 | GRI 102-50 | GRI 102-52 | GRI 102-53 | GRI 102-54

रिपोर्ट के बारे में

यह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) की पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशिएटिव (जीआरआई) स्टैंडर्ड्स 2020 के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मापदंडों का पालन करने के साथ सस्टेनेबिलिटी में नेतृत्व मज़बूत बनाने और मूल्य सृजन करने के लिए जेएनपीटी की प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों पर विचार किया गया है। यह रिपोर्ट जीआरआई मानकों के अनुरूप तैयार की गई है: मूल विकल्प। जीआरआई विषयसूची पाठकों के लिए उन खण्डों का मार्गदर्शन करती है जहां इस रिपोर्ट में जीआरआई मानकों द्वारा निर्धारित प्रासंगिक मानकों पर जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट का दायरा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, शेवा, जो कि नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में स्थित है, के लिए अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक की अवधि से संबंधित है। रिपोर्ट के दायरे में शामिल की गई संस्थाओं में टर्मिनल जैसे कि जेएनपीसीटी, एनएसआईसीटी, एनएसआईजीटी, जीटीआई-एपीएम, बीएमसीटी और बीपीसीएल, तथा इसके अलावा एक लिक्विड बल्क टर्मिनल, एक शैलो वॉटर बर्थ और एक जेएनपीटी टाउनशिप सम्मिलित है। आगे, जेएनपीटी अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक वार्षिक रिपोर्टिंग क्रम का पालन करेगा।

आर्थिक कार्यप्रदर्शन खण्ड में दी गई जानकारी, जेएनपीटी की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के संदर्भ में दी गई है। वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों को, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अनुभाग 102 (1) में उल्लेखित अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया गया है। पर्यावरण और सामाजिक मापदंडों पर डेटा और जानकारी, जेएनपीटी के आधिकारिक दस्तावेजों, तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए प्रशासन रिपोर्टऔर वार्षिक रिपोर्ट से प्राप्त की गई है।

दि एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) ने परिणामों का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हुए रिपोर्ट में, रिपोर्ट विषयवस्तु के सिद्धांतों जैसे कि हितधारक समावेशिता, सस्टेनेबिलिटी, संदर्भ, यथार्थता और पूर्णता; और रिपोर्ट गुणवत्ता जैसे कि संतुलन, तुलनीयता, परिशुद्धता, समयबद्धता, स्पष्टता और विश्वसनीयता का पालन किया जाना सुनिश्चित किया है।

संपर्क जानकारी

जेएनपीटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2020-21 और पत्तन की सस्टेनेबिलिटी की यात्रा के बारे में अतिरिक्त जानकारी जेएनपीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट की जानकारी के लिए संपर्क सूत्र श्री जी. वैद्यनाथन (मुख्य प्रबंधक, पत्तन नियोजन विकास विभाग, जेएनपीटी) हैं। इस रिपोर्ट के संबंध में कोई प्रश्न या सुझाव श्री जी. वैद्यनाथन को कार्यालय के पंजीकृत पते पर या cmppd@jnport.gov.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है।

Message from the Chairman, JNPT

Dear Stakeholders,

Presenting the 1st Edition of JNPT's Sustainability Report for the financial year 2020-2021, is a matter of privilege and pride. The report is compliant with the GRI Standards and aims to showcase our efforts towards Environmental protection. The Port has made remarkable progress in last 32 years on all fronts like infrastructure development, traffic handling, revenue generation, environmental aspects etc. JNPT is committed to sustainable development and adequate measures are being taken to maintain ecological balance. The total land available with JNPT is around 3402 hectares out of this, 1147 hectares area (34%) of the port is under green cover including mangroves. In three decades of its operations, JNPT has transformed from a bulk- cargo terminal to become the premier container port in the country. JNPT is connected to over 200 ports in the world and is ranked 33rd in the list of top 100 Container Ports globally.

JNPT is committed to achieve fostering leadership in sustainability and creating value for the trade – depicted across the economic, social, and environmental parameters.

The commitment to sustainable development by JNPT is exhibited through the various initiatives and measures undertaken to maintain ecological balance. The Green Port Initiatives also include installed Sewage Treatment Plant, Setup Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) & Environmental Monitoring through IIT Madras, Comprehensive Solid Waste Management Facility with 10 MT/Day capacity, upgradation of roads, projects related to use of renewable energy as Roof Top Solar System, Energy saving/conservation projects as Shore Power Supply, E-RTGCs, Electric vehicles, LED Lamp Replacement Work for Port Area, marine conservancy, comprehensive plantation, Initiative for ease of Traffic Congestion Initiative for the ease of Traffic at Centralized Parking Plaza MARPOL provisions and sustainable development in all operations. Under simplification of the process, the Port commenced the inter-terminal movements and dispensed with seal checking by CISF at the Gate. The Port also focused to increase the DPD (Direct Port Deliveries) and Direct Port Entry (DPE).

Despite challenges owing to COVID-19, JNPT facilitated a new Centralized Parking Plaza. The port also received the operational status for India's first port-based Special Economic Zone (SEZ). The port completed the construction of a coastal berth with the capacity to handle 2.5 million tons of coastal cargo including liquid cargo and inaugurated Internal Terminal Route which helps in enhancing the operational efficiencies. Under improvement of infrastructure, JNPT created parking plaza for undocumented export containers, facilitated infrastructure for Customs

जनेप न्यास अध्यक्ष का संदेश

प्रिय हितधारकों,

जनेप न्यास की वित्तीय वर्ष 2020-2021 की संपोषणीयता रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस हो रहा है । यह रिपोर्ट वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानकों के अनुरुप है और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे प्रयासों को प्रदर्शित करना है । पत्तन ने पिछले 32 वर्षों में बुनियादी ढांचे के विकास, यातायात प्रबंधन, राजस्व सृजन, पर्यावरणीय पहलुओं जैसे सभी मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है । जनेप न्यास संपोषणीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं । जनेप न्यास के पास लगभग 3402 हेक्टेयर की कुल भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 1147 हेक्टेयर क्षेत्र (34%) कच्छ वनस्पति (मैंग्रोव) सहित हरित क्षेत्र है । अपनी तीन दशकों की यात्रा में, जनेप न्यास बल्क-कार्गो टर्मिनल से कंटेनर टर्मिनल में परिवर्तित होकर के देश का मुख्य कंटेनर पत्तन बन गया है। जनेप न्यास विश्व के 200 से अधिक पत्तनों से जुड़ा है और विश्व के शीर्ष 100 कंटेनर पत्तनों में 33 वें स्थान पर है ।

जनेप न्यास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मानकों के अधीन रहकर संपोषणीयता और व्यापार में मूल्य निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है ।

पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए विभिन्न पहलों और उपायों के माध्यम से जनेप न्यास द्वारा संपोषणीय विकास की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है । हरित पत्तन पहल में मलजल उपचार संयंत्र, निरंतर परिवेषी वायु निगरानी केंद्र और आयआयटी मद्रास के माध्यम से पर्यावरण निगरानी, प्रतिदिन 10 मीट्रिक टन क्षमता की व्यापक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, सड़कों का उन्नयन, रुफ टॉप सोलर सिस्टम जैसे नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं । ऊर्जा बचत/संरक्षण के लिए तट पर बिजली आपूर्ति, ई-आरटीजीसी, इलेक्ट्रिक वाहन, पत्तन क्षेत्र में एलईडी लैंप का उपयोग, समुद्री संरक्षण, व्यापक वृक्षारोपण, सुगम यातायात के लिए पहल, वाहनों की भीड़ कम करने के लिए केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा पहल में मारपोल प्रावधान और सभी कार्यों में संपोषणीय विकास । प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए पत्तन ने अंतर-टर्मिनल गतिविधियांयों की शुरुआत की है और प्रवेश द्वार पर के.औ.सु.बल द्वारा सील की जांच करने की प्रक्रिया बंद कर दी है । पत्तन ने सीधे पत्तन में सुपुर्दगी और सीधे पत्तन में प्रवेश को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है ।

कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद जनेप न्यास ने नए केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा की सुविधा शुरु की है । पत्तन को भारत का प्रथम पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) कार्यरत करने का दर्जा भी प्राप्त हुआ है । पत्तन ने एक तटीय घाट का निर्माण पूरा किया जिसकी तटीय कार्गो प्रहस्तन क्षमता तरल कार्गो सहित 2.5 मिलियन टन की है और आंतरिक टर्मिनल मार्ग का उद्घाटन किया है जिससे जो प्रचालन दक्षता वृद्धि में मदद हुई है । बुनियादी ढांचे में सुधार के तहत जनेप न्यास ने अप्रयोजित निर्यात कंटेनरों के लिए पार्किंग प्लाजा विकसित किया है जिसमें सीमा शुल्क मंजूरी के लिए की सुविधा उपलब्ध कराई गई है । सड़कों को चौड़ा करना और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जारी है ।

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास का वित्त वर्ष 2020-21 का पंजीकृत व्यवसाय (कंटेनर प्रहस्तन) 4.7 मिलियन टीईयू रहा जबकि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान पंजीकृत

for clearance in the Parking Yards, commenced the Centralized Parking Plaza Project, and the widening of roads and other infrastructure projects.

Jawaharlal Nehru Port Trust, registered a throughput of over 4.7 million twenty-foot equivalent units (TEUs) in container handling as against 5.03 million TEUs during FY 2020. The total traffic handled at JNPT during the Financial Year 2020-21 is 64.81 million tons as against 68.45 million tons in FY 2019-20.

Major improvement in Avg. Turn-round Time of all vessels by 2.62% i.e. from 29.42 hrs. to 28.64 hrs. as well as for container vessels by 2.01% i.e. from 25.82 hrs. to 25.30 hrs. from Pilot Boarding to De-boarding in FY 2020-21 in comparison with FY 2019-2020.

The JNPT has an Integrated Management System (IMS) which includes Quality Management System - ISO 9001:2015, Environmental Management System-ISO 14001:2015, Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018, and Information Security Management System ISO 27001:2013 and In the process of Energy Management System i.e., ISO 50001- 2018 ISO certifications.

JNPT, as part of its Corporate Social Responsibility and Corporate Environment Responsibility engage with local groups and associations to implement targeted programmes that emphasize good health and family welfare, quality education, sustainable livelihoods, Skill Development Trainings, water conservation, promotion of sports, promotion of the art and culture. Community infrastructure to contribute to the socio-economic development of the local community and ecological development in its area of influence as Rain Water harvesting, conservation, protection wall to Elephanta Island & Panje village and Boat landing jetty at Nhava Island.

JNPT is committed to play its part efficiently and effectively to achieve the above along with continual improvement in its performance and progress as Organization. As an organization, we are dedicated and focused towards expanding our core business segments of Port development.

At JNPT, We believe in building trust amongst our stakeholders and assure them transparent, responsive and efficient services. We work towards ensuring our employees' safety, satisfaction and happiness and keep our communication channels open to all our stakeholders. We respect the natural habitats and the local communities in the areas we operate in and work towards nurturing its flora and fauna. JNPT's CSR & CER projects/activities continue to reshape sustenance and livelihood.

JNPT's Proposed Vadhavan project is a "Greenfield" project and it is proposed to construct in such a way that, it will have minimal impact to the environment, fishery activities, mangroves and locals. This project will have substantial positive impact on socio-economic profile of Vadhavan, in and around Dahanu, both in terms of overall employment and skill development of local workforce.

Our philosophy of creating value beyond business and keeping sustainable development at the heart of business is embodied in this report aptly titled Execution, Efficiency & Excellence and reasserts our resolve to create a sustainable future for our stakeholders. I look forward to your valuable comments and feedback on our initiatives so as to enhance the delivery in all our sustainable engagements.

Sanjay Sethi (IAS)
Chairman JNPT

व्यवसाय 5.03 मिलियन टीईयू हुआ था । जनेप न्यास में वित्त वर्ष 2019-20 में प्रहस्तित 68.45 मिलियन टन यातायात की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 64.81 मिलियन टन प्रहस्तन हुआ।

वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में सभी जलयानों के औसत घुमाव समय में बड़ा सुधार आया । पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष औसत घुमाव समय 2.62 प्रतिशत कम रहा अर्थात 29.42 घंटे से घट कर 28.64 घंटे हुआ, साथ ही कंटेनर जलयान के लिए पायलट बोर्डिंग से डी-बोर्डिंग का समय 2.01 प्रतिशत कम रहा अर्थात 25.82 घंटे से घट कर 25.30 घंटे रहा ।

जनेप न्यास में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली है जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली- आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली- आईएसओ 14001:2015, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 45001:2018 और सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 27001:2013 शामिल हैं और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 50001- 2018 आईएसओ प्रमाणन प्रक्रिया में है ।

जनेप न्यास अपने निगमित सामाजिक दायित्व और निगमित पर्यावरण दायित्व के रूप में स्थानीय समूहों और संघों के साथ मिलकर बेहतर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, संपोषणीय आजीविका, कौशल विकास प्रशिक्षण, जल संरक्षण, खेल, कला और संस्कृति आदि को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है । जनेप न्यास ने स्थानीय समुदाय के सामाजिक-आर्थिक विकास और पारिस्थितिक विकास में योगदान के लिए वर्षा जल संचय, संरक्षण, एलिफेंटा द्वीप और पाँजे गांव के लिए सुरक्षा दीवार और न्हावा द्वीप में अवतरण घाट आदि सुविधाएँ विकसित की है ।

जनेप न्यास अपने प्रदर्शन में निरंतर सुधार और प्रगति में निरंतर सुधार के साथ-साथ उपरोक्त को प्राप्त करने हेतु कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है । एक संगठन के रूप में, हम पत्तन विकास के मुख्य व्यवसाय के विस्तार के लिए समर्पित तथा उस पर पूरा ध्यान केंद्रित है ।

जनेप न्यास में हम अपने हितधारकों के बीच विश्वास निर्माण करने में भरोसा हैं और उन्हें पारदर्शी, उत्तरदायी और कुशल सेवाओं का आश्वासन देते हैं । हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा, संतुष्टि और खुशी सुनिश्चित करने की दिशा में काम करते हैं तथा हमारे सभी हितधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तैयार रहते है । पत्तन प्रचालन क्षेत्र के प्राकृतिक आवासों और स्थानीय समुदायों का हम सम्मान करते हैं तथा वनस्पतियों और जीवों के परिपोषण की दिशा में भी काम करते हैं । जनेप न्यास की निगमित सामाजिक दायित्व और निगमित पर्यावरणीय दायित्व परियोजनाएं/गतिविधियां स्थानीय समुदाय की उपजीविका और आजीविका को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

जने प न्यास की प्रस्तावित वाढवण परियोजना एक "ग्रीनफील्ड" परियोजना है जिसके निर्माण से पर्यावरण, मत्स्य गतिविधियों, कच्छ वनस्पति (मैंग्रोव) और स्थानीय लोगों पर कम से कम प्रभाव पड़ेगा। वाढवण पत्तन के निर्माण से स्थानीय लोगो कों रोजगार प्राप्त होगा और उनका कौशल विकास होकर वाढवण, डहाणू और उसके आसपास के परिसर के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

व्यवसाय से परे मूल्य निर्माण करना और व्यवसाय के केंद्र में संपोषणीय विकास को रखने का हमारा दृष्टिकोण इस रिपोर्ट में सन्निहित है जिसे निष्पादन, दक्षता और उत्कृष्टता कहा गया है साथ ही यह रिपोर्ट हमारे हितधारकों के लिए एक संपोषणीय भविष्य निर्माण करने का हमारे संकल्प की पुष्टि करता है । हमारी पहलों पर आपकी बहुमूल्य टिप्पणियों और प्रतिक्रिया की हमें प्रतीक्षा है ताकि हमारे सभी संपोषणीय कार्यों में बढ़ोत्तरी की जा सके ।

संजय सेठी (भा.प्र.से.)
अध्यक्ष, जनेप न्यास

JNPT FY 2020-21
Performance Snapshot: Economic, Environmental, Social, and Operational

181
Economic Value Retained (₹ in crore)

804
Profit After Tax (PAT) (₹ in crore)

16.43
Investments in Environment Protection (₹ in crore)

34%
Port Area under Green Cover

21,39,714
Renewable Energy Generation (in kWh)

80.00
Average Gross Berth Productivity (moves/hr)

50.4
Overall
Average Vessel Turnaround Time (in hr)

33.12
Average Vessel Turnaround Time – Container (in hr)

Import: 24.60
Export: 74.80
Overall: 44.80
Average Container Dwell Time (in hr)

Overall: 26,875
Containers: 34,275
Average Ship Berth Day Output (in tonne)

19.32
CSR Investment (₹ in crore)

- Economic
- Environment
- Operational
- Social

जेएनपीटी वित्तीय वर्ष 2020-21
कार्यप्रदर्शन की झलक: आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रचालन संबंधी

181
प्रतिधारित आर्थिक मूल्य
(₹ करोड़ में)

804
कर पश्चात लाभ (पीएटी)
(₹ करोड़ में)

16.43
पर्यावरण संरक्षण में निवेश (₹ करोड़ में)

34%
हरित आच्छादन के अंतर्गत पत्तन का क्षेत्रफल

21,39,714
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (किलोवाट घंटे में)

80.00
औसत सकल घाट उत्पादकता (फेरे/प्रतिघंटा)

50.4
समग्र
औसत जहाज घुमाव समय (घंटे में)

33.12
औसत जहाज घुमाव समय – कंटेनर (घंटे में)

आयात करें 24.60
निर्यात: 74.80
समग्र: 44.80
औसत कंटेनर विराम समय (घंटे में)

समग्र: 26875
कंटेनर: 34275
औसत जहाज घाट दिवस उत्पादकता (टन में)

19.32
सीएसआर में निवेश
(₹ करोड़ में)

- आर्थिक
- पर्यावरण
- प्रचालन संबंधी
- सामाजिक

Introduction

History and Legacy

In three decades of its operations, JNPT has transformed from a bulk cargo terminal to become the premier container port in the country.

Currently, JNPT operates five container terminals – Jawaharlal Nehru Port Container Terminal (JNPCT), Nhava Sheva International Container Terminal (NSICT), Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL), Nhava Sheva International Gateway Terminal (NSIGT), and Bharat Mumbai Container Terminals Private Limited (BMCT). The port also has a shallow water berth for handling containers, liquid, cement, general cargo, and a twin-berth liquid cargo terminal, which is managed by the BPCL-IOCL consortium. JNPT has developed a dedicated Coastal Berth having capacity of 2.5 MMTPA to handle Coastal Cargo Traffic.

Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) is the biggest container handling port in India, accounting for around

50%

of the total volume of containerized cargo across the major ports of the country. Located in Navi Mumbai, the Port was commissioned on ***26 May 1989***.

JNPT is connected to over

200

ports in the world directly or indirectly and is ranked

33rd

in the list of world's top

100

container ports.

The fourth container terminal is being developed in two phases of which Phase-I is operational and Phase-II is expected to be fully operational by March 2026 with a total quay length of 2000 metre, adding a combined annual capacity of 4.8 million Twenty Foot Equivalent (TEU). JNPT has developed a multi-product SEZ in its owned freehold land of 277 hectare to attract international capital and global giants in manufacturing. Additionally, JNPT is also developing a satellite port in Vadhavan and four dry ports – Jalna, Wardha, Sangli, and Nashik – to promote industrialization in the hinterland. JNPT has anchored itself as the major catalyst for trade and commerce in the country and is committed to provide seamless services to the world.

GRI 102-2 | GRI 102-3 | GRI 102-6 | GRI 102-7

परिचय

इतिहास और विरासत

अपने प्रचालनों के तीन दशक में, जेएनपीटी ने एक बल्क कार्गो टर्मिनल से अपना रूपांतरण किया है और यह देश में एक प्रमुख कंटेनर पत्तन बन गया है।

वर्तमान में, जेएनपीटी पांच कंटेनर टर्मिनल– जवाहरलाल नेहरु पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी), न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (एनएसआईसीटी), एपीएम टर्मिनल्स, न्हावा शेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल (एनएसआईजीटी) और भारत मुम्बई कंटेनर टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड (बीएमसीटी) का प्रचालन करता है। पत्तन में कंटेनर, लिक्विड, सीमेन्ट, सामान्य कार्गो हैंडल करने के लिए एक शैलो वॉटर बर्थ और एक ट्विन बर्थ लिक्विड कार्गो टर्मिनल भी है, जिसे बीपीसीएल - आईओसीएल कंसोर्टियम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जेएनपीटी ने कोस्टल कार्गो यातायात को संभालने के लिए 2.5 एमएमटीपीए क्षमता की एक समर्पित कोस्टल बर्थ विकसित की है

जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) भारत में सबसे बड़ा कंटेनर हैंडलिंग पत्तन है, जो देश में प्रमुख पत्तनों के कंटेनराइज्ड कार्गो का लगभग

50%

*संभालता है। नवी मुम्बई में स्थित इस पत्तन को **26 मई 1989** को शुरु किया गया था।*

जेएनपीटी, विश्व में सीधे या परोक्ष रूप से

200

से अधिक पत्तनों से जुड़ा है और विश्व की शीर्ष

100

कंटेनर पत्तनों में इसका स्थान

33वां

है।

चौथा कंटेनर टर्मिनल दो चरणों में विकसित किया जा रहा है जिसमें से फेज़-I कार्य करना आरंभ कर चुका है और फेज़-II 2000 मीटर की कुल क्वे लंबाई के साथ मार्च 2026 तक पूर्ण प्रचालित होना अपेक्षित है जिससे संयुक्त वार्षिक क्षमता 4.8 मिलियन ट्वेंटी फुट इक्विवैलेंट (टीईयू) हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पूँजी और बड़ी वैश्विक निर्माता कंपनियों को आकर्षित करने के लिए, जेएनपीटी ने अपने स्वामित्व वाली 277 हेक्टेयर फ्रीहोल्ड भूमि पर एक मल्टी-प्रोडक्ट एसईजेड विकसित किया है। इसके अलावा, आंतरिक क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए, जेएनपीटी वाढवण में एक सैटेलाइट पत्तन और चार शुष्क पत्तनों – जालना, वर्धा, सांगली और नासिक का भी विकास कर रहा है। जेएनपीटी ने खुद को देश में व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में स्थापित किया है और विश्व को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

JNPT Location

Jawaharlal Nehru Port is located at 18° 56′ 43″ N (latitude) and 72° 56′ 24″ E (longitude) along the eastern shore of Mumbai harbour, south-east of Elephanta Island (Table 1).

Table 1: Topography of JNPT

LOCATION			ENTRANCE CHANNEL		TURNING CIRCLE		TYPE OF DOCK/PORT
Latitude	Longitude	Length of channel	Minimum depth (m)	Minimum width (m)	No.	Diameter (m)	
18° 56′ 43″ North	72° 56′ 24″ East	19.17 nautical mile	14.4–15.6	450	1	600	All-weather tidal port

One of the key advantages JNPT offers is its proximity to Mumbai, India's economic capital. It also boasts of a robust network of rail and road connected to some of the major cities across the country (Figure 1).

Figure 1: JNPT map co-ordinates

Road Connectivity

The major road linkages connecting JNPT with the hinterland include NH4B, NH4, NH17, NH3, NH8, and State Highway 54

जेएनपीटी की लोकेशन

जवाहरलाल नेहरु पत्तन, मुम्बई हार्बर के पूर्वी तट पर, एलिफैंटा द्वीप के दक्षिण-पूर्व में 18° 56′ 43″ एन (अक्षांश) और 72° 56′ 24″ ई (देशांतर) पर स्थित है (तालिका 1)।

तालिका 1: जेएनपीटी की स्थलाकृति

लोकेशन			प्रवेश चैनल		टर्निंग सर्किल		डॉक/पत्तन का प्रकार
अक्षांश	देशांतर	चैनल की लंबाई	न्यूनतम गहराई (मी)	न्यूनतम चौड़ाई (मी)	सं	व्यास (मी)	
18° 56′ 43″ उत्तर	72° 56′ 24″ पूर्व	19.17 नॉटिकल मील	14.4–15.6	450	1	600	सभी मौसम वाला ज्वारीय पत्तन

भारत की आर्थिक राजधानी मुम्बई से निकटता, जेएनपीटी का एक प्रमुख लाभ है। यह रेल और सड़क के एक मज़बूत नेटवर्क से भी जुड़ा है जो देश के प्रमुख शहरों को जोड़ते हैं (चित्र 1)।

चित्र 1: जेएनपीटी मानचित्र निर्देशांक

सड़क संपर्क

जेएनपीटी को आंतरिक भूमि से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों में एनएच4बी, एनएच4, एनएच17, एनएच3, एनएच8 और राजकीय राजमार्ग 54 शामिल हैं

Rail Connectivity

JNPT is linked with the Indian Railways through a lead line connecting the port with its serving station Jasai, which is located on the Panvel–Uran branch line section of the Mumbai Division of Central Railway at a distance of 9 km from the port. The rail system at the port, which is operated and maintained by the Indian Railways, has 13 full-length railway lines serving the four existing container terminals.

Two major initiatives include the Dedicated Freight Corridor (DFC) along the western line from JNPT leading up to Delhi and the Mumbai Trans Harbour Link (MTHL).

Master Plan

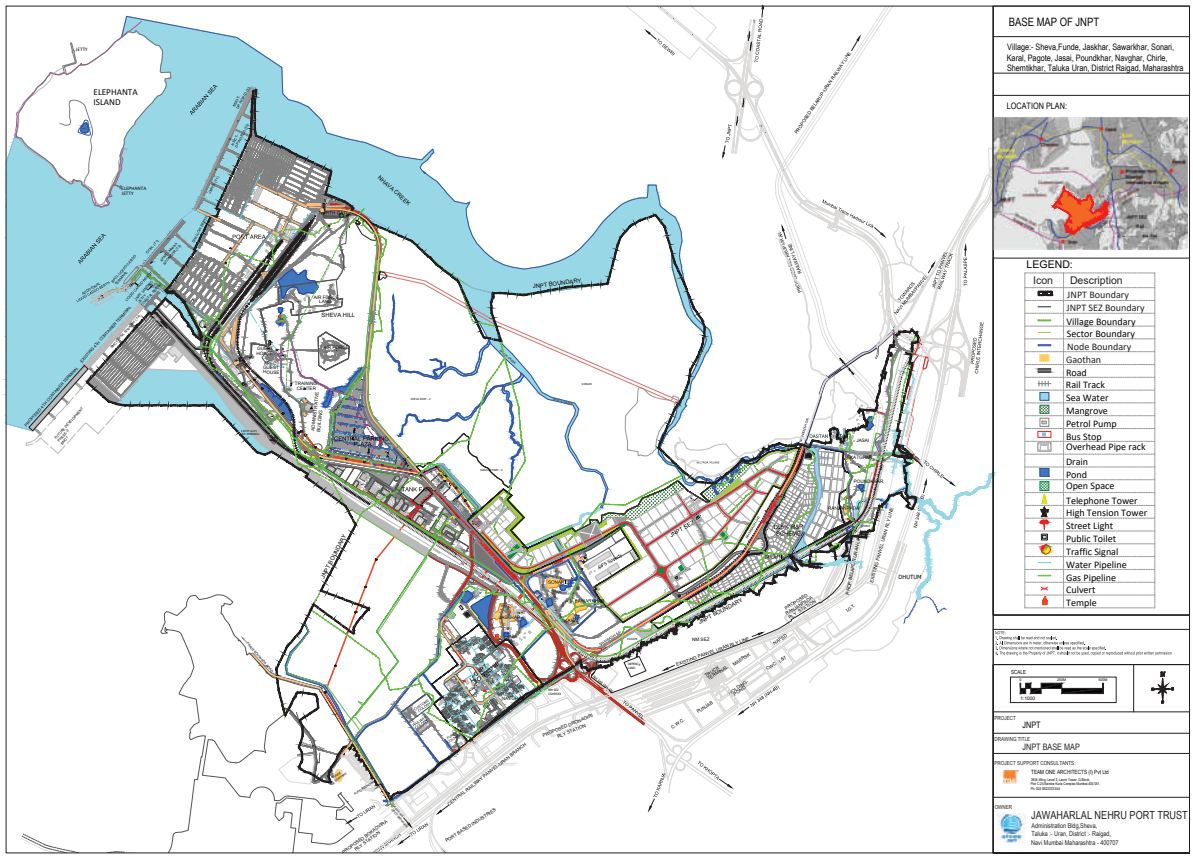

रेल संपर्क सुविधा

जेएनपीटी भारतीय रेलवे से जुड़ा है, जिसकी एक मुख्य लाइन, पत्तन को इसके सेवा वाले स्टेशन जासई से जोड़ती है, जो कि पत्तन से 9 किलोमीटर की दूरी पर मध्य रेलवे के मुम्बई संभाग के पनवेल-उरण ब्रांच लाइन अनुभाग पर स्थित है। पत्तन की रेल व्यवस्था, जिसका प्रचालन और अनुरक्षण भारतीय रेलवे द्वारा किया जाता है, में 13 पूरी लंबाई वाली रेलवे लाइनें हैं जो चार मौजूदा कंटेनर टर्मिनलों को सेवा देती हैं।

पश्चिमी लाइन के अनुदिश, जेएनपीटी से दिल्ली तक जाने वाला समर्पित मालवाही गलियारा (डीएफसी) और मुम्बई ट्रांसहार्बर लिंक (एमटीएचएल) दो प्रमुख कार्यक्रम हैं।

मास्टर प्लान

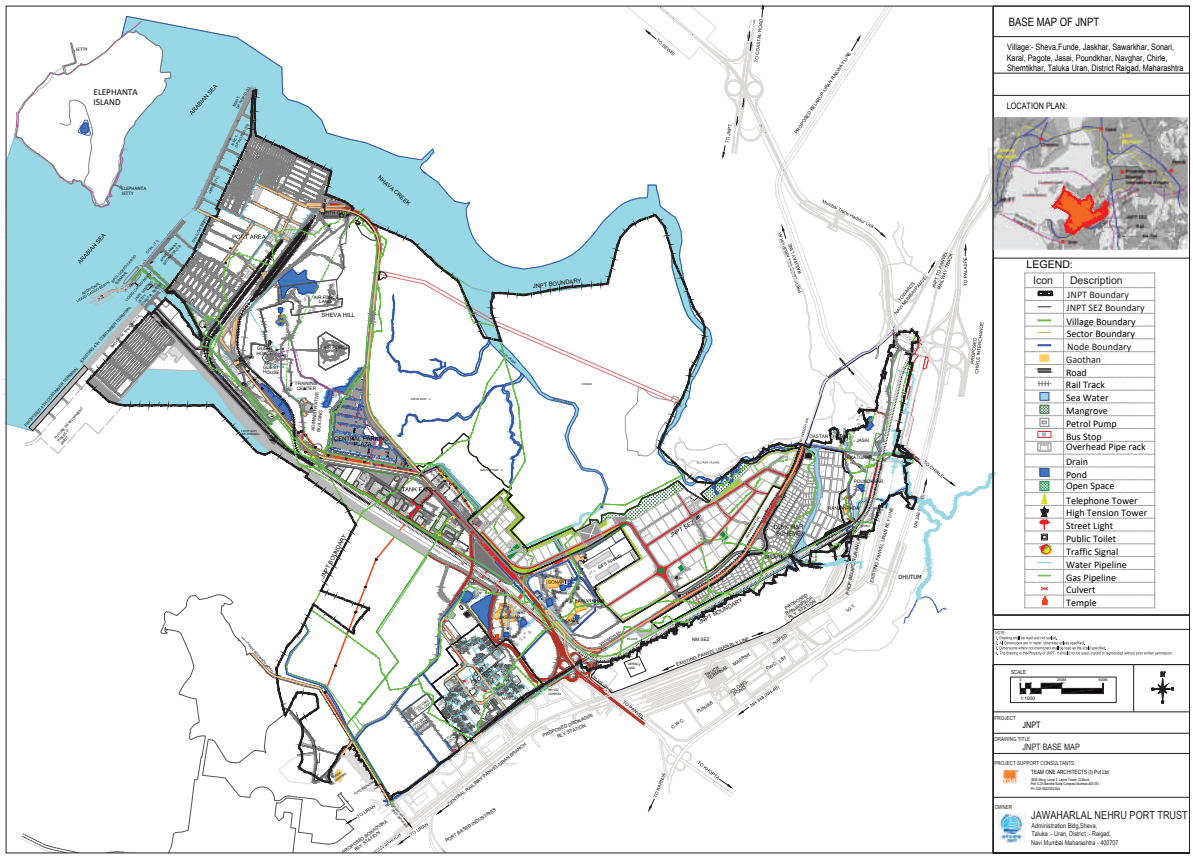

Vision

To become the premier container port of South Asia

Mission

- To be equipped with state-of-the-art technology, efficiency, and manpower which are at par with the international standards;
- To conform to international standards and offer cost-effective integrated logistics solutions;
- Ensure security and safety of life, equipment, and cargo;
- Pursue the principles of eco-friendly sustainable development;
- Constantly upgrade the competence, awareness, skills, and motivation of port personnel for continual improvement in all efficiency parameters.

विज़न

दक्षिण एशिया का प्रीमियर कंटेनर पत्तन बनना

मिशन

- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कार्यदक्षता और कार्मिकशक्ति से सुसज्जित होना, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों;
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना और किफायती एकीकृत लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करना;
- जीवन, उपकरणों और कार्गो की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना;
- पर्यावरण अनुकूल सस्टेनेबल विकास के सिद्धांतों का पालन करना;
- कार्यदक्षता के सभी मापदंडों में सतत सुधार के लिए पत्तन कर्मचारियों की सक्षमता, जागरूकता, कौशल और अभिप्रेरण निरंतर उन्नत बनाना।

JOURNEY OF JNPT

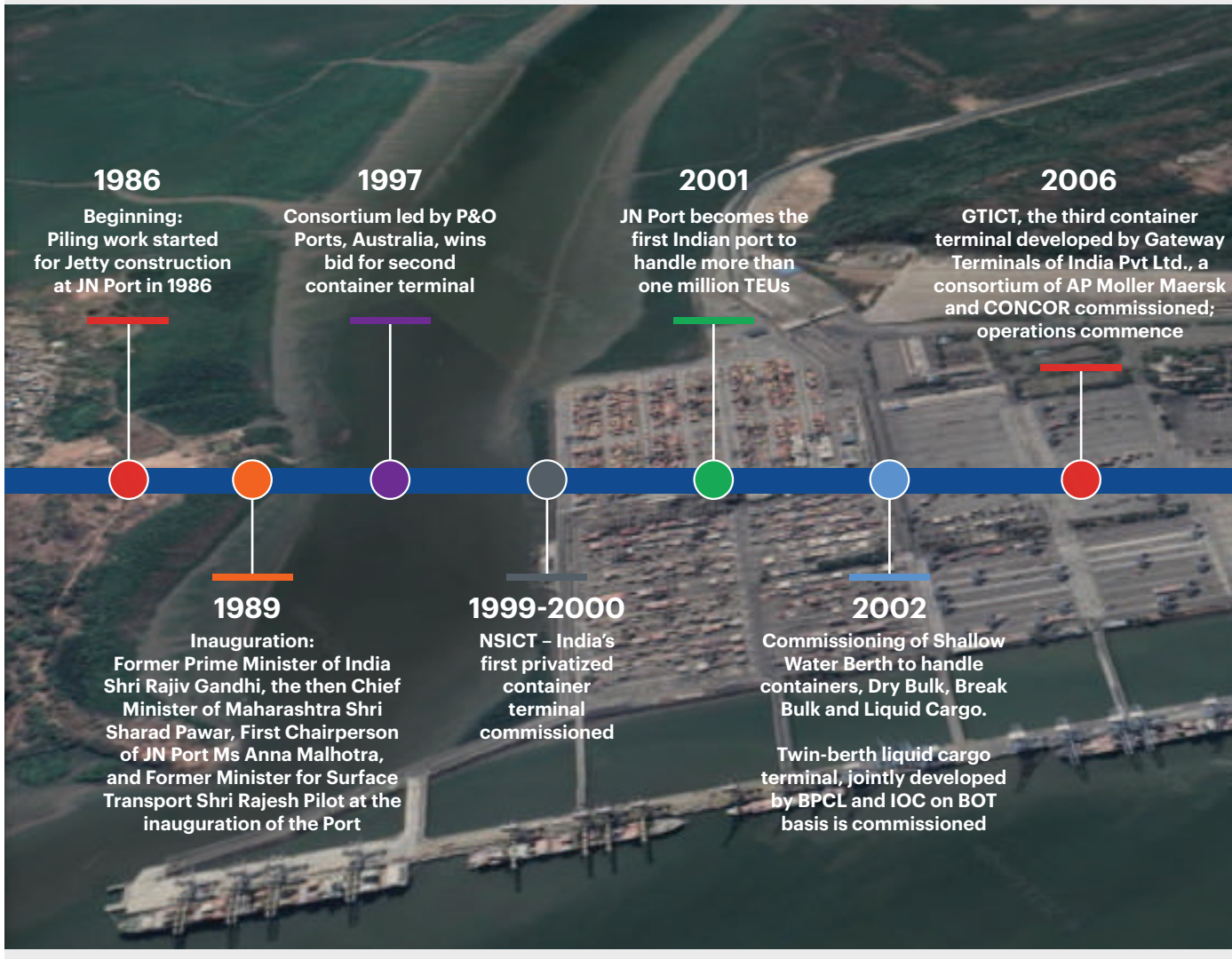

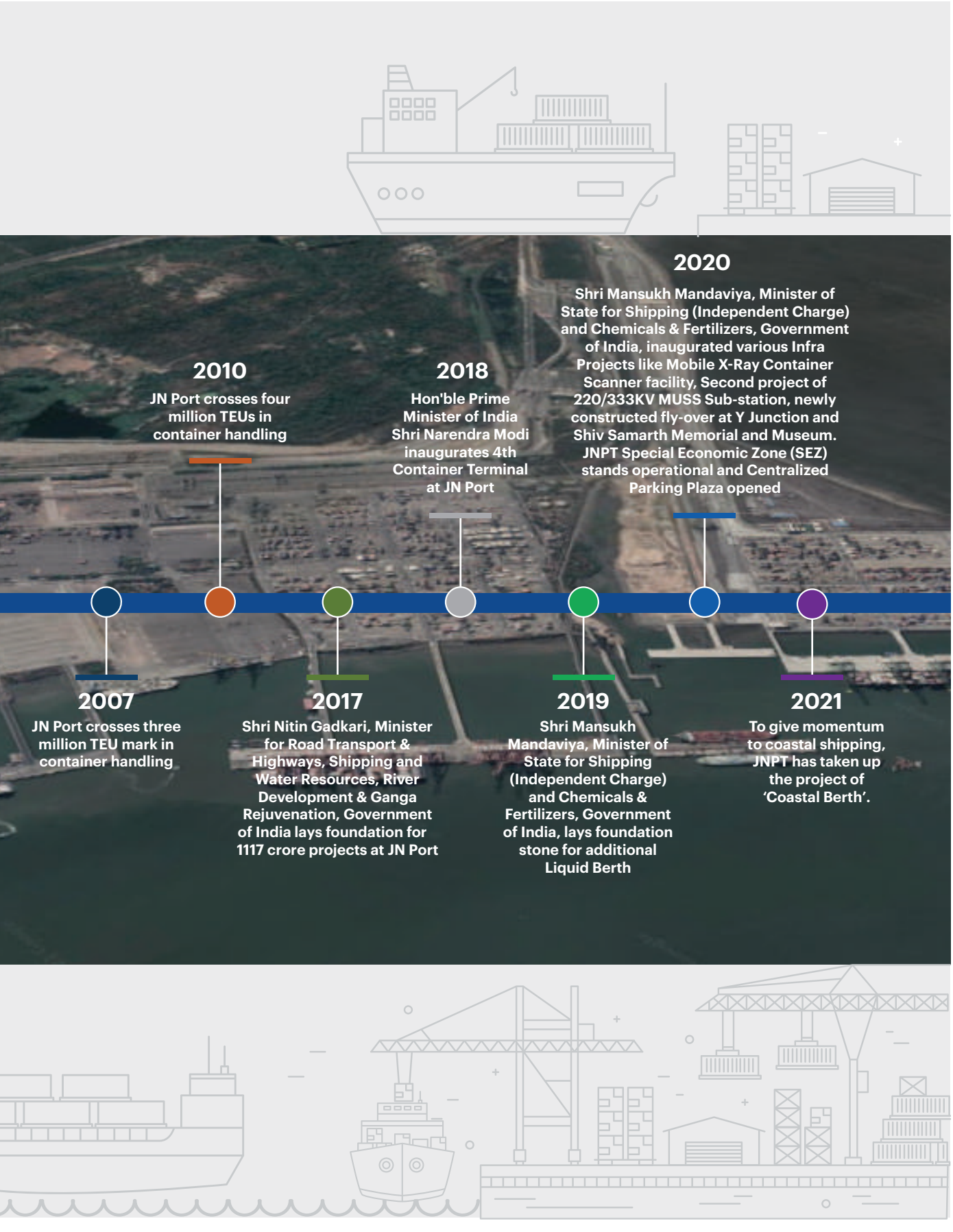
2007
JN Port crosses three million TEU mark in container handling
2010
JN Port crosses four million TEUs in container handling
2017
Shri Nitin Gadkari, Minister for Road Transport & Highways, Shipping and Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Government of India lays foundation for 1117 crore projects at JN Port
2018
Hon'ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi inaugurates 4th Container Terminal at JN Port
2019
Shri Mansukh Mandaviya, Minister of State for Shipping (Independent Charge) and Chemicals & Fertilizers, Government of India, lays foundation stone for additional Liquid Berth
2020
Shri Mansukh Mandaviya, Minister of State for Shipping (Independent Charge) and Chemicals & Fertilizers, Government of India, inaugurated various Infra Projects like Mobile X-Ray Container Scanner facility, Second project of 220/333KV MUSS Sub-station, newly constructed fly-over at Y Junction and Shiv Samarth Memorial and Museum. JNPT Special Economic Zone (SEZ) stands operational and Centralized Parking Plaza opened
2021
To give momentum to coastal shipping, JNPT has taken up the project of 'Coastal Berth'.

जेएनपीटी की यात्रा

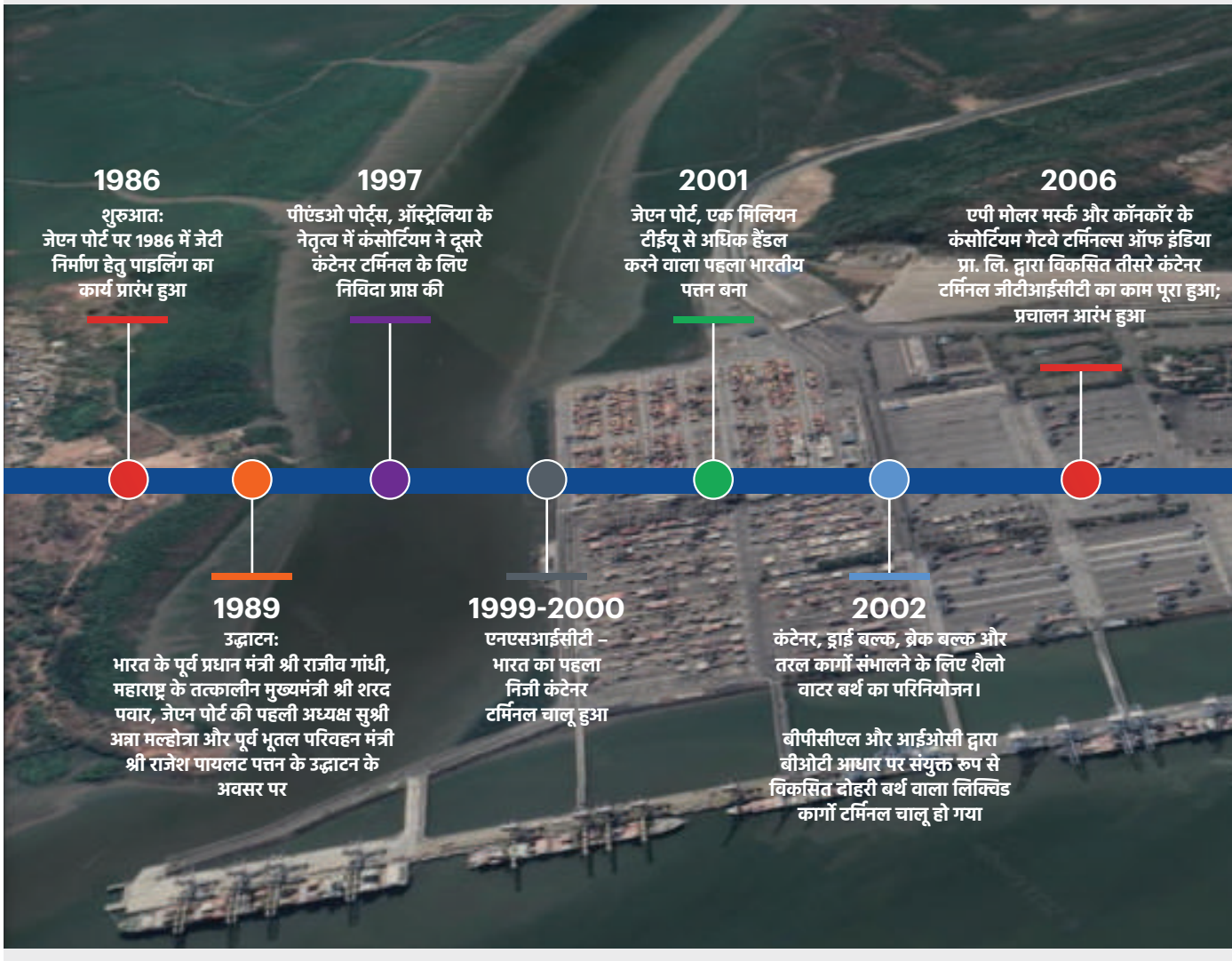
1986
शुरुआत:
जेएन पोर्ट पर 1986 में जेटी निर्माण हेतु पाइलिंग का कार्य प्रारंभ हुआ
1989
उद्घाटन:
भारत के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शरद पवार, जेएन पोर्ट की पहली अध्यक्ष सुश्री अन्ना मल्होत्रा और पूर्व भूतल परिवहन मंत्री श्री राजेश पायलट पत्तन के उद्घाटन के अवसर पर
1997
पीएंडओ पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में कंसोर्टियम ने दूसरे कंटेनर टर्मिनल के लिए निविदा प्राप्त की
1999-2000
एनएसआईसीटी – भारत का पहला निजी कंटेनर टर्मिनल चालू हुआ
2001
जेएन पोर्ट, एक मिलियन टीईयू से अधिक हैंडल करने वाला पहला भारतीय पत्तन बना
2002
कंटेनर, ड्राई बल्क, ब्रेक बल्क और तरल कार्गो संभालने के लिए शैलो वाटर बर्थ का परिनियोजन।
बीपीसीएल और आईओसी द्वारा बीओटी आधार पर संयुक्त रूप से विकसित दोहरी बर्थ वाला लिक्विड कार्गो टर्मिनल चालू हो गया
2006
एपी मोलर मर्स्क और कॉनकॉर के कंसोर्टियम गेटवे टर्मिनल्स ऑफ इंडिया प्रा. लि. द्वारा विकसित तीसरे कंटेनर टर्मिनल जीटीआईसीटी का काम पूरा हुआ; प्रचालन आरंभ हुआ

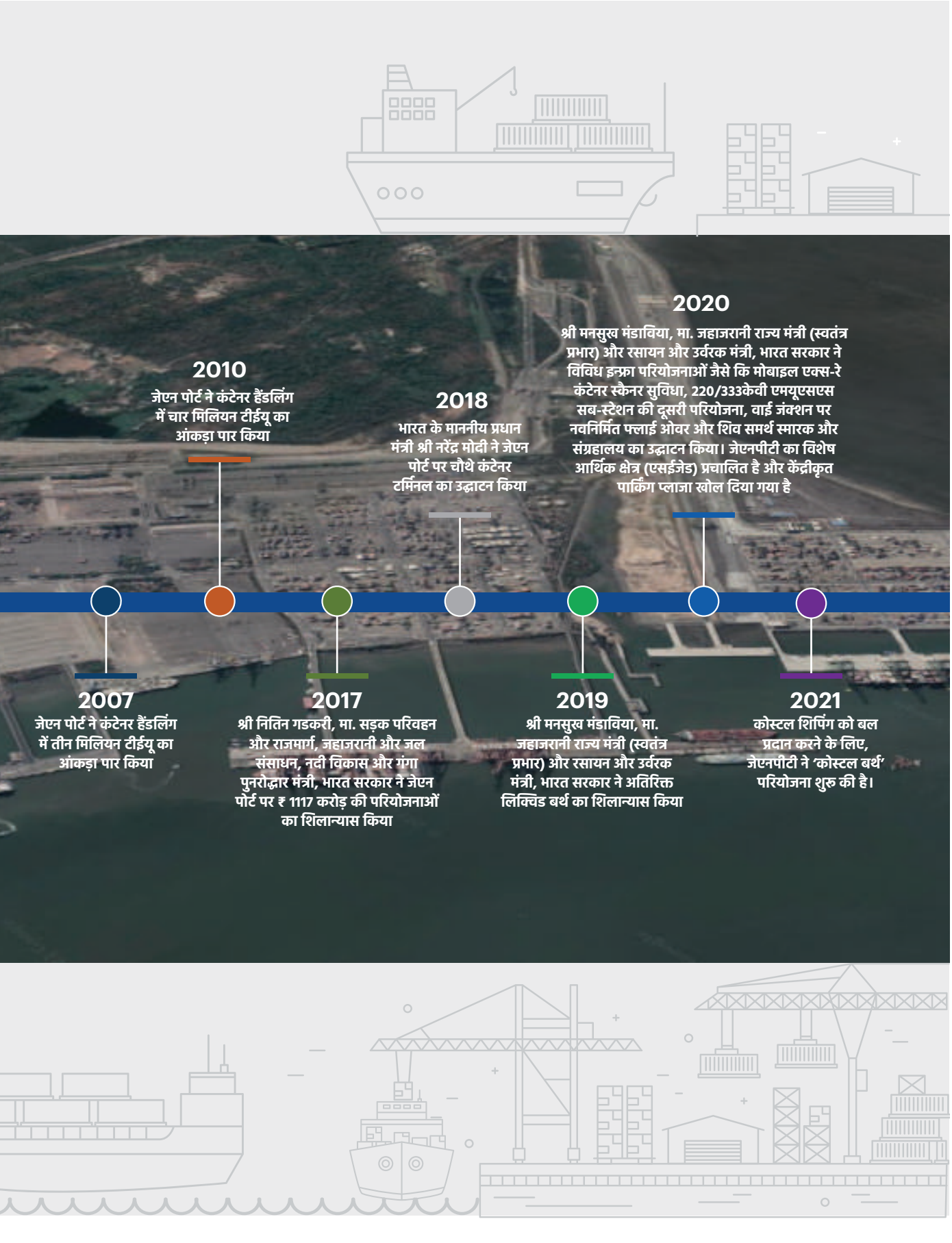

2007
जेएन पोर्ट ने कंटेनर हैंडलिंग में तीन मिलियन टीईयू का आंकड़ा पार किया

2010
जेएन पोर्ट ने कंटेनर हैंडलिंग में चार मिलियन टीईयू का आंकड़ा पार किया

2017
श्री नितिन गडकरी, मा. सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरोद्धार मंत्री, भारत सरकार ने जेएन पोर्ट पर ₹ 1117 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया

2018
भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जेएन पोर्ट पर चौथे कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया

2019
श्री मनसुख मंडाविया, मा. जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार ने अतिरिक्त लिक्विड बर्थ का शिलान्यास किया

2020
श्री मनसुख मंडाविया, मा. जहाजरानी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार ने विविध इन्फ्रा परियोजनाओं जैसे कि मोबाइल एक्स-रे कंटेनर स्कैनर सुविधा, 220/33केवी एमयूएसएस सब-स्टेशन की दूसरी परियोजना, वाई जंक्शन पर नवनिर्मित फ्लाई ओवर और शिव समर्थ स्मारक और संग्रहालय का उद्घाटन किया। जेएनपीटी का विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) प्रचालित है और केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा खोल दिया गया है

2021
कोस्टल शिपिंग को बल प्रदान करने के लिए, जेएनपीटी ने 'कोस्टल बर्थ' परियोजना शुरू की है।

List of Awards and Recognitions for JNPT

t

2020

JNPT Awarded as the "Best Global Port in India" at the prestigious 6th Atal Shastra Markenomy Award 2020

2019

JNPT Awarded as 3rd Cleanest and Greenest Port of the Under Swaachh Bharat Abhiyan Initiative by Ministry of shipping

2018

JNPT Awarded with the 'Best Port of the Year (Containerized)' at India Maritime Award.

JNPT Wins 'Container Handling Port of the Year' and 'Port Personality of the Year' at Maritime and Logistics Award Organized by Exim India

JNPT wins the "Best container Terminal por Award" & "Indian Maritime Personality of the Year" at the Gateway Awards 2018

जेएनपीटी को प्राप्त पुरस्कारों और सम्मानों की सूची

2020

प्रतिष्ठित छठे अटल शास्त्र मार्केनॉमी अवार्ड 2020 में जेएनपीटी को "भारत में सर्वश्रेष्ठ वैश्विक पत्तन" के रूप में सम्मानित किया गया

2019

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत जेएनपीटी को तीसरे सबसे स्वच्छ और सबसे हरे-भरे पत्तन के रूप में पुरस्कृत किया गया

2018

इंडिया मैरीटाइम अवार्ड में जेएनपीटी को 'वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्तन (कंटेनराइज्ड)' के रूप में पुरस्कृत किया गया।

एक्ज़िम इंडिया द्वारा आयोजित मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स अवार्ड में जेएनपीटी ने 'कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट ऑफ दि ईयर' और 'पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ दि ईयर' का सम्मान जीता

गेटवे अवाइर्स 2018 में जेएनपीटी ने "बेस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट अवार्ड" और "इंडियन मैरीटाइम पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर" प्राप्त किया

Corporate Governance

The Major Port Authorities Bill, 2020 supersedes the Major Port Trusts Act, 1963 and has been put into effect from September 2020. The Bill aims to provide greater autonomy and flexibility to the major ports in India and professionalize their governance. Subsequently, the Central Government has been directed to constitute the Board of Major Port Authority after which the Board of Trustees shall cease to exist.

JNPT fulfils its fiduciary duty as depicted in the hierarchical governance model shown in Figure 2. The Board of Trustees, as constituted under the Major Port Trusts Act, 1963, serves as the decision-making authority for all operational and administrative activities. The Board of Management oversees the overall planning and maintenance of existing and upcoming infrastructure, marine security, ecological balance, integrity, and transparency in operations along with addressing public grievances, maintaining industrial relations, employee welfare and training, and reports on regular frequency to the Board of Trustees for their vision and guidance. The Board of Trustees is accountable to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for achieving higher standards of governance and efficiency in operations.

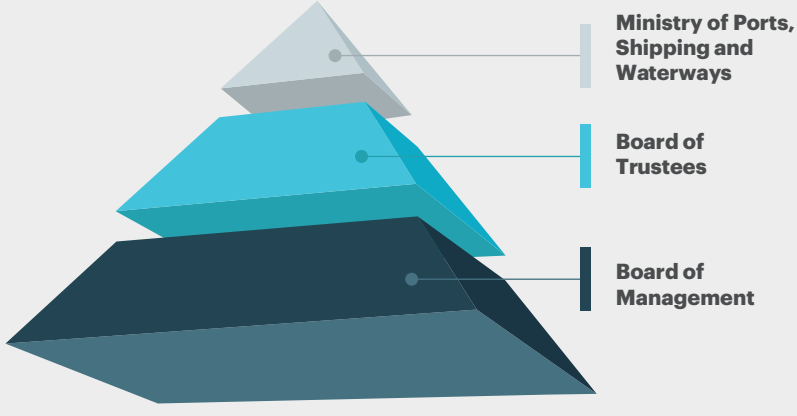

Figure 2: JNPT governance hierarchy

GRI 102-5 | GRI 102-16 | GRI 102-18 | GRI 102-20

कॉर्पोरेट अभिशासन

महा पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 को अध्यारोपित किया और सितम्बर 2020 से प्रभावी हुआ। भारत में महा पत्तनों को अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्रदान करना और उनके अभिशासन को पेशेवर रूप प्रदान करना इस विधेयक का उद्देश्य है। बाद में, केंद्र सरकार ने महा पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के गठन का निर्देश दिया जिसके बाद न्यासी मंडल को भंग कर दिया जाएगा।

जेएनपीटी अपने न्यासीय कर्तव्य पूर्ण करता है जैसा चित्र 2 में पदानुक्रमिक अभिशासन मॉडल में दिखाए गया है। महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित न्यासी मंडल, समस्त प्रचालन संबंधी और प्रशासकीय गतिविधियों के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है। प्रबंधन बोर्ड, मौजूदा और भावी अवसंरचना, सामुद्रिक सुरक्षा, पारिस्थितिक संतुलन, प्रचालनों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता का का समग्र नियोजन और रखरखाव करता है और सार्वजनिक शिकायतों का समाधान करता है, औद्योगिक संबंधों, कर्मचारी कल्याण और प्रशिक्षण का रखरखाव करता है और न्यासी मंडल के विज़न और मार्गदर्शन के लिए नियमित रूप से रिपोर्ट करता है। न्यासी मंडल, अभिशासन के उच्चतर मानकों और प्रचालनों में दक्षता के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रति जवाबदेह है।

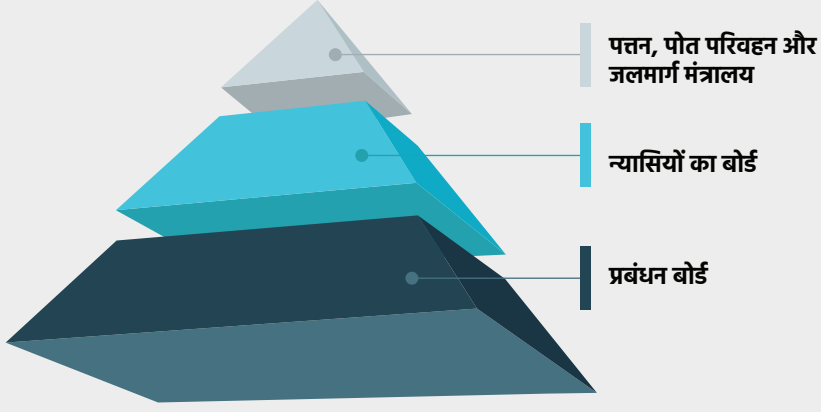

चित्र 2: जेएनपीटी का अभिशासन

BOARD OF TRUSTEES

SHRI SANJAY SETHI, IAS Chairman Jawaharlal Nehru Port Trust	**SHRI UNMESH SHARAD WAGH, IRS** Deputy Chairman Jawaharlal Nehru Port Trust	**SHRI SANJAY KUMAR, IAS** As and FA, Ministry of Shipping, Govt of India
SHRI V. N. AMBADE, IFS Deputy Director of Forest (C), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt of India	**SHRI AMITABH KUMAR, IRS** DG Shipping Mercantile Marine Department, Govt of India	**SHRI RAJIV TALWAR, IRS** Principal Chief Commissioner, Jawaharlal Nehru Custom House, Ministry of Revenue
DR SANJAY MUKHERJEE, IAS VC and MD, CIDCO, Govt of Maharashtra	**CMDE SHRI SANJAY SACHDEVA** Naval Officer-in-Charge (Mah), Indian Navy, Defence Services	**DIG SHRI KALPIT DIKSHIT, TM** Chief of Staff, Coast Guard Region (West), Indian Coast Guard
SHRI K. N. SINGH CFTM (CR), Indian Railways	**SHRI DINESH K. PATIL** President, JNPT Kamagar Ekta Sanghatna, Labour Representative	**SHRI BHUSHAN N. PATIL** General Secretary, Nhava Sheva Bandar Kamagar Sanghatna (A), Labour Representative

BOARD OF MANAGEMENT

SHRI SANJAY SETHI, IAS
Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust

SHRI UNMESH SHARAD WAGH, IRS
Deputy Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust

SHRI VIDYADHAR A. MALEGAONKAR, IRTS
Chief Vigilance Officer

SHRI RAJAN GURAV
Chief Manager (Traffic)

SHRI JAIWANT DHAWALE
Chief Manager, Admin. Secretary

SHRI G. VAIDYANATHAN
Chief Manager, Port Planning Development Department

CAPT. SUNIL NISHITH
Deputy Conservator, In-Charge / Harbour Master

SHRI NITEEN M. BORWANKAR
Chief Manager, Mechanical & Electrical Engineering

न्यासी मंडल

श्री संजय सेठी, आईएएस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट	**श्री उन्मेष शरद वाघ, आईआरएस** उपाअध्यक्ष जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट	**श्री संजय कुमार, आईएएस** एएस और एफए, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार
श्री वी.एन. अम्बाडे, आईएफएस उप निदेशक, वन (सी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	**श्री अमिताभ कुमार, आईआरएस** महानिदेशक (डीजी) व्यापारिक समुद्री विभाग, भारत सरकार	**श्री राजीव तलवार, आईआरएस** प्रधान मुख्य आयुक्त, जवाहरलाल नेहरु सीमा शुल्क, राजस्व मंत्रालय
डॉ. संजय मुखर्जी, आईएएस वीसी और एमडी, सिडको, महाराष्ट्र सरकार	**सीएमडीई श्री संजय सचदेव** नेवल ऑफिसर इंचार्ज (एमएएच), भारतीय नौसेना, प्रतिरक्षा सेवाएं	**डीआईजी श्री कल्पित दीक्षित, टीएम** चीफ ऑफ स्टाफ (पश्चिम), भारतीय तटरक्षक दल
श्री के.एन. सिंह सीएफटीएम (सीआर), भारतीय रेलवे	**श्री दिनेश के. पाटिल** अध्यक्ष, जेएनपीटी कामगार एकता संगठन, श्रमिक प्रतिनिधि	**श्री भूषण एन. पाटिल** महासचिव, न्हावा शेवा बंदर कामगार संगठन (ए), श्रमिक प्रतिनिधि

प्रबंधन बोर्ड

श्री संजय सेठी, आईएएस
अध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट

श्री उन्मेष शरद वाघ, आईआरएस
उपाअध्यक्ष, जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट

श्री विद्याधर ए मालेगांवकर, आईआरटीएस
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री राजन गुरव
मुख्य प्रबंधक (यातायात)

श्री जयवंत ढवले
मुख्य प्रबंधक, (प्रशासन) एंव सचिव

श्री जी. वैद्यनाथन
मुख्य प्रबंधक, पत्तन योजना एंव विकास विभाग

कैप्टन सुनील निशीथ
प्रभारी उप संरक्षक / हार्बर मास्टर

श्री नितीन एम. बोरवणकर
मुख्य प्रबंधक, यांत्रिक एंव वीधुत अभियांत्रिकी

Sustainability at JNPT

The commitment to sustainable development by Jawaharlal Nehru Port is exhibited through the various initiatives and measures undertaken to maintain ecological balance. JNPT derives its sustainability approach from its logo, which signifies the importance of modern and efficient ports and international trade, contributing to the principles of Blue Economy and Maritime India Vision 2030.

Sustainability Organogram

JNPT's Environment Division is led by Shri G. Vaidyanathan, Chief Manager (Port Planning Development Department), who oversees the mitigation and adaptation measures. These include afforestation activities, compliances related to the environment for new and existing infrastructure, and other actions undertaken to achieve the "Green Port Status".

The structure of the Environment Division is presented in Figure 3. JNPT also constitutes a team of nodal officers – for environment management and monitoring plan – which oversees the implementation of activities at the level of operations across departments on a regular basis.

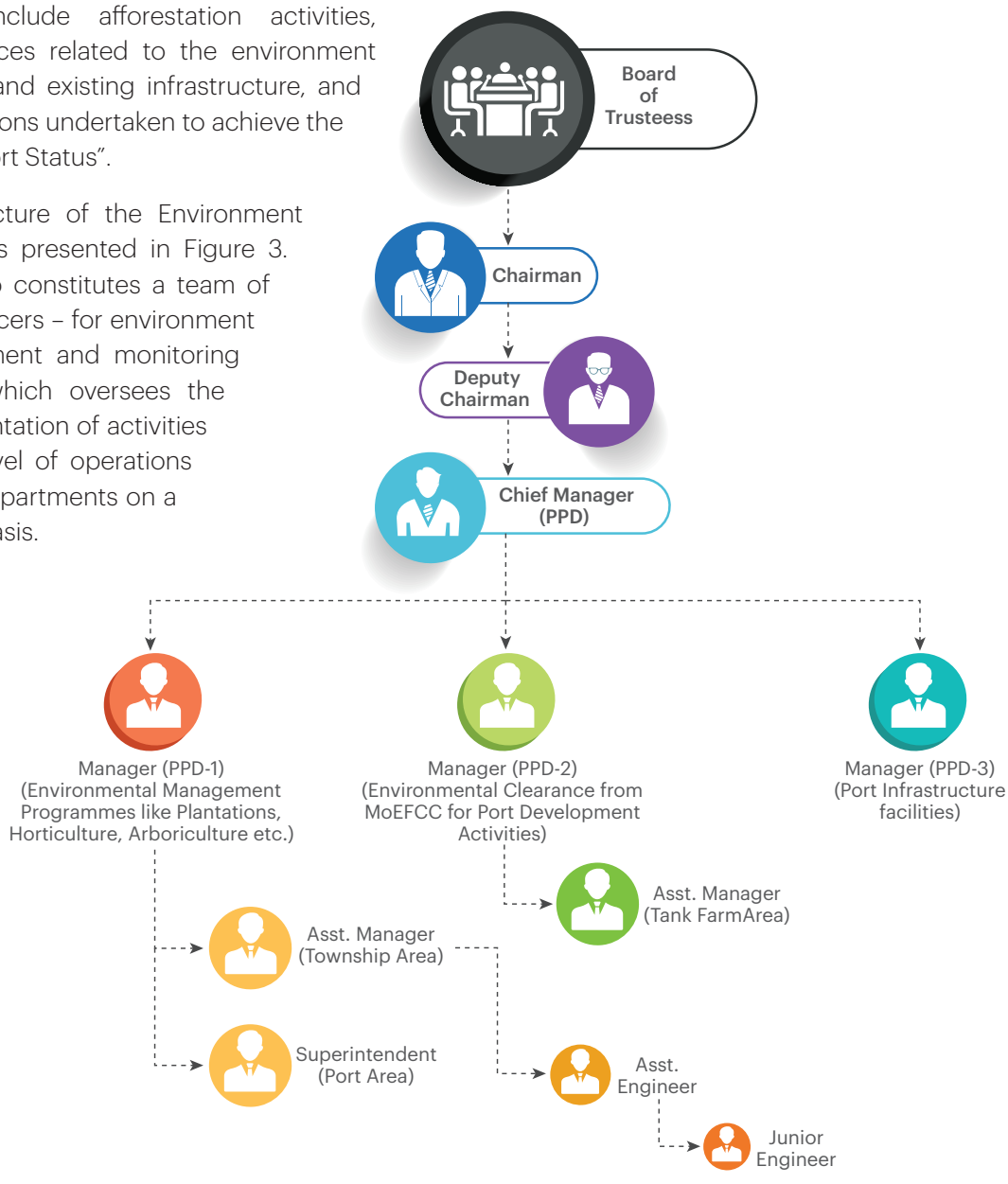

Figure 3: Structure of JNPT's Environmental Division

जेएनपीटी में सस्टेनेबिलिटी

सस्टेनेबल विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन की प्रतिबद्धता, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपनाए गए विविध प्रयासों और उपायों के माध्यम से प्रदर्शित होती है। जेएनपीटी का सस्टेनेबिलिटी का तरीका, इसके लोगो से जुड़ा है, जो आधुनिक और कार्यक्षम पत्तनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्त्व को रेखांकित करते हुए ब्लू इकोनॉमी और मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 के सिद्धांतों में योगदान करता है।

सस्टेनेबिलिटी का संगठनात्मक चार्ट

जेएनपीटी के पर्यावरण प्रभाग का नेतृत्व श्री जी. वैद्यनाथन, मुख्य प्रबंधक (पत्तन योजना एंव विकास विभाग), द्वारा किया जाता है जो न्यूनीकरण और अनुकूलन के उपायों का पर्यवेक्षण करते हैं। इसमें पुनर्वनीकरण गतिविधियां, नई और मौजूदा अवसंरचना के लिए पर्यावरण संबंधी अनुपालन और "ग्रीन पोर्ट स्टेट्स" हासिल करने के लिए की जाने वाली अन्य कार्यवाहियां शामिल हैं।

पर्यावरण प्रभाग की संरचना को चित्र 3 में दिखाया गया है। जेएनपीटी ने पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना के लिए नोडल अधिकारियों की एक टीम भी गठित की है जो नियमित रुप से सभी विभागों में सभी प्रचालन स्तरों पर क्रियान्वयन गतिविधियों की निगरानी करती है।

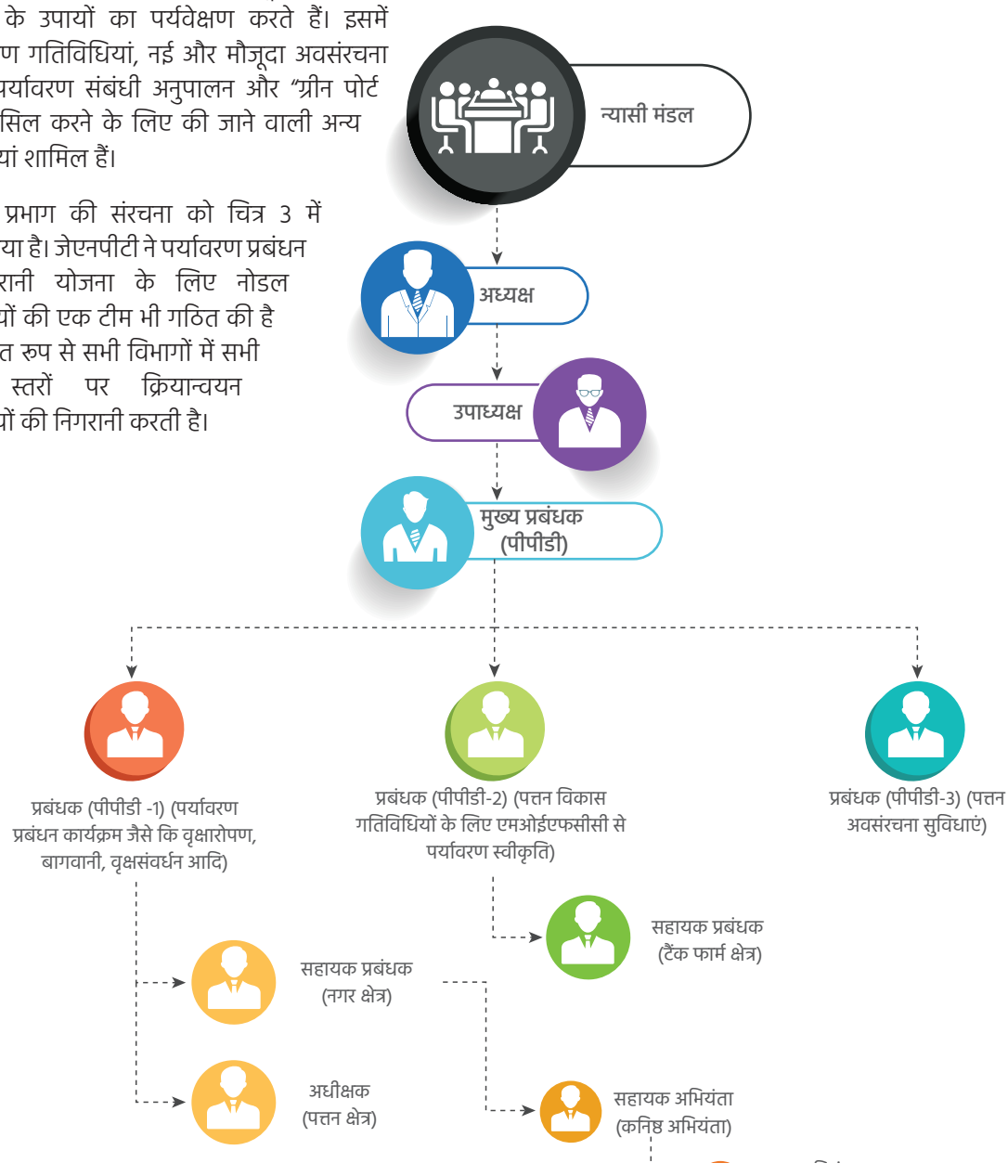

चित्र 3: जेएनपीटी के पर्यावरणीय प्रभाग की संरचना

JNPT constituted a multidisciplinary, functional Sustainability Core Group for articulating and reviewing its sustainability performance. The Core Group includes representatives from various functional departments. It works in collaboration with pertinent internal and external stakeholders.

Sustainability Core Group

Shri Vishwanath Gharat Manager (PP&D)	**Shri A. T. Chopade** Manager (EM) I/c	**Ms N. S. Latha** Dy. Manager (Traffic)
Dr Sachin Markad Labour Welfare Officer	**Shri K. D. Vasudevan** Dy. Manager (PEM)	**Shri J. P. Raval** Dy. Manager (Safety)
Dr Ramanand N. Jadhav Manager (Environment)		

Stakeholder Engagement

A bottom-up approach is followed where the strategic intent of different stakeholder categories is taken into account in addition to the strategic intent of the Port. Figure 4 gives a schematic representation of priority mapping of the influence and interests of the identified stakeholders.

In order to create value in the short and long term, and understand the potential impacts – both positive and negative – it is critical to recognize the key stakeholders in the organization and respectively map their concerns to the organization strategy and operations. The stakeholder engagement exercise has guided JNPT in systematic adoption of the understanding of expectations and interests of diverse stakeholders' groups. Further, it aided in preparing a stakeholder engagement framework, where existing activities merge with a set of planned activities for strengthening its engagement and communication with stakeholders.

The first step in identifying the key stakeholders was to draw a potential list of stakeholders, which are being engaged either directly or indirectly. On the basis of their significance and relevance to the Port's planning and management, the key stakeholders are identified in consultation with JNPT's core team and further prioritized to be engaged in future consultations.

अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस निर्धारित करने और इसकी समीक्षा करने के लिए जेएनपीटी ने एक बहुवैषयिक, प्रकार्यात्मक सस्टेनेबिलिटी कोर ग्रुप का गठन किया है। इस कोर ग्रुप में विविध प्रकार्यात्मक विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं। यह संबंधित आंतरिक और बाहरी हितधारकों के सहयोग से काम करता है।

सस्टेनेबिलिटी कोर ग्रुप

श्री विश्वनाथ घरत प्रबंधक (पीपीएंडडी)	**श्री ए.टी. चौपड़े** प्रबंधक (ईएम) आई/सी	**सुश्री एन.एस. लता** उप प्रबंधक (यातायात)
डॉ. सचिन मर्कड श्रम कल्याण अधिकारी	**श्री के.डी वासुदेवन** उप प्रबंधक (पीईएम)	**श्री जे.पी. रावल** उप प्रबंधक (सुरक्षा)
डॉ. रामानंद एन. जाधव प्रबंधक (पर्यावरण)		

हितधारक सहभागिता

एक ऊर्ध्वगामी दृष्टिकोण का पालन किया जाता है जहां पत्तन के कार्यनीतिक अभिप्राय के अलावा विभिन्न श्रेणियों के हितधारकों के कार्यनीतिक अभिप्राय को ध्यान में रखा जाता है।
चित्र 4 में, चिन्हित हितधारकों के प्रभाव और हितों के प्राथमिकता मापन का एक योजनाबद्ध निरुपण दिया गया है।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य सृजन करने और सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के संभावित प्रभावों को समझने के लिए संगठन में प्रमुख हितधारकों की पहचान करना और संगठन की रणनीति और प्रचालनों में उनकी चिंताओं का उपयुक्त रूप से मापन करना महत्त्वपूर्ण है। हितधारक सहभागिता अभ्यास ने जेएनपीटी को विविध हितधारक समूहों की अपेक्षाओं और हितों की समझ को व्यवस्थित रूप से अंगीकृत करने के लिए मार्गदर्शित किया है। इसके अलावा, इससे हितधारक सहभागिता के लिए रूपरेखा बनाने में मदद मिली है जहां हितधारकों से सहभागिता और संवाद सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा गतिविधियां, नियोजित गतिविधियों के एक समूह में मिलती हैं।

प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संलग्न हितधारकों की एक संभावित सूची तैयार करना, प्रमुख हितधारकों की पहचान करने का पहला कदम है। पत्तन के नियोजन और प्रबंधन में उनके महत्त्व और प्रासंगिकता के आधार पर प्रमुख हितधारकों को जेएनपीटी की कोर टीम से परामर्श के आधार पर चिन्हित किया गया है और भावी परामर्शों में संलग्न किए जाने हेतु प्राथमिकता निर्धारण किया गया है।

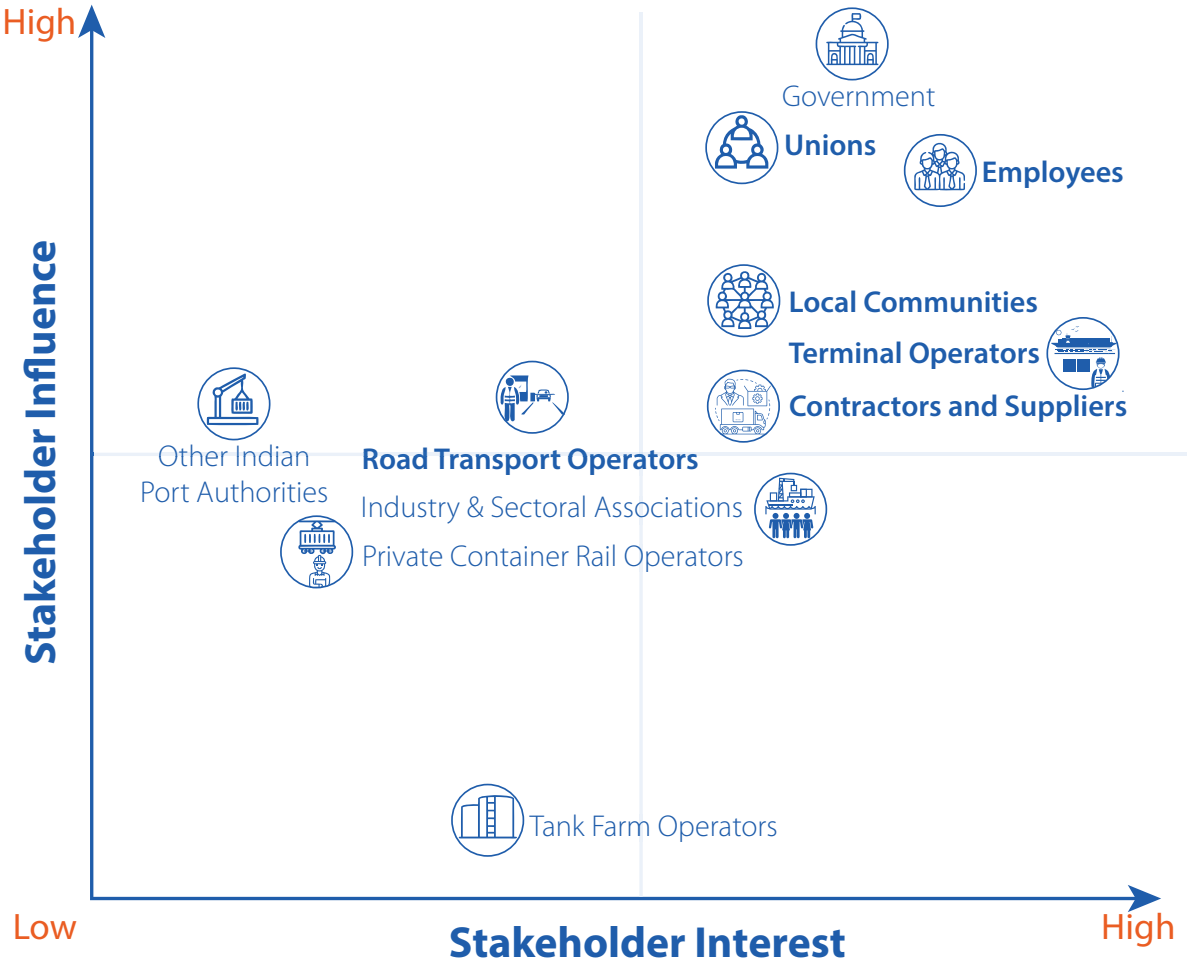

Figure 4: Prioritization of key stakeholders

JNPT engages with a diverse set of stakeholders ranging from central and state authorities, employees, suppliers, local communities, and so on. Table 2 shows the stakeholder engagement matrix of the key stakeholders as identified during the reporting period.

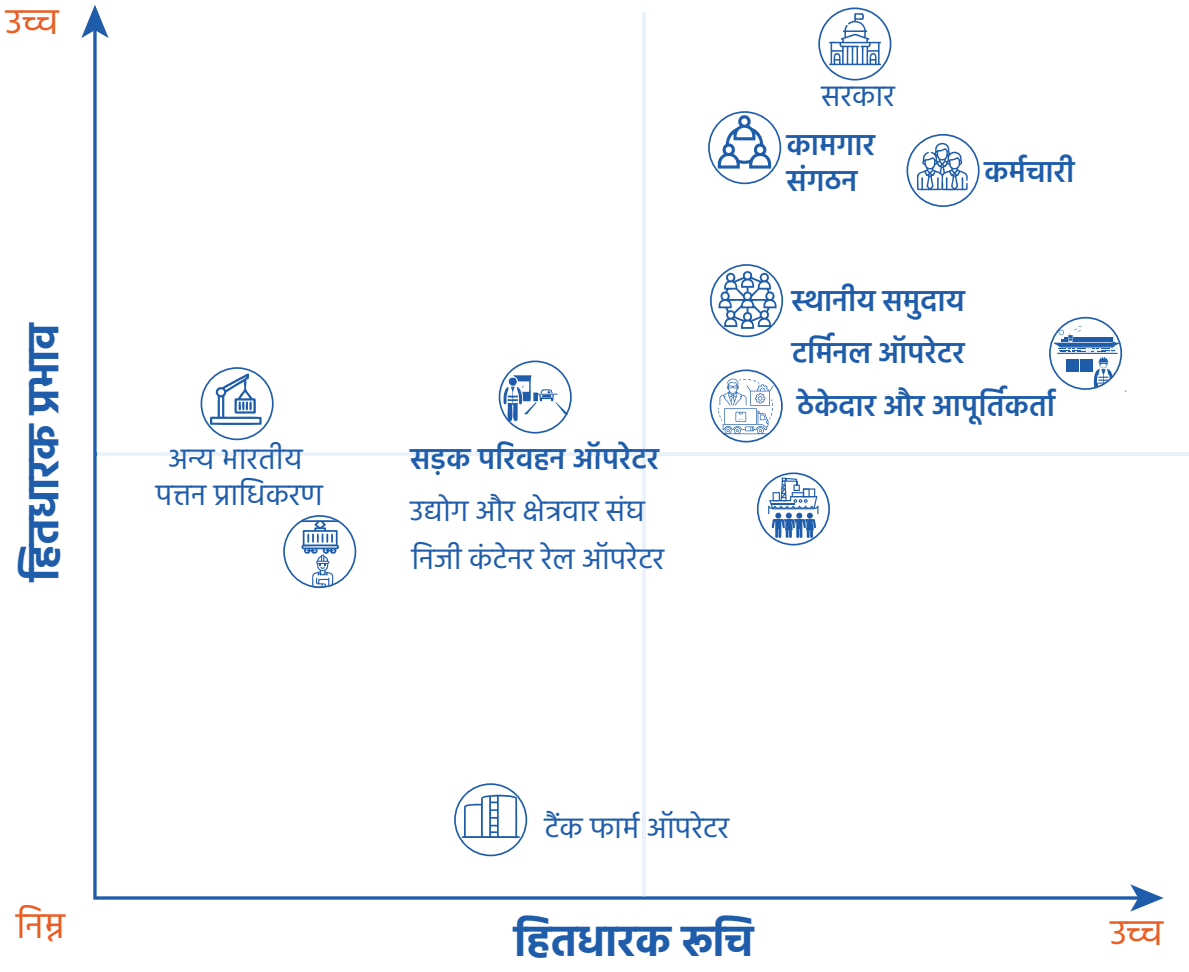

चित्र 4: प्रमुख हितधारकों का प्राथमिकता निर्धारण

जेएनपीटी, हितधारकों के एक विविधतापूर्ण समूह के साथ संलग्न है, जिसमें केंद्र और राज्य के प्राधिकारी, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय समुदाय व अन्य सम्मिलित हैं। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान चिन्हित प्रमुख हितधारकों की हितधारक सहभागिता सारणी को तालिका 2 में दिखाया गया है।

Table 2: Stakeholder Engagement Matrix

	Terminal Operators	Employees	Contractors and Suppliers	Unions	Road transport Operators	Local Communities
Mode of Engagement						
	• Online/ Offline trainings • JNPT website • Sustainability Newsletters	• Trainings • Reports, JNPT Website • Sustainability Newsletters	• In-person Interaction • JNPT Website • Sustainability Newsletters	• In-person Interaction	• In-person Interaction	• In-person Interactions • CSR Initiatives • Sustainability Newsletter
Frequency of Engagement						
	• Periodic • Monthly • Quarterly	• Continuous • Monthly • Annually • Quarterly	• Periodic • Quarterly	• Regular • Quarterly	• Regular • Quarterly	• Periodic • Quarterly
Vehicles for Engagement						
	• Regular business activities • Compliance – (e.g., monthly report on environmental monitoring) • Strengthening safety management system • Strengthening waste management system • Awareness of ESG issues	• Grievance redressal • Talent development • Business performance reviews • Organization's communication • Awareness of ESG issues	• Supplier/ Vendor conferences • Supplier audits • Awareness of ESG issues	• Grievance redressal • Compliance • Welfare	• Regular business activities	• Community issues • Awareness of ESG issues

The adoption of a systematic stakeholder engagement process guides JNPT to identify additional relevant material issues and improve its accountability to a range of stakeholders. It specifically articulates the vehicles of engagement and appropriate frequency at which the engagements are carried out.

The stakeholder engagement is an ongoing process and JNPT shall revisit the stakeholder identification process at an appropriate frequency.

तालिका 2: हितधारक सहभागिता सारणी

	टर्मिनल ऑपरेटर	कर्मचारी	ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता	कामगार संगठन	सड़क परिवहन ऑपरेटर	स्थानीय समुदाय
सहभागिता का प्रकार	• ऑनलाइन/ऑनलाइन प्रशिक्षण • जेएनपीटी की वेबसाइट • सस्टेनेबिलिटी न्यूज़लेटर्स	• प्रशिक्षण • रिपोर्टें, जेएनपीटी की वेबसाइट • सस्टेनेबिलिटी न्यूज़लेटर्स	• व्यक्तिगत संवाद • जेएनपीटी की वेबसाइट • सस्टेनेबिलिटी न्यूज़लेटर्स	• व्यक्तिगत संवाद	• व्यक्तिगत संवाद	• व्यक्तिगत संवाद • सीएसआर कार्यक्रम • सस्टेनेबिलिटी न्यूज़लेटर
सहभागिता की आवृत्ति	• आवधिक • मासिक • त्रैमासिक	• अनवरत • मासिक • वार्षिक • त्रैमासिक	• आवधिक • त्रैमासिक	• नियमित • त्रैमासिक	• नियमित • त्रैमासिक	• आवधिक • त्रैमासिक
सहभागिता हेतु माध्यम	• नियमित व्यावसायिक गतिविधियाँ • अनुपालना (उदाहरण के लिए, पर्यावरण निगरानी पर मासिक रिपोर्ट) • संरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना • अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाना • ईएसजी मुद्दों के बारे में जागरुकता	• शिकायत निवारण • प्रतिभा विकास • व्यवसाय कार्यप्रदर्शन समीक्षाएं • संगठन का संवाद • ईएसजी मुद्दों के बारे में जागरुकता	• आपूर्तिकर्ता/विक्रेता सम्मेलन • आपूर्तिकर्ताओं का लेखापरीक्षण • ईएसजी मुद्दों के बारे में जागरुकता	• शिकायत निवारण • अनुपालना • कल्याण	• नियमित व्यावसायिक गतिविधियाँ	• सामुदायिक मुद्दे • ईएसजी मुद्दों के बारे में जागरुकता

एक व्यवस्थित हितधारक सहभागिता प्रक्रिया को अपनाना, अतिरिक्त प्रासंगिक मुद्दों की पहचान करने और विविध प्रकार के हितधारकों के लिए जेएनपीटी की जवाबदेही में सुधार करने के लिए इसका मार्गदर्शन करता है। यह विशेषरूप से सहभागिता के साधनों और सहभागिता किए जाने की उपयुक्त आवृत्ति निर्धारित करता है।

हितधारक सहभागिता एक निरंतर प्रक्रिया है और जेएनपीटी उपयुक्त आवृत्ति पर हितधारक चिन्हांकन प्रक्रिया का पुनरीक्षण करेगा।

Materiality Evaluation

The material topics/issues reflect on JNPT's impact boundary embedding the entire spectrum of economic, environment, social, and governance issues with the intent to minimize the conflicts arising due to expansion or upgradation of the existing infrastructure. These material topics/issues would also be a premise for the JNPT management to prioritize its efforts and budgets in keeping with the initiatives to achieve the "Green Port status".

JNPT has adopted the methodology, as shown in Figure 5, for materiality evaluation and identified the material issues, as shown in Figure 6, for its first sustainability report.

Step 1 Identification

Identified relevant material topics through internal and external screening (benchmarking of peer sustainability reports, globally accepted ESG frameworks (SASB, etc.) and media analysis).

Step 2 Prioritization

JNPT Core Team reviewed the comprehensive set of material issues. A total of 27 topics were deemed as material in the priortization stage.

Step 3 Engagement

Engaging with prioritized internal and external stakeholders relevant to business for soliciting their inputs and rankings on 27 material issues.

Step 4 Materiality Evaluation

A set of 15 topics (as highlighted in the top left most quadrant) was identified as material for the first sustainability report of JNPT.

Figure 5: Materiality Evaluation Process

Materiality Map

The materiality map depicts the relative prioritization of material issues by JNPT and key stakeholders on the X-axis and Y-axis, respectively.

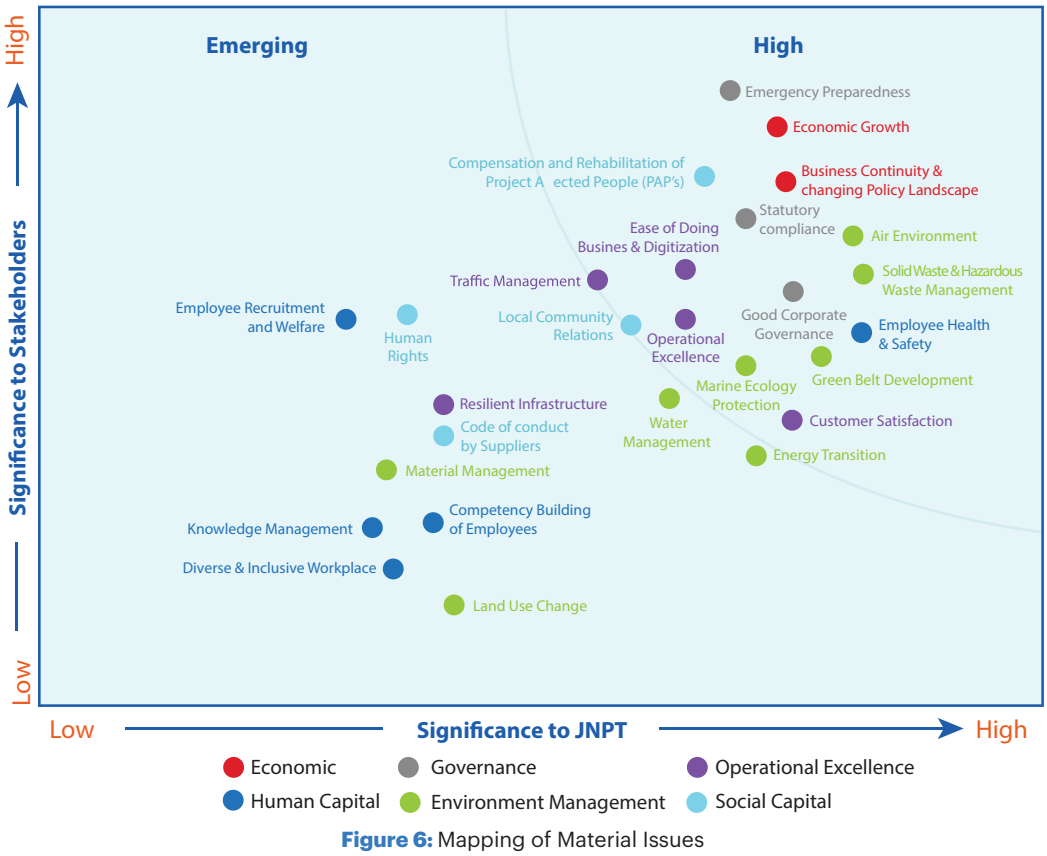

Figure 6: Mapping of Material Issues

यथार्थता मूल्यांकन

जेएनपीटी के प्रभाव की सीमा में परिलक्षित यथार्थ विषयों/मुद्दों में, मौजूदा अवसंरचना के विस्तार या उन्नयन के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्षों को न्यूनतम करने के अभिप्राय से, आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन संबंधी मुद्दों का पूरा वर्णक्रम शामिल है। ये यथार्थ विषय/मुद्दे, जेएनपीटी के प्रबंधन के लिए, "ग्रीन पोर्ट स्टेट्स" हासिल करने के प्रयासों को जारी रखते हुए, इसके प्रयासों और बजट की प्राथमिकता निर्धारित करने का भी आधार हैं।

अपनी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए जेएनपीटी ने यथार्थता मूल्यांकन की विधि को अपनाया है, जैसा कि चित्र 5 में दिखाया गया है और यथार्थ मुद्दों की पहचान की है, जैसा कि चित्र 6 में दिखाया गया है।

चरण 1 चिन्हांकर

आंतरिक और बाहरी स्क्रीनिंग (पीयर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट की बेंचमार्किंग, विश्व स्तर पर स्वीकृत ईएसजी फ्रेमवर्क (एसएएसबी, आदि) और मीडिया विश्लेषण) के माध्यम से प्रासंगिक यथार्थ विषयों की पहचान की गई।

चरण 2 प्राथमिकता निर्धारण

जेएनपीटी की कोर टीम द्वारा यथार्थ मुद्दों के व्यापक सेट की समीक्षा की गई। प्राथमिकता निर्धारण के चरण में कुल 27 विषयों को यथार्थ माना गया था।

चरण 3 सहभागिता

27 यथार्थ मुद्दों पर इनपुट और रैंकिंग प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय से संबंधित प्राथमिकता आधारित आंतरिक और बाहरी हितधारकों से सहभागिता।

चरण 4 यथार्थता मूल्यांकन

15 विषयों का एक सेट (जैसा कि ऊपर सबसे बाएं चौकोर भाग में रेखांकित किया गया है) को जेएनपीटी की पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के लिए यथार्थ के रूप में चिन्हित किया गया।

चित्र 5: यथार्थता मूल्यांकन प्रक्रम

यथार्थता मानचित्र

यथार्थता मानचित्र, जेएनपीटी और प्रमुख हितधारकों द्वारा क्रमशः एक्स-अक्ष और वाई-अक्ष पर यथार्थ मुद्दों के संबंधित प्राथमिकता निर्धारण को चित्रित करता है।

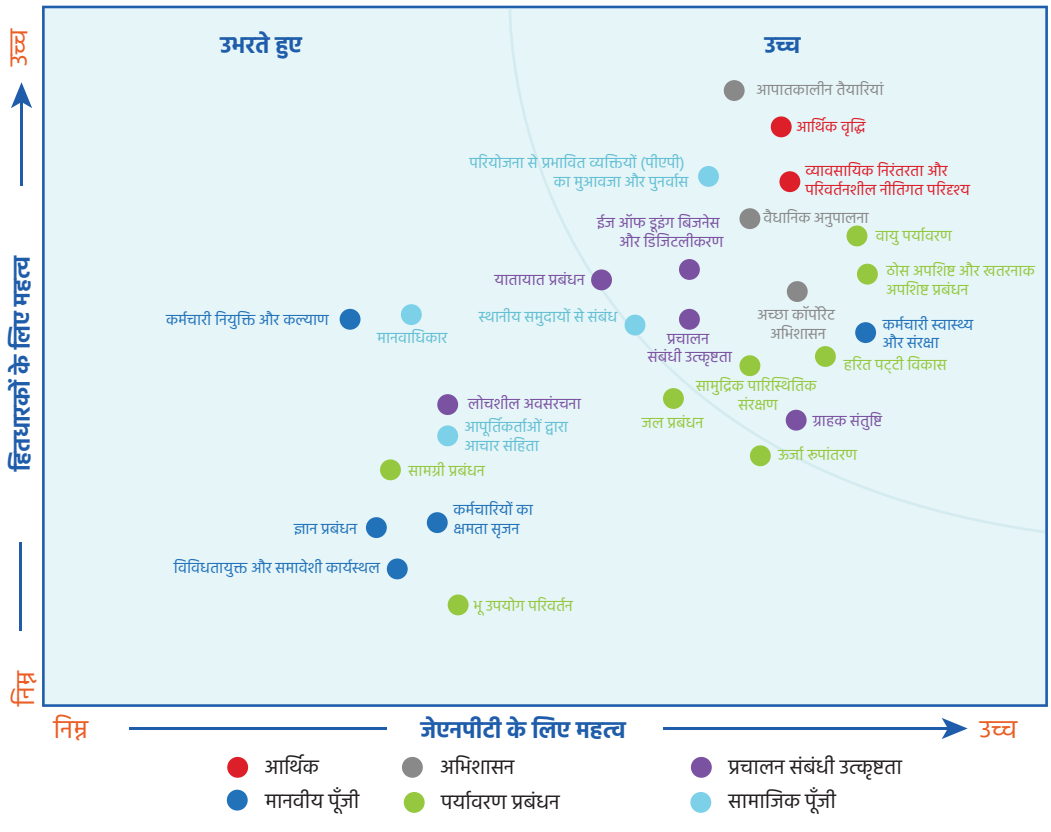

चित्र 6: यथार्थ मुद्दों का मानचित्रण

Sustainability Context: JNPT

The shades of blue in the JNPT logo are inspired by the water bodies that are the source of JNPT's livelihood. The strokes and lines help distinguish JNPT as the port that offers flexibility and ease in operations. The globe gives a clear message that the port is associated with international trade.

The rotating arrows around the globe suggest mobilization in import and export trade. The steer at the top signifies JNPT's vision to be at the apex of trade in India, and the white strokes at the horizon represent its international footprint. The waves at the bottom symbolize the highly efficient and productive modern container handling port, facilitating international trade.

JNPT's Alignment with the Blue Economy Principles and Maritime India Vision 2030

JNPT's operations to achieve the "Green Port Status" reflect the Port's alignment with the Blue Economy Principles and Maritime India Vision (MIV) 2030 (Figure 7).

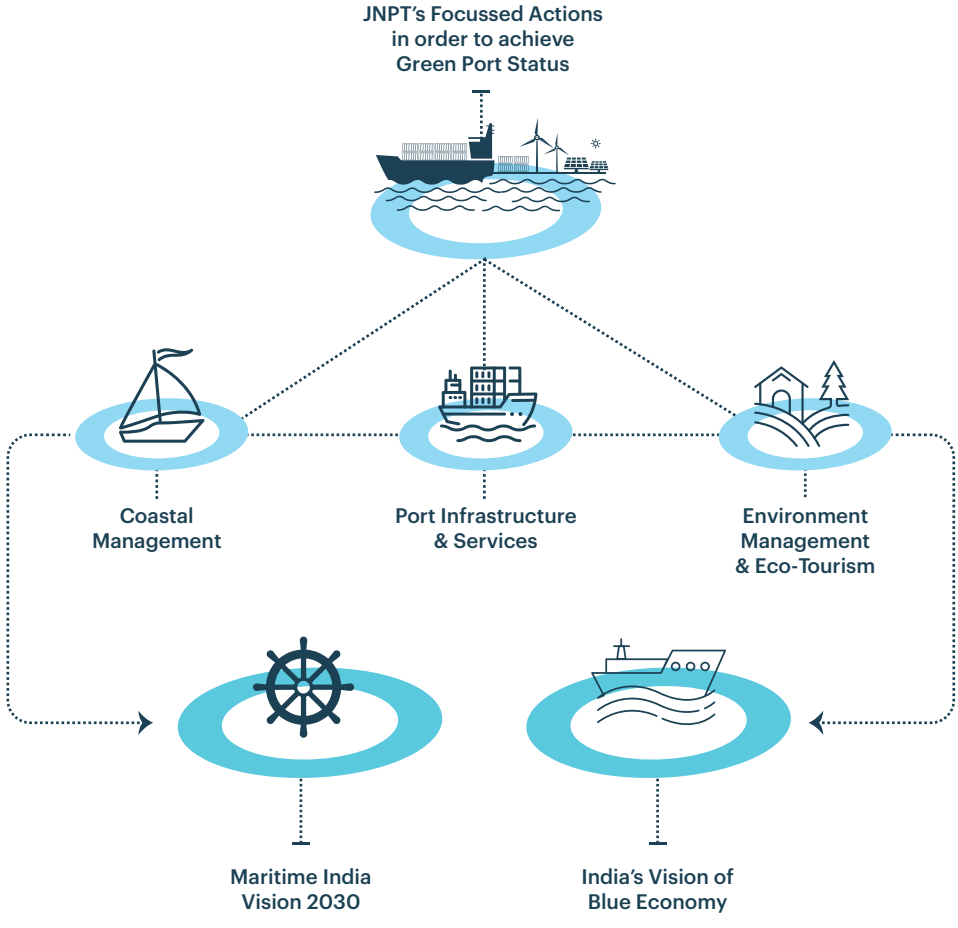

Figure 7: A schematic diagram of JNPT's alignment with Maritime India Vision 2030 and India's vision of Blue Economy

सस्टेनेबिलिटी का संदर्भ: जेएनपीटी

जेएनपीटी के लोगो में नीले रंग की घटाएँ, जल राशियों से प्रेरित हैं जो जेएनपीटी की आजीविका का स्रोत हैं। धारियां और रेखाएं, जेएनपीटी को एक ऐसे पत्तन के रूप में अलग से प्रतिष्ठित करने में सहायक हैं जो लचीलापन, तथा प्रचालनों में सरलता प्रदान करता है। ग्लोब एक स्पष्ट संदेश देता है कि बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है।

ग्लोब पर घूमते तीर, आयात और निर्यात व्यापार में गतिशीलता का संकेत देते हैं। शीर्ष पर स्टीयर, भारत में व्यापार के शीर्ष पर रहने के लिए जेएनपीटी के विज़न को परिलक्षित करता है और क्षितिज पर सफेद धारियां, इसकी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति को प्रदर्शित करती हैं। नीचे अंकित लहरें, उच्च कार्यक्षम और उत्पादक आधुनिक कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट (पत्तन) का प्रतीक हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाता है।

ब्ल्यू इकोनॉमी प्रिंसिपल्स और मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 के साथ जेएनपीटी की अनुरूपता

"ग्रीन पोर्ट स्टेट्स" हासिल करने के लिए जेएनपीटी के प्रचालन, ब्ल्यू इकोनॉमी प्रिंसिपल्स और मैरिटाइम इंडिया विज़न (एमआईवी) 2030 के साथ पत्तन की अनुरूपता दर्शाते हैं (चित्र 7)।

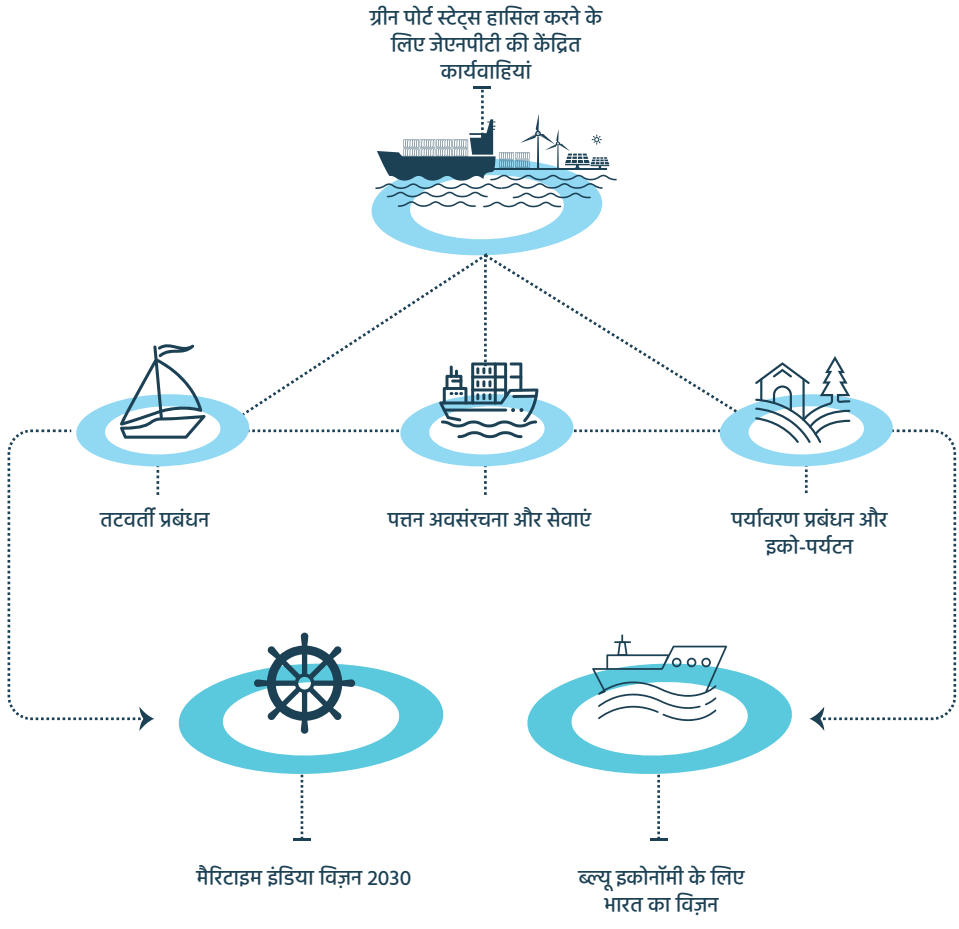

चित्र 7: मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 और भारत के ब्ल्यू इकोनॉमी के विज़न से जेएनपीटी की अनुरूपता का एक योजनाबद्ध आरेख

Table 3 depicts JNPT's contribution to accelerate the growth of the maritime sector and India's vision of Blue Economy. The actions / initiatives adopted by JNPT to achieve the Green Port Status are in complete synergy with the key themes as identified under the Maritime India Vision 2030.

Table 3: JNPT's alignment with Blue Economy Principles and Maritime India Vision 2030

JNPT's Material Topics	Action / Initiatives by JNPT	MIV 2030*	India's Vision of Blue Economy**: Priority Areas
◆ Economic Growth ◆ Resilient Infrastructure ◆ Operational Excellence	◆ Development of Port-Based SEZ ◆ Development of Integrated Centralized Parking Zone for Parking of Tractor Trailers ◆ Development of Coastal Berth ◆ Development of Dry Ports at Jalna, Wardha, Nasik, and Sangli * *Details of the Initiatives can be Found in the Chapter: Operational Excellence*	◆ Develop Best-in-Class Port Infrastructure	◆ Priority Area 5: Logistics, Infrastructure, and Shipping (including transhipments) ◆ Priority Area 4: Manufacturing, Emerging Industries, Trade, Technology, Services, and Skill Development
◆ Ease of Doing Business and Digitization ◆ Traffic Management	◆ Development of Integrated Common Rail Yard Facility at JNPT ◆ Commissioning of 15 E-RTGCs at JNPT Container Terminal and Commissioning of RTGCs in APMT and Replacement of RMQCs & RTGCs in NSICT ◆ Construction of Flyovers and Widening of Roads Within the Port Premises ◆ Digitization * *Details of the Initiatives can be Found in the Sub-section: Ease of Doing Business, Traffic Management, and Digitization*	◆ Drive E2E Logistics Efficiency and Cost Competitiveness	◆ Priority Area 5: Logistics, Infrastructure, and Shipping (including transhipments)
◆ Good Corporate Governance ◆ Statutory Compliance ◆ Business Continuity and Changing Landscape	◆ Constituted Sustainability Core Team ◆ Environment Management and Monitoring Plan ◆ Stakeholder Engagement Framework in Place ◆ Conducted Materiality Assessment * *Details of the Initiatives can be Found in the Chapter: Sustainability at JNPT*	◆ Strengthen Policy and Institutional Framework to Support All Stakeholders	◆ Priority Area 4: Manufacturing, Emerging Industries, Trade, Technology, Services, and Skill Development

तालिका 3 में सामुद्रिक क्षेत्र के विकास को तेज़ करने के लिए जेएनपीटी के योगदान और ब्ल्यू इकोनॉमी के लिए भारत के विज़न को दर्शाया गया है। ग्रीन पोर्ट स्टेट्स हासिल करने के लिए जेएनपीटी द्वारा की गई कार्यवाहियां/अपनाए गए कार्यक्रम, मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 के अंतर्गत चिन्हित प्रमुख थीमों से पूरी तरह से पारस्परिक तालमेल में जुड़े हैं।

तालिका 3: ब्ल्यू इकोनॉमी प्रिंसिपल्स और मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 से जेएनपीटी की अनुरूपता

जेएनपीटी के यथार्थ विषय	जेएनपीटी की कार्यवाहियां / कार्यक्रम	एमआईवी 2030*	ब्ल्यू इकोनॉमी के लिए भारत का विज़न**: प्राथमिकता के क्षेत्र
• आर्थिक वृद्धि • लचीली अवसंरचना • प्रचालन संबंधी उत्कृष्टता	• पत्तन-आधारित एसईजेड का विकास • ट्रैक्टर ट्रेलरों की पार्किंग के लिए एकीकृत केंद्रीय पार्किंग जोन का विकास • कोस्टल बर्थ का विकास • जालना, वर्धा, नासिक और सांगली में शुष्क पत्तनों का विकास ** कार्यक्रमों के विवरण: (प्रचालन संबंधी उत्कृष्टता) अध्याय में देखे जा सकते हैं*	• अपने वर्ग में सर्वोत्तम पत्तन अवसंरचना का विकास	• प्राथमिकता के क्षेत्र 5: लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और शिपिंग (ट्रांसशिपमेन्ट्स सहित) • प्राथमिकता के क्षेत्र 4: उत्पादन, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास
• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और डिजिटलीकरण • यातायात प्रबंधन	• जेएनपीटी में एकीकृत कॉमन रेल यार्ड सुविधा का विकास • जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल पर 15 ई-आरटीजीसी की स्थापना और एपीएमटी में आरटीजीसी की स्थापना और एनएसआईसीटी में आरएमक्यूसी और आरटीजीसी का प्रतिस्थापन • पत्तन परिसर में उपरिगामी सेतुओं का निर्माण और सड़कों का चौड़ीकरण • डिजिटलीकरण ** कार्यक्रमों के विवरण: (ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यातायात प्रबंधन और डिजिटलीकरण) उप-अनुभाग में देखे जा सकते हैं*	• ई2ई लॉजिस्टिक्स कार्यदक्षता और लागत कुशलता	• प्राथमिकता के क्षेत्र 5: लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और शिपिंग (ट्रांसशिपमेन्ट्स सहित)
• अच्छा कॉर्पोरेट अभिशासन • वैधानिक अनुपालना • व्यावसायिक निरंतरता और परिवर्तनशील परिदृश्य	• सस्टेनेबिलिटी कोर टीम का गठन • पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना • हितधारक सहभागिता रूपरेखा की स्थापना • यथार्थता मूल्यांकन का आयोजन ** कार्यक्रमों के विवरण: (जेएनपीटी में सस्टेनेबिलिटी) अध्याय में देखे जा सकते हैं*	• सभी हितधारक को समर्थित करने के लिए नीति और संस्थागत रूपरेखा का सुदृढ़ीकरण	• प्राथमिकता के क्षेत्र 4: उत्पादन, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास

JNPT's Material Topics	Action / Initiatives by JNPT	MIV 2030*	India's Vision of Blue Economy**: Priority Areas
◆ Knowledge Management ◆ Emergency Preparedness ◆ Employee Health and Safety	◆ JNPT Antwerp Port Training & Consultancy Foundation ◆ JNPT's Partnership with Industry and Sectoral Association ◆ Emergency Preparedness * *Details of the Initiatives can be Found in the Chapter: Social and Human Capital*	◆ Enhance India's Global Stature and Maritime Cooperation	◆ Priority Area 7: Security, Strategic Dimensions, and International Engagement
◆ Energy Transition ◆ Air Environment ◆ Solid Waste and Hazardous Waste Management ◆ Water Management ◆ Green Belt Development	◆ Switching from Diesel Engine to E-RTGC ◆ Shore Power Supply to Tugs/Port Crafts ◆ Solar Panels with 2310 MWp Installed Capacity ◆ Sewage Treatment Plant ◆ 10 MT/Day Solid Waste Management Facility * *Details of the Initiatives can be Found in the Chapter: Environmental Management*	◆ Lead the World in Safe, Sustainable and Green Maritime Sector	◆ Priority Area 4: Manufacturing, Emerging Industries, Trade, Technology, Services, and Skill Development

* Basis Maritime India Vision 2030 by Ministry of Ports, Shipping and Waterways

** Basis India's Blue Economy: A Draft Policy Framework, Economic Advisory Council to the Prime Minister, Government of India

The mapping of the key performance indicators (KPIs) in Table 4 is derived from MIV 2030 key targets. Globally benchmarked targets have been defined to improve logistical efficiencies, cost competitiveness, promote domestic ship building, global hub for cruise tourism, and so on. In total, there are 11 identified KPIs and set targets (2030) across the 10 identified key themes. The relevant indicators where actions by JNPT are aligned and monitored are also given in Table 4. The same performance indicators are discussed in detail in the Chapter: Operational Excellence.

Table 4: JNPT performance in alignment with the identified MIV 2030 – KPIs

Key Performance Indicator	Current (2020)	Status: JNPT (April 2020 – March 2021)	Target (2030)
Major ports* with >300 MTPA cargo handling capacity	–	118.3 MMTA	300
Average vessel turnaround time (containers)	25 hours#	33.12 hours	<20 hours
Average container dwell time	55 hours	44.80	<40 hours
Average ship daily output (gross tonnage)	16,500	26,875	>30,000

* Vadhavan-JNPT cluster is identified as one of the major ports to achieve >300 MMTA along with two other major ports.

IPA's port statistics report FY19–20; TRT considered for major container ports (JNPT, Chennai, Cochin, Vishakhapatnam, and V. O. Chidambaranar)

जेएनपीटी के यथार्थ विषय	जेएनपीटी की कार्यवाहियां / कार्यक्रम	एमआईवी 2030*	ब्ल्यू इकोनॉमी के लिए भारत का विज़न**: प्राथमिकता के क्षेत्र
◆ ज्ञान प्रबंधन ◆ आपातकालीन तैयारियां ◆ कर्मचारी स्वास्थ्य और संरक्षा	◆ जेएनपीटी एंटवर्प पत्तन प्रशिक्षण और परामर्श फाउंडेशन ◆ औद्योगिक और सेक्टरवार एसोसिएशन से जेएनपीटी की साझेदारी ◆ आपातकालीन तैयारियां ** कार्यक्रमों के विवरण: (सामाजिक और मानवीय पूँजी) अध्याय में देखे जा सकते हैं*	◆ भारत के वैश्विक कद और सामुद्रिक सहयोग का संवर्धन	◆ प्राथमिकता के क्षेत्र 7: सुरक्षा, रणनीतिक आयाम और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता
◆ ऊर्जा रुपांतरण ◆ वायु पर्यावरण ◆ ठोस अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन ◆ जल प्रबंधन ◆ हरित पट्टी विकास	◆ डीजल इंजन से ई-आरटीजीसी की ओर परिवर्तन ◆ टग/पत्तन क्राफ्ट्स पर तटीय विद्युत आपूर्ति ◆ 2310 मेगावाट पीक स्थापित क्षमता के साथ सोलर पैनल ◆ सीवेज उपचार संयंत्र ◆ 10 मीट्रिक टन/प्रतिदिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई ** कार्यक्रमों के विवरण: (पर्यावरण प्रबंधन) अध्याय में देखे जा सकते हैं*	◆ सुरक्षित, धारणीय और हरित सामुद्रिक क्षेत्र की ओर विश्व का नेतृत्व	◆ प्राथमिकता के क्षेत्र 4: उत्पादन, उभरते उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सेवाएं और कौशल विकास

* आधार, पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030

** आधार, भारत की ब्ल्यू इकोनॉमी: प्रधानमंत्री, भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए नीतिगत रुपरेखा का एक प्रारुप

तालिका 4 में प्रमुख कार्यप्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) का मापन एमआईवी 2030 के प्रमुख लक्ष्यों से लिया गया है। लॉजिस्टिक सक्षमताएं, लागत कुशलता बढ़ाने, घरेलू जहाज निर्माण को बढ़ावा देने, क्रूज पर्यटन के लिए वैश्विक केंद्र और इसी प्रकार अन्य के लिए वैश्विक स्तर पर बेंचमार्क वाले लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर, 11 चिन्हित केपीआई और 10 चिन्हित प्रमुख थीमों में निर्धारित लक्ष्य (2030)। संबंधित संकेतक, जहां जेएनपीटी की कार्यवाहियां संरेखित और पर्यवेक्षित की गई हैं, वे भी तालिका 4 में दिए गए हैं। उन्हीं कार्यप्रदर्शन संकेतकों पर प्रचालन संबंधी उत्कृष्टता नामक अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है:

तालिका 4: चिन्हित एमआईवी 2030 – केपीआई के सापेक्ष जेएनपीटी का कार्यप्रदर्शन

प्रमुख कार्यप्रदर्शन संकेतक	वर्तमान (2020)	स्थिति: जेएनपीटी (अप्रैल 2020 – मार्च 2021)	लक्ष्य (2030)
प्रमुख पत्तन* >300 एमटीपीए कार्गो हैंडलिंग क्षमता के साथ	–	118.3 एमएमटीए	300
औसत जहाज टर्नअराउंड टाइम (कंटेनर)	25 घंटे#	33.12 घंटे	<20 घंटे
औसत कंटेनर ड्वेल टाइम	55 घंटे	44.80	<40 घंटे
औसत जहाज दैनिक आउटपुट (सकल टनेज)	16500	26875	>30,000

* वाढवण जेएनपीटी संकुल को, >300 एमएमटीए हासिल करने के लिए दो अन्य प्रमुख पत्तनों के साथ एक प्रमुख पत्तन के रुप में चिन्हित किया गया है।

\# आईपीए की पत्तन सांख्यिकी रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 19–20; प्रमुख कंटेनर पत्तनों (जेएनपीटी, चेन्नई, कोचिन, विशाखापट्टनम और वी.ओ. चिदम्बरनार) के लिए विचारित टीआरटी

ECONOMIC PERFORMANCE

आर्थिक निष्पादन

Economic Performance

Economic Development and Job Creation

Financial Performance

In 2020–21, JNPT generated a net revenue of ₹1921* crore from operations, accounting for a 1.12% increase on a year-on-year basis. The profit after tax was calculated at ₹804 crore, which declined by 24% on a year-on-year basis. The incremental increase in revenue is correlated to the COVID-19 pandemic and its impacts on the overall economy. The direct economic implications of JNPT are depicted in Figure 8. The economic value retained for FY2020-21 is ₹181 crore.

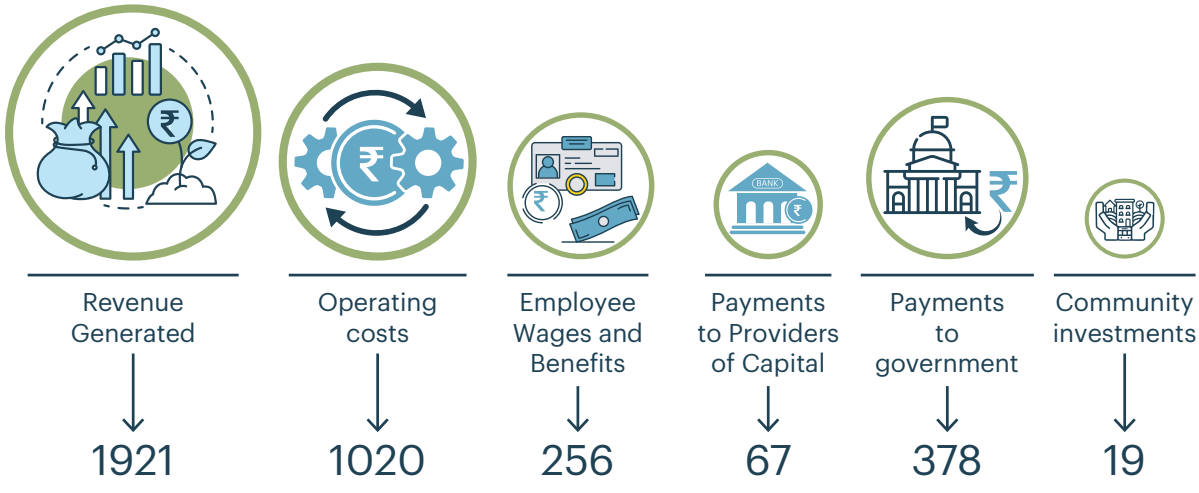

Figure 8: Economic value retained (₹ crores)

* Data corresponds to unaudited FY 2020–21 financial statements

The trends of the net revenue from operations and profit after taxes for JNPT in the last three years are shown in Figures 9 and 10.

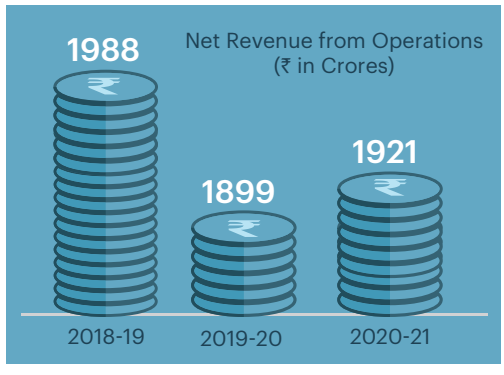

Figure 9: Net revenue from operations

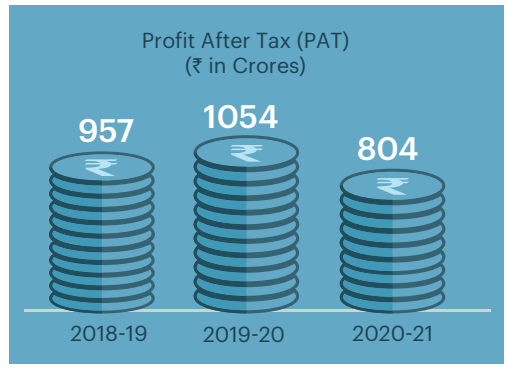

Figure 10: Profit After Tax

आर्थिक निष्पादन

आर्थिक विकास एवं रोजगार निर्माण

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2020-21 में जनेप न्यास ने प्रचालन से रु.1921 करोड़ का निवल राजस्व प्राप्त किया जो वार्षिक आधार पर 1.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कर पश्चात लाभ रु.804 करोड़ परिकलित किया गया जो वार्षिक आधार पर 24 प्रतिशत कम है। राजस्व वृद्धि कोविड़-19 महामारी तथा उसके समग्र अर्थव्यवस्था पर हुए प्रभाव से संबन्धित है। जनेप न्यास के प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव चित्र-8 में दर्शाए गए है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रतिधारित आर्थिक मूल्य रु.181 करोड़ है।

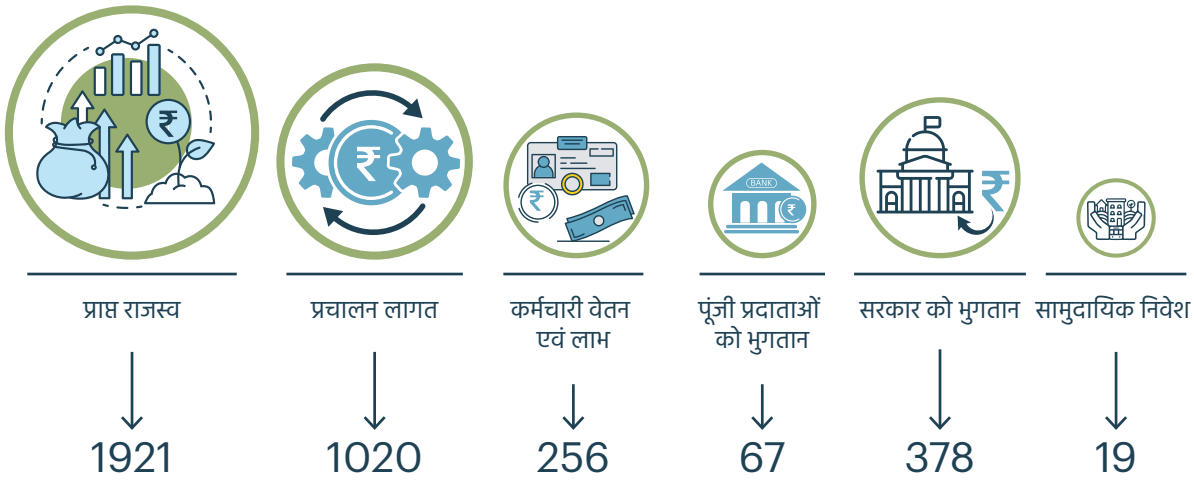

चित्र 8 - प्रतिधारित आर्थिक मूल्य (रु.करोड़ में)

* यह आंकड़े वित्त वर्ष 2020-21 के गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुरुप है।

गत तीन वर्षों में जनेप न्यास के प्रचालन से निवल राजस्व एवं कर पश्चात लाभ के रुझान चित्र 9 और 10 में दर्शाए गए है।

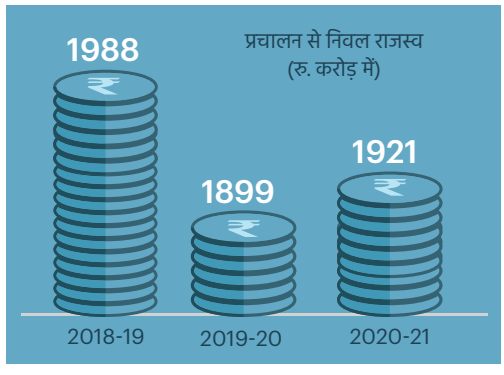

चित्र 9 : प्रचालन से निवल राजस्व

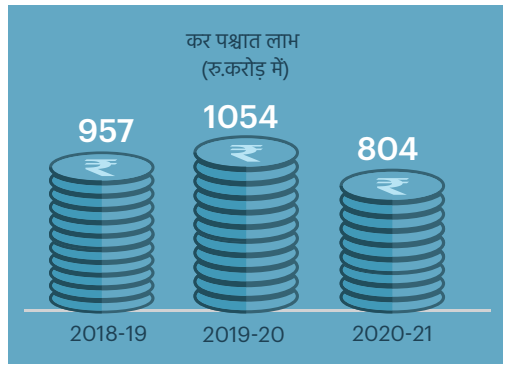

चित्र 10 : कर पश्चात लाभ

Employee Benefits

JNPT employees are covered under various benefit schemes, such as gratuity, pension fund, and leave encashment liability. In the reporting year 2020–21, a total amount of ₹73.85 crore was the allotted budget recognized towards employee benefits (Table 5). JNPT covers its employees under various insurance policies, such as group personal accident insurance scheme and group term insurance. The coverage to the employees is provided as per their respective grades. The wages offered to the employees in all categories adhere to the requirements given in the Minimum Wages Act, 1948.

Table 5: Direct employee benefits **Amount (₹ in Crore)**

Particulars	2018–19	2019–20	2020–21
Gratuity (Liability as on Balance Sheet Date)	58.14	19.31	5.00
Provident Fund Contribution	26.28	30.29	45.85
Super Annuation Contribution	–	–	23.00
Total	**84.42**	**49.60**	**73.85**

JNPT's property is a national asset and the Port has been insuring these assets since 2006 against the AOG, which refers to the Act of God perils including – storm, tempest, flood and inundation, subsidence, rockslide, landslide, earthquake, tsunami, and other natural calamities that are beyond the control of human beings. This is in compliance with the directives received from the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and Indian Ports Association (IPA). JNPT has taken a Comprehensive Port Package Policy worth ₹4821.92 crore, which covers risks including Standard Fire and Specials Peril Policy with Earthquake Extension (for assets outside port operational area and township), Property, Liability, Business Interruption, Marine Hull, Fidelity Guarantee, Electronic Equipment, Terrorism, and Directors and Officers Liability Policy.

Indirect Economic Impacts

Besides the direct economic impacts, JNPT also provides indirect opportunities for employment, livelihood generation, and social inclusion. These are largely driven by the interventions undertaken as part of JNPT's corporate social responsibility (CSR) programmes. The details are discussed in the Chapter: Human and Social Capital.

JNPT has provided direct and indirect employment to around

2600

JNP-PAPs (projected affected persons).

2033

residential units constructed in its township along with pre-primary, primary, and secondary schools (English and Marathi medium).

During the reporting period,

₹ 19.32 *crore was spent towards health, education, water conservation, and other developmental activities for the benefit of communities in the villages surrounding JNPT.*

कर्मचारी लाभ

जनेप न्यास कर्मचारियों को उपदान, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण जैसे विभिन्न लाभ योजनाओं के लिए कवर किया गया है । समीक्षाधीन वर्ष 2020-21 में कर्मचारी लाभ के लिए 73.85 करोड़ रुपये की राशि बजट में आबंटित की गई (सारणी -5)। जनेप न्यास ने अपने कर्मचारियों को समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और समूह अवधि बीमा जैसी विभिन्न बीमा पॉलिसियों के तहत कवर किया है। कर्मचारियों को उनके संबंधित श्रेणी के अनुसार कवरेज प्रदान किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को मजदूरी दी जाती है ।

सारणी 5 : **प्रत्यक्ष कर्मचारी लाभ** **राशि (₹ करोड़ में)**

विवरण	2018–19	2019–20	2020–21
उपदान (तुलन पत्र तिथि के अनुसार देयता)	58.14	19.31	5.00
भविष्य निधि अंशदान	26.28	30.29	45.85
अधिवर्षिता अंशदान	–	–	23.00
कुल	**84.42**	**49.60**	**73.85**

जनेप न्यास की संपत्ति राष्ट्रीय परिसंपत्ति है और पत्तन वर्ष 2006 से इन परिसंपत्तियों का अन्य प्राकृतिक आपदाएं जो मानव नियंत्रण से परे होती है के विरुद्ध बीमा कराता रहा है जिसमें आँधी,तूफान, बाढ़ और सैलाब, अवतलन, चट्टानें खिसकना, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी शामिल है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और भारतीय पत्तन संघ से प्राप्त निर्देशों के अनुरुप इसका अनुपालन किया गया है। जनेप न्यास ने 4821.92 करोड़ रुपये की समग्र पत्तन पैकेज पॉलिसी ली है, जो (पत्तन प्रचालन क्षेत्र और नगर क्षेत्र के बाहर की परिसंपत्तियों के लिए) भूकंप के साथ आग और संपत्ति, देयता, व्यापार में बाधा, समुद्री हल, विश्वस्तता गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आतंकवाद के जोखिम को कवर करती है साथ ही इसमें निदेशकों और अधिकारियों की देयता पॉलिसी भी शामिल है।

अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव

प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों के अलावा, जनेप न्यास रोजगार, आजीविका सृजन और सामाजिक समावेशन के लिए अप्रत्यक्ष अवसर भी प्रदान करता है। ये जनेप न्यास के निगमित सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में बड़े पैमाने पर किए गए प्रयासों से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में खंड : मानवीय एवं सामाजिक पूंजी में विस्तृत चर्चा की गई है।

जनेप न्यास ने लगभग

2600

जनेप परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्रदान किया है।

पत्तन ने अपने नगरक्षेत्र में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक पाठशाला (अंग्रेजी और मराठी माध्यम) के साथ-साथ

2033

रिहायशी फ्लॅटों का निर्माण किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान जनेप न्यास के आसपास के गांववालों के लाभ हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संरक्षण और अन्य विकास गतिविधियों पर

₹ 19.32 *करोड़ रुपये खर्च किए।*

OPERATIONAL EXCELLENCE

प्रचालनीय उत्कृष्टता

Operational Excellence

The COVID-19 resulted in major structural implications on the country's economy. The effects were cyclical and impacted the growth of the Port and the allied sectors. Despite the pandemic, during FY2020–21, JNPT registered a throughput of over 4.7 million twenty-foot equivalent units (TEUs) in container handling and the total traffic handled was 64.81 million tonne. Additionally, the Port witnessed a major improvement in the average turnaround time of all vessels (from pilot boarding to pilot de-boarding) during FY2019–20 by 2.62%, i.e., from 29.41 hours to 28.64 hours. During FY2020–21, the turnaround time for container vessels (from pilot boarding to pilot de-boarding) lowered by 2.01%, i.e., from 25.82 hours to 25.30 hours.

Despite the challenges and hurdles posed by the COVID-19 pandemic, JNPT facilitated the construction of a new centralized parking plaza during the reporting period. JNPT has developed Centralized Parking Plaza with an objective to provide parking facility for trucks carrying factory stuffed export containers and enable completing pre-gate entry formalities and documentation for export etc. under one window system. The Port also received the operational status for India's first port-based SEZ. The Port completed the construction of a coastal berth with the capacity to handle 2.5 million tonne of coastal cargo including liquid cargo. Port also inaugurated the opening of an inter terminal route connecting BMCT with other terminals to enhance operational efficiency. The road is custom notified road thereby eliminating customs formalities and saving time to travel between BMCT to other terminals.

GRI 103-3

प्रचालनीय उत्कृष्टता

कोविड-19 ने देश की अर्थव्यवस्था पर बड़े ढांचागत उलझाव खड़े किए । प्रभाव चक्रीय थे और उन्होने पत्तन एवं संबद्ध क्षेत्रों के विकास को प्रभावित किया। महामारी के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, जनेप न्यास ने कंटेनर प्रहस्तन में 4.7 मिलियन से अधिक बीस-फुट समकक्ष टीईयू का प्रहस्तन दर्ज किया और कुल 64.81 मिलियन टन का यातायात प्रहस्तन किया। इसके अलावा, पत्तन ने वित्त वर्ष 2019-20 में सभी जलयानों (पायलट के जलयान पर चढ़ने से उतरने तक) के औसत घुमाव समय में (29.41 घंटों से 28.64 घंटों तक) 2.62 प्रतिशत का बड़ा सुधार देखा। वित्त वर्ष 2020-21 में कंटेनर जलयानों (पायलट के जलयान पर चढ़ने से उतरने तक) के औसत घुमाव समय में (25.82 घंटों से 28.64 घंटों तक) 2.01 प्रतिशत की कमी आयी।

कोविड-19 के कारण उभरी चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद जनेप न्यास ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान नए केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा की सुविधा प्रदान की। जनेप न्यास ने कारखानों से कच्चा माल ले जानेवाले निर्यात के लिए और सिंगल विंडो प्रणाली के अधीन निर्यात हेतु प्रवेश पूर्व औपचारिकताओं और दस्तावेजों को पूरा करने के उद्देश्य से केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा विकसित किया है। जनेप न्यास को भारत का पहला पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) निर्माण करनेवाला पत्तन का दर्जा भी मिला। पत्तन ने तरल कार्गो सहित 2.5 मिलियन टन तटीय कार्गो को प्रहस्तन करने की क्षमता के साथ एक तटीय घाट का निर्माण किया। पत्तन ने प्रचालन क्षमता वृद्धि हेतु बीएमसीटी को अन्य टर्मिनलों से जोडनेवाले अंतर टर्मिनल मार्ग का उद्घाटन किया। यह सीमा-शुल्क अधिसूचित सड़क होने से सीमाशुल्क औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है और बीएमसीटी से अन्य टर्मिनलों के बीच आवागमन करने के समय में बचत होती है।

The 2nd edition of the Maritime India Summit (MIS), held virtually from 2 March to 4 March 2021, was inaugurated by the Honourable Prime Minister of India Shri Narendra Modi. The Summit provided a platform where the world's prominent dignitaries from the maritime fraternity participated and their shared ideas. JNPT signed over 30 MOUs with potential investors for port projects, technology transfer, and the development of plots in JNPT SEZ.

Over the years, JNPT's operational performance has increased steadily. Figures 11 and 12 represent the average import and export dwell time (container) in the last three years. The average import dwell time has reduced significantly by 56%, and the average export dwell time has reduced by 3% from FY2018–19.

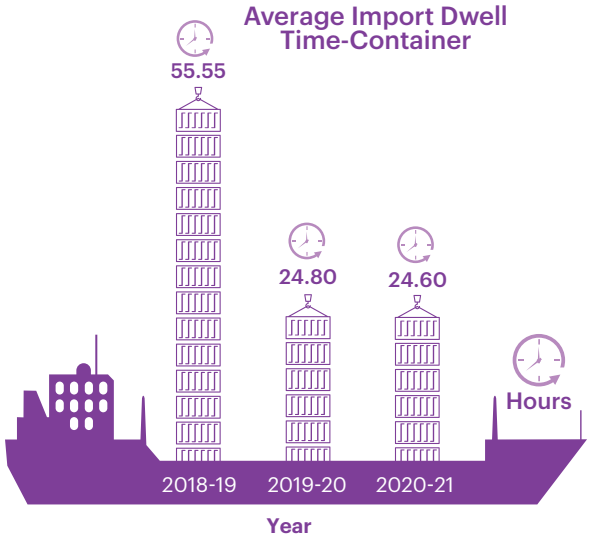

Figure 11: Average import dwell time (container)

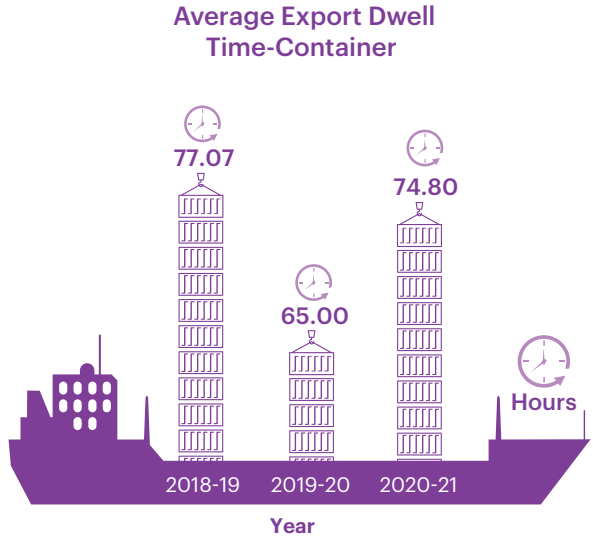

Figure 12: Average export dwell time (container)

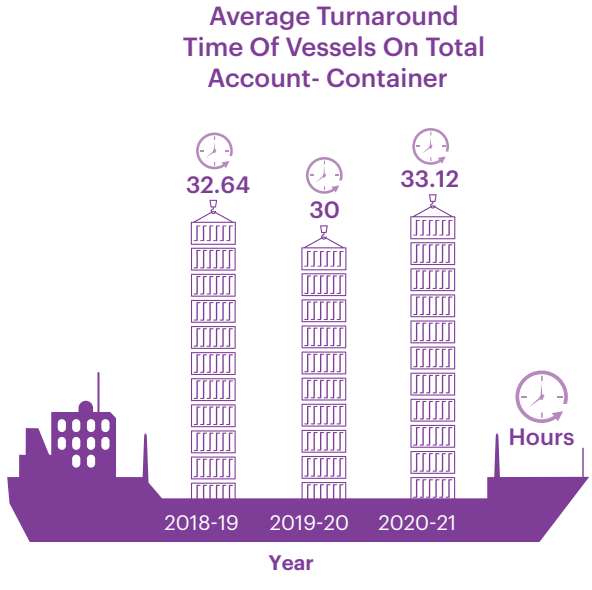

Figure 13: Average turnaround time of vessels (container)

दिनांक 2 मार्च से 4 मार्च। 2021 तक आयोजित दूसरे वर्च्युअल मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया । शिखर सम्मेलन ने मैरिटाइम बिरादरी के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को मंच प्रदान किया जहां उन्होने भाग लिया और अपने विचारों को साझा किया। जनेप न्यास ने पत्तन परियोजनाओं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और जनेप न्यास विशेष आर्थिक क्षेत्र में भूखंडों के विकास के लिए संभावित निवेशकों के साथ 30 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

पिछले कुछ वर्षों में जनेप न्यास के प्रचालन निष्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। चित्र 11 और 12 में पिछले तीन वर्षों में औसत आयात और निर्यात विराम समय (कंटेनर) को दर्शाया गया है। औसत आयात विराम समय में 56 प्रतिशत की कमी आयी है और वित्त वर्ष 2018-19 से औसत निर्यात विराम समय में 3 प्रतिशत की कमी आयी है।

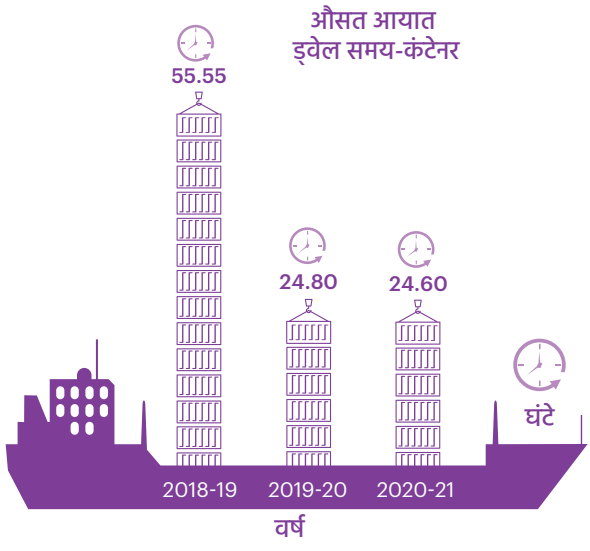

चित्र 11 : औसत आयात (कंटेनर) विराम समय

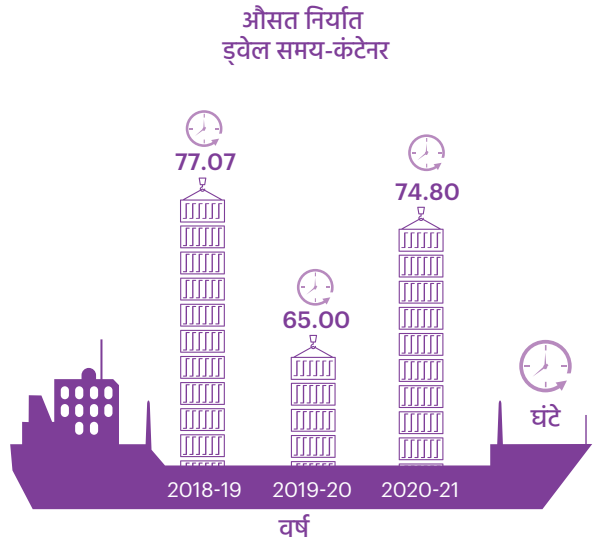

चित्र 12 : औसत निर्यात (कंटेनर) विराम समय

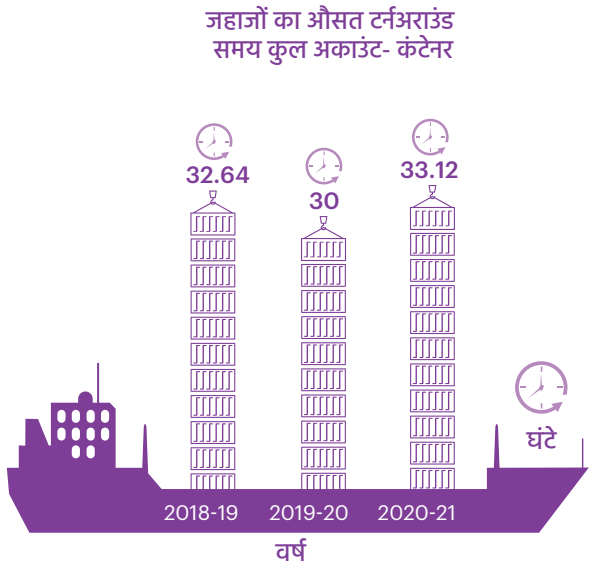

चित्र 13 : जलयानों (कंटेनर) का औसत घुमाव समय

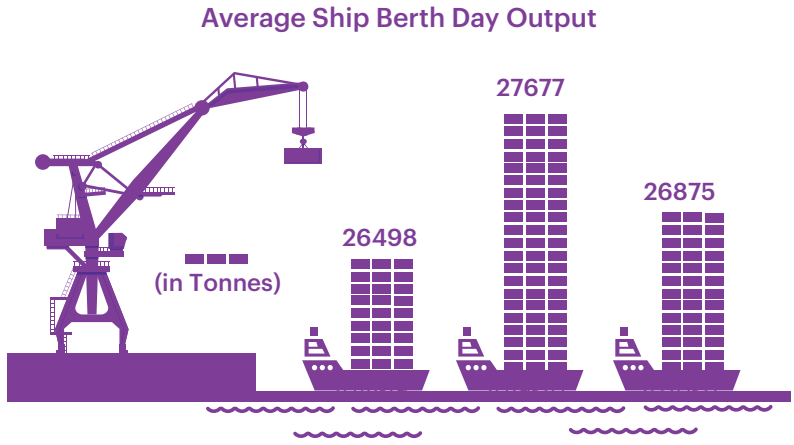

Figure 14: Average ship berth day output

During FY2020–21, Average Turn Round Time of Container Vessels increased by 1.47% from FY2018–19 (Figure 13).

The average ship berth day output is one of the key performance indicators as highlighted under the MIV 2030 (Figure 14). An analysis of JNPT's performance during FY2020–21 reveals that the 2030 target of daily output of greater than 30,000 tonne could be a reality.

Operational Performance

Container Terminal Performance

JNPT registered a throughput of 4.7 million twenty-foot equivalent units (TEUs) in container handling and the total traffic handled was 64.81 million tonne in the reporting period.

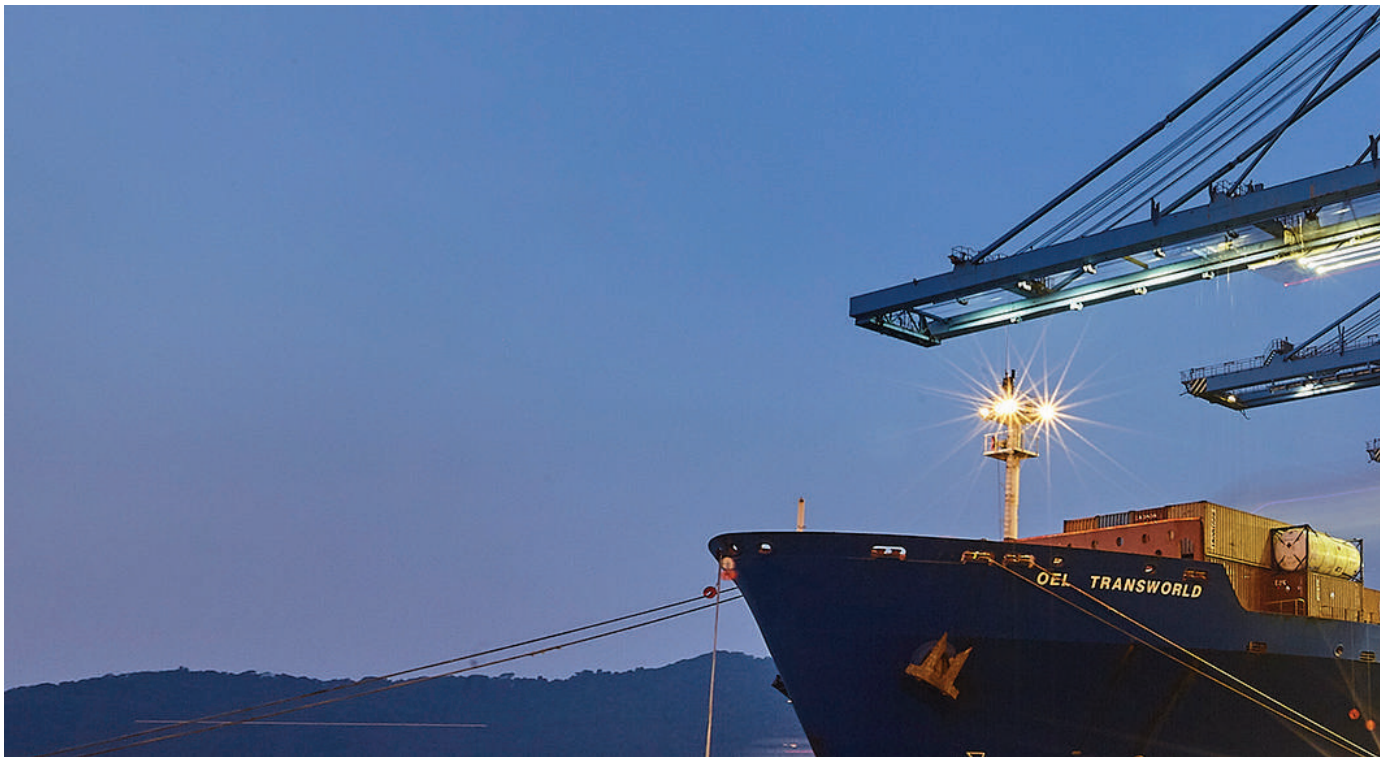

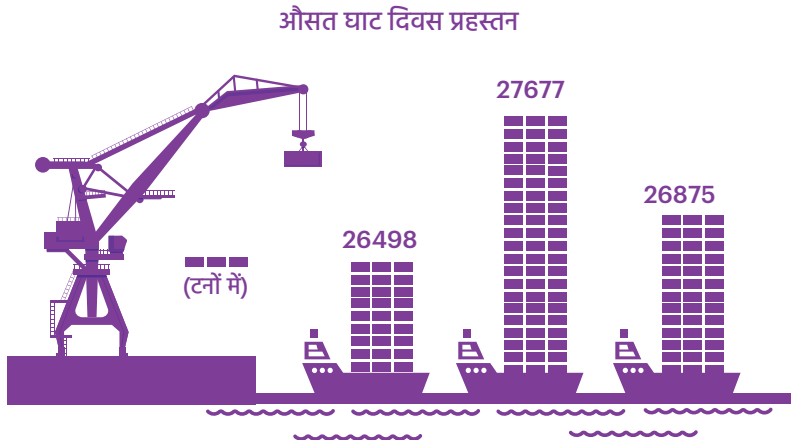

चित्र 14 : औसत जहाज बर्थ दैनिक आउटपुट

वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंटेनर जलयानों के औसत घुमाव समय में 1.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। (चित्र 13)

औसत जलयान घाट दिवस प्रहस्तन एमआयवी 2030 के अधीन दर्शाए गए मुख्य निष्पादन संकेतकों में से एक है (चित्र 14)। जैसा कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जनेप न्यास के निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2030 का 30,000 टन से अधिक के दैनिक प्रहस्तन का लक्ष्य एक वास्तविकता हो सकता है।

प्रचालनीय निष्पादन

कंटेनर टर्मिनल निष्पादन

जनेप न्यास ने कंटेनर प्रहस्तन में 4.7 मिलियन से अधिक बीस-फुट समकक्ष टीईयू का प्रहस्तन दर्ज किया और रिपोर्टिंग अवधि में कुल 64.81 मिलियन टन का यातायात प्रहस्तन किया।

JNPT had a share of 48.66% in terms of TEUs in the total container traffic at major ports from April 2020 to March 2021. The share of JNPCT was 11.63% of the total port traffic handled by the Port.

Table 6: JNPT terminal performance 2021

Sr. No.	Particulars	Unit	Terminal Performance 2021				
			JNPCT	NSICT	NSIGT	APM Terminals	BMCT
1	No. of containers handled in a year	In TEUs	544,027	750,978	779,769	1,668,903	933,154
		In million tonne	6.55	9.33	9.77	21.16	10.94
2	Average gross berth productivity in a year	Moves/hr	55.33	67.76	101.05	91.13	81.13
3	Output per ship berth day in a year	In TEUs	1783	2251	3106	3164	3268

The indicators of terminal performance in the reporting period (FY2020–21), such as the average gross berth productivity saw a decline of 8.58%, the average crane productivity by 1.25%, and the Average Output per Ship Berthday reduced by 7.7% in terms of TEUs.

Table 7: JNPT Traffic Snapshot 2021

Sr. No.		Particulars	Unit	2020–21
1		Total container traffic (JNPT)	In TEUs	4,676,831
	1.a	Share of JNPCT	In %	11.63
2	2.a	Total cargo handled (total traffic)	In million tonne	64.81
		Share of containerized cargo	In %	89.10
	2.b	Share of liquid cargo	In %	9.49
	2.c	Share of dry bulk / miscellaneous	In %	1.41
3		Total traffic	In million tonne	64.81
	3.a	Import	In million tonne	34.54
	3.b	Export	In million tonne	28.83
	3.c	Transhipment	In million tonne	1.44

अप्रैल 2020 से मार्च 2020 तक महापत्तनों के कुल कंटेनर यातायात में टीईयु के संदर्भ में जनेप न्यास की 48.66 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। पत्तनों द्वारा प्रहस्तित कुल यातायात में जनेप कंट की हिस्सेदारी 11.63 प्रतिशत थी।

सारणी 6 : जनेप न्यास टर्मिनल निष्पादन 2021

क्र.सं.	विवरण	इकाई	टर्मिनल निष्पादन 2021				
			जनेप कंट	एनएसआयसीटी	एनएसआयजीटी	एपीएम टर्मिनल्स	बीएमसीटी
1	वर्ष में प्रहस्तित कंटेनरों की संख्या	टीईयु में	544027	750978	779769	1668903	933154
		मिलियन टनों में	6.55	9.33	9.77	21.16	10.94
2	वर्ष में औसत सकल घाट प्रहस्तन	फेरे/ घंटे	55.33	67.76	101.05	91.13	81.13
3	वर्ष में प्रति जलयान घाट दिवस प्रहस्तन	टीईयु में	1783	2251	3106	3164	3268

रिपोर्टिंग अवधि (वित्त वर्ष 2020-21) में टर्मिनल निष्पादन के संकेतक दर्शाते है की औसत सकल घाट उत्पादकता 8.58 प्रतिशत घटी है, औसत क्रेन उत्पादकता 1.25 प्रतिशत से और प्रति जलयान घाटदिन औसत प्रहस्तन में टीईयु के संदर्भ में 7.7 प्रतिशत की कमी आयी है।

सारणी 7 : जनेप न्यास यातायात 2021

क्र.सं.		विवरण	इकाई	2020–21
1		कुल कंटेनर यातायात (जनेप न्यास)	टीईयु में	4676831
	1.क	जनेप कं.ट. की हिस्सेदारी	प्रतिशत में	11.63
2	2.क	कुल प्रहस्तित कार्गो (कुल यातायात)	मिलियन टनों में	64.81
		कंटेनरकृत कार्गो की हिस्सेदारी	प्रतिशत में	89.10
	2.ख	द्रव कार्गो की हिस्सेदारी	प्रतिशत में	9.49
	2.ग	शुष्क बल्क / विविध की हिस्सेदारी	प्रतिशत में	1.41
3		कुल यातायात	मिलियन टनों में	64.81
	3.क	आयात	मिलियन टनों में	34.54
	3.ख	निर्यात	मिलियन टनों में	28.83
	3.ग	यानांतरण	मिलियन टनों में	1.44

Port Modernization

Under improvement of infrastructure, JNPT created parking yards for undocumented export containers, facilitated infrastructure for Customs clearance in the Parking Yards, commenced the Centralized Parking Plaza project, and the widening of roads and other infrastructure projects.

	Development of Coastal berth	Development of Port-Based SEZ
New Infrastructure	To give momentum to coastal shipping, JNPT has taken up the project of Coastal Berth. Capacity for handling liquid cargo of 1.5 MTPA and General Coastal cargo of 1 MTPA.	In line with the objective of Port-led industrialization, a multi-product Special Economic Zone (SEZ) project was conceptualized by JNPT. The entire area of 277.38 Ha - processing area wherein manufacturing, logistics, warehousing, trading & services activities are permissible as per SEZ Acts & Rules. About 33 hectare (20% of leasable land) has been successfully allotted to 20 companies (19 MSME and 01 FTWZ-Warehousing).
Status	**Work completed in April 2021**	**Work completed in FY 2020-21 and Phase -1 Operationalized in June 2020**
Expected Benefits	Coastal berth development shall help in the decongestion of rail and road networks besides ensuring cost-competitive and effective multi-modal transportation solutions.	The project is likely to generate 4000 Cr of investment and provide direct and indirect jobs to 57000 thousand in the region once the JNPT SEZ is operationalized.

Development of Dry Ports at Jalna, Wardha, Nasik, and Sangli

JNPT has identified four potential sites for the development of Dry Ports at Wardha, Jalna, Nashik, and Sangli. The development of Wardha and Jalna Dry Ports is in the advanced stage, while that of Nashik Dry Port is in the planning stage, and development of Sangli Dry Port shall be considered in Phase II.

Jalna & Wardha are awaiting Environment Clearance (EC), Land acquisition has completed for Nashik and Land acquisition in process for Sangli

Boost in the hinterland traffic and strong presence of various manufacturing industries

Berthing facilities for Ro-Pax / Ro-Ro vessels at Shallow Water Berth: Roll-on/Roll-off (RO-RO or Ro-Pax)

Ro-Ro Vessels are cargo ships designed to carry wheeled cargo such as cars, trucks, semi-trailer trucks and trailers, that are driven on and off the ship on their wheels or using a platform, typically have a stern ramp and a side ramp for dual loading. Because of the above, it is essential to provide infrastructure to handle and operate Ro-Ro/Ro-Pax vessels at JNPT which can serve all coastal RO-Pax /Ro-Ro vessels up to 25m Beam and 170m LoA.

Work in Progress. (Expected completion by Feb 2022)

Reduction in transport cost and delivery time, direct delivery to Mumbai region avoiding the ware-house cost, new transport system to enhance and encourage coastal movement, and comfort travel for passengers.

Development of Integrated Common Rail Yard facility at JNPT

JNPT is developing an integrated Common Rail Yard Facility inside the Port to cater DFCC rake handling with DFC (Dedicated Freight Corridor) compliant yard including construction/modification of ROB (Road over Bridges) and additional Railway Track from Jasai to fourth Container Terminal to handle DFC rakes destined for other terminals namely JNPCT, NSICT, GTI & NSIGT.

Physical progress of 75% achieved

Cost advantage to the customers and enhance rail traffic

पत्तन आधुनिकीकरण

आधारभूत संरचनाओं में सुधार के तहत जनेप न्यास ने दस्तावेज रहित निर्यात कंटेनरों के लिए पार्किंग यार्ड बनाए, पार्किंग यार्ड में सीमा शुल्क निकासी के लिए सुविधा प्रदान की, केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा परियोजना शुरू की और सड़कों को चौड़ा करने के साथ-साथ अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं का कार्य किया ।

	तटीय घाट का विकास :	पत्तन आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास:
नई आधारभूत संरचना	तटीय नौवहन को गति देने के लिए जनेप न्यास ने तटीय घाट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना की क्षमता 1.5 एमटीपीए तरल कार्गो और 1 एमटीपीए सामान्य तटीय कार्गो का प्रहस्तन करने की होगी ।	पत्तन आधारित औद्योगीकरण उद्देश्य से जनेप न्यास द्वारा बहु-उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना की अवधारणा की गई थी। यह 277.38 हेक्टेयर का प्रसंस्करण क्षेत्र है जिसमें विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियमों और नियमों के अनुसार उत्पादन, लॉजेस्टिक, भंडारण, व्यापार और सेवा गतिविधियों की अनुमति है। लगभग 33 हेक्टेयर (पट्टे योग्य भूमि का 20%) 20 कंपनियों (19 एमएसएमई और 01 एफटीडब्ल्यूज़ेड-वेयरहाउसिंग) को सफलतापूर्वक आवंटित किया गया है।
स्थिति	**अप्रैल 2021 में कार्य पूरा किया गया।**	**वित्त वर्ष 2020-21 में कार्य पूरा हुआ और चरण-1 का कार्य जून 2020 में आरंभ हुआ ।**
अपेक्षित लाभ	तटीय घाट विकास लागत- प्रतिस्पर्धा और प्रभावी बहु-मोडल परिवहन समाधान सुनिश्चित करने के अलावा रेल और सड़क नेटवर्क के भीड़भाड़ को कम करने में मदद करेगा।	इस परियोजना से 4000 करोड़ का निवेश होने की संभावना है और जनेप न्यास विशेष आर्थिक क्षेत्र के चालू होने के बाद इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 57,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है।

जालना, वर्धा, नासिक और सांगली में शुष्क पत्तनों का विकास

जनेप न्यास ने वर्धा, जालना, नासिक और सांगली में शुष्क पत्तनों के विकास के लिए चार संभावित स्थलों की पहचान की है। वर्धा और जालना शुष्क पत्तन का विकास उन्नत चरण में है, जबकि नासिक शुष्क पत्तन का विकास योजना चरण में है, और चरण II में सांगली शुष्क पत्तन के विकास पर विचार किया जाएगा।

जालना और वर्धा शुष्क पत्तनों को पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की प्रतीक्षित है, नासिक के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया है और सांगली के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य प्रक्रियाधीन है।

आंतरिक यातायात में वृद्धि और विभिन्न उत्पादन उद्योगों को बढ़ावा

उथले जल घाट पर रो-पैक्स/रो-रो जलयानों के लिए घाटायन सुविधाएं: रोल-ऑन/रोल-ऑफ (आरओ-आरओ या रो-पैक्स):

रो-रो जलयान कार, ट्रक, सेमी-ट्रेलर ट्रक और ट्रेलर जैसे पहिएदार कार्गो को ले जाने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्गो जलयान हैं, जो अपने पहियों पर या प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जलयान पर आते और बाहर जाते हैं, आमतौर पर दोहरी लदाई के लिए स्टर्न रैंप और साइड रैंप होता है। उपरोक्त के कारण जनेप न्यास में रो-रो/रो-पैक्स जहाजों का प्रहस्तन और प्रचालन करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना आवश्यक है जिससे 25 मीटर ऊंचाई और 170 मीटर लंबाई तक के सभी तटीय आरओ-पैक्स/ रो-रो जलयानों का प्रहस्तन किया जा सके ।

कार्य प्रगति पर है। (फरवरी 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है)

परिवहन लागत और सुपुर्दगी समय में कमी, गोदाम लागत न करते हुए मुंबई क्षेत्र में सीधे सुपुर्दगी, तटीय आवाजाही को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए नई परिवहन व्यवस्था और यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा।

जनेप न्यास में एकीकृत सामान्य रेल यार्ड सुविधा का विकास:

जनेप न्यास डीएफसी (समर्पित फ्रेट कॉरिडोर) अनुपालन यार्ड के साथ डीएफसीसी रेक प्रहस्तन पूरा करने के लिए एकीकृत सामान्य रेल यार्ड सुविधा विकसित कर रहा है जिसमें उपरी पुल का निर्माण /मरम्मत और डीएफसी रेक के प्रहस्तन हेतु जेएनपीसीटी, एनएसआईसीटी, जीटीआई और एनएसआईजीटी जैसे अन्य टर्मिनलों के लिए जासई से चौथे कंटेनर टर्मिनल तक अतिरिक्त रेलवे ट्रैक शामिल है।

75 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है।

ग्राहकों को लागत में लाभ और रेल यातायात में वृद्धि

Ancillary Services

The Maritime India Vision (2030) has classified the ancillary services in terms of "common" and "differentiated" that shall improve the Port's performance. MIV 2030 guides the Indian ports to run selected cargo- and ship-related ancillary services according to the commodity profiles and business objectives.

One of the initiatives under MIV 2030 is to facilitate the Participating Government Agencies (PGAs) in their activities. These are allied agencies that examine and provide clearance to certain types and categories of cargo. These include Food Safety & Standards Authority of India (FSSAI), Controller of Drugs, Animal Quarantine, Plant Quarantine, Wildlife Crime Control Bureau (WCCB), and so on. In line with MIV 2030, JNPT has allotted office space / land to all the PGAs, thereby resulting in saving of at least 24 hours for both importers and exporters.

Ease of Doing Business, Traffic Management, and Digitization

JNPT is among the world's top 35 major container ports. Aligning its objectives with the ministry's directives, the Port has initiated activities under Ease of Doing Business, which include improvements in infrastructure, thereby resulting in monetary savings and reduced resource consumption. This was also reflected in World Bank's Ease of Doing Business Report 2020 where India's rank in trading across border improved from 80 in 2019 to 68 in 2020.

In order to improve the traffic management, JNPT simplified its processes as highlighted under simplification of processes and digitization.

सहायक सेवाएं

मैरीटाइम इंडिया विजन (2030) ने सहायक सेवाओं को "सामान्य" और "पृथक" सेवाओं में वर्गीकृत किया है जो पत्तन निष्पादन में सुधार करेगी। यह भारतीय पत्तनों को कमोडिटी प्रोफाइल और व्यावसायिक उद्देश्यों के आधार पर चयनित कार्गो और जलयान से संबंधित सहायक सेवाओं को स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करता है।

मैरीटाइम इंडिया विजन (2030) के तहत की गई पहलों में से एक पहल भाग लेनेवाली सरकारी एजेंसियों को उनकी गतिविधियों में सुविधा प्रदान करना है। यह वो संबद्ध एजेंसियां हैं जिन्हें कार्गो के कुछ प्रकार/श्रेणियों की जांच करने और उन्हें मंजूरी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इनमें भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, औषधि नियंत्रक, पशु संगरोध, वनस्पति संगरोध, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो आदि शामिल हैं। विजन के अनुरूप, जनेप न्यास ने सभी भाग लेनेवाली सरकारी एजेंसियों को कार्यालय स्थान/भूमि आवंटित की है जिसके परिणामस्वरूप आयातकों और निर्यातकों दोनों के लिए कम से कम 24 घंटे की बचत होती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यातायात प्रबंधन और डिजिटाइजेशन

जनेप न्यास वैश्विक स्तर पर शीर्ष 35 प्रमुख कंटेनर पत्तनों में से एक है। मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप, पत्तन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत गतिविधियां शुरू की हैं जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप मौद्रिक बचत और संसाधन खपत में कमी आई है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भी यही परिलक्षित हुआ था- जहां सीमा पार व्यापार में वर्ष 2019 में भारत का स्थान में 80 से बढ़कर 2020 में 68 हो गया।

यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए- प्रक्रिया सरलीकरण और डिजिटलीकरण के अधीन दर्शाए गए जनेप न्यास ने प्रक्रिया को सरल बनाया ।

Simplification of Processes

Under the simplification of its processes, the Port commenced inter-terminal movements and dispensed the seal checking by CISF at the Gate. The Port also focused on increasing the Direct Port Deliveries (DPDs) and Direct Port Entry (DPE) services.

	Inter-Terminal Transfer of Tractor Trailers	**Direct Port Delivery (DPD)**
Initiatives	This facility is used by approx. 300–400 tractor trailers every day. It saves about 7.5 km of distance per truck	This was implemented with the objective to expedite the delivery of import containers and reduce the cost of the transaction. It facilitates the delivery of a container directly from the terminal without going through the conventional steps of transferring to a container freight station (CFS) where the customs procedures are carried out and the container is given "out of charge", thereby saving not just the costs for transportation and handling at container freight stations (CFSs) but also the time in delivery of the consignment
Benefits	Reduced the load off the road. Further, it led to saving of logistics cost to trade since the commencement of the facility besides minimizing congestion; Till the end of FY2020-21, 1,014,701 trucks availed this facility by making 1,278,519 transactions	Facility of DPD well received by trade; percentage of containers cleared under DPD grew from 3% to 59.74% during FY2020–21

Direct Port Entry (DPE)

This facility was created for exporters to bring in the containers directly to the port instead of routing them through CFSs. Every factory stuff container was earlier required to go to a CFS to get customs' approval and then proceed to the terminal gates. The conversion of parking yards to customs processing areas, and the facilitation of customs operation led to a higher percentage of DPE

Exporters benefit immensely through savings in cost. DPE for FY2020–21 is 47.63%

ITRHO

After the commencement of the new terminal of PSA (BMCT), operational issues arose in the handling of mixed trains, i.e., those carrying containers for more than one terminal as BMCT is 5.5 km away from the existing port terminals. In order to solve such issues, JN Port made a determined effort to put in place a new ITRHO agreement by drafting and framing operational procedures and cost calculations acceptable to all the terminals including BMCT and NSIGT

Average monthly dwell time of rail containers reduced by 54.86% from 94.16 hours in FY2018–19 to 42.50 hours in FY2019–20, and 41.90 hours in FY2020–21

E-Marketplace Transport Solution for JNPT

JNPT issued the permit to operate Transport Solution for optimum utilization of tractor-trailer movements and infrastructure to eliminate inefficiencies by reducing empty trailer movements between the Port and CFSs, reducing empty container movements in the hinterland, and minimizing trucks' idling time for the fleet owners, thereby ensuring trucks' availability for trade operations

Transport Solution helped the Port reduce import dwell time of road bound containers from 30.35 hours in FY2018–19 to 21.80 hours in FY2020-21; and the overall import dwell time declined from 33.75 hours in FY2018–19 to 24.60 hours in FY2020-21.

प्रक्रियाओं का सरलीकरण

प्रक्रिया के सरलीकरण के तहत, पत्तन ने अंतर-टर्मिनल संचलन की शुरुआत की और प्रवेश द्वार पर के.औ.सु.बल द्वारा सील जांच को समाप्त कर दिया। पत्तन ने सीधे पत्तन सुपुर्दगी और सीधे पत्तन प्रवेश को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया।

	ट्रैक्टर ट्रेलरों का अंतर टर्मिनल स्थानांतरण :	सीधे पत्तन सुपुर्दगी :
कार्यक्रम	यह सुविधा हर दिन 300-400 ट्रैक्टर ट्रेलरों द्वारा अधिकतम उपयोग की जाती है। । इससे प्रति ट्रक लगभग 7.5 किमी की दूरी कम हुई है।	सीधे पत्तन सुपुर्दगी को आयात कंटेनरों की सुपुर्दगी में तेजी लाने और लेनदेन की लागत को कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। यह कंटेनर फ्रेट स्टेशनों को स्थानांतरित करने के पारंपरिक प्रक्रिया के बिना सीधे टर्मिनल से कंटेनर की सुपुर्दगी की सुविधा प्रदान करता है जहां सीमा शुल्क प्रक्रियाएं की जाती हैं और कंटेनर को 'आउट ऑफ चार्ज' दिया जाता है, इस तरह सीएफएस में परिवहन और प्रहस्तन के लागत में और साथ ही माल सुपुर्दगी के समय में भी बचत हो रही है।
फायदे	सड़क पर की भीड़ कम हुई इसके अलावा यह सुविधा आरंभ होने के बाद से व्यापार परिवहन लागत में बचत हुई है और भीड़ में कमी आयी है। वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक 1,014,701 ट्रकों ने 1,278,519 लेनदेन कर इस सुविधा का लाभ उठाया।	सीधे पत्तन सुपुर्दगी सुविधा व्यापार में अच्छी तरह से अपनायी गई है और सीधे पत्तन सुपुर्दगी के तहत सुपुर्द किए गए कंटेनरों का प्रतिशत वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र 3% से बढ़कर 59.74% हो गया है।

सीधे पत्तन सुपुर्दगी:

सीधे पत्तन सुपुर्दगी,निर्यातकों के लिए सीएफएस के बजाय कंटेनरों को सीधे पत्तन में लाने के लिए बनाई गई सुविधा है। हर भरे हुए कंटेनर को पहले सीमा शुल्क अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सीएफएस में जाना पड़ता था और फिर टर्मिनल गेट्स पर जाना पड़ता था। पार्किंग यार्ड को सीमा शुल्क प्रसंस्करण क्षेत्र के रूप में बदलने और सीमा शुल्क प्रचालन सुविधा के कारण सीधे पत्तन सुपुर्दगी का प्रमाण बढ़ा है।

निर्यातकों को वर्तमान में लागत में बचत का लाभ मिल रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 (अप्रैल से मार्च) में सीधे पत्तन सुपुर्दगी 47.63 प्रतिशत हुई है।

आईटीआरएचओ :

पीएसए (बीएमसीटी) नया टर्मिनल के आरंभ के बाद, मिश्रित ट्रेनों के प्रहस्तन में प्रचालनीय समस्याएं उत्पन्न हुई उदा. एक से अधिक टर्मिनल में कंटेनर ले जाने वाली ट्रेनें मौजूदा पत्तन टर्मिनलों से 5.5 किमी दूर हैं। इन मामलों को हल करने के लिए जने पत्तन ने बीएमसीटी और एनएसआईजीटी सहित सभी टर्मिनलों के लिए प्रचालनीय प्रक्रियाओं और लागत गणनाओं का मसौदा तैयार करके और नया आईटीआरएचओ समझौता करने के लिए एक दृढ़ प्रयास किया।

रेल कंटेनरों का औसत मासिक विराम समय में 54.86 प्रतिशत की कमी आयी है। वित्त वर्ष 2018-19 में 94.16 घंटों से घटकर वित्त वर्ष 2019-20 में 42.50 घंटे हो गया और वित्त वर्ष 2020-21 में 41.90 घंटे तक कमी आयी।

जनेप न्यास के लिए ई-बाजार परिवहन समाधान:

जनेप न्यास ने पत्तन और सीएफएस के बीच खाली ट्रेलर संचलन कम करके, भीतरी इलाकों में खाली कंटेनर संचलन को कम करके, और बेड़े के मालिकों के लिए ट्रक विराम समय को कम करके कमियों को दूर करने के लिए ट्रैक्टर-ट्रेलर संचलन और बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग के लिए परिवहन समाधान प्रचालित करने के लिए परमिट जारी किया है जिससे व्यापार प्रचालनों के लिए ट्रकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

परिवहन समाधान से पत्तन को सड़क से आनेवाले कंटेनरों के विराम समय में वित्त वर्ष 2018-19 में 30.35 घंटे से वर्ष 2020-2021 में 21.80 घंटे तक कमी आयी और कुल आयात विराम समय में वित्त वर्ष 2018-19 में 33.75 घंटे से वर्ष 2020-2021 में 24.60 घंटे तक कमी आयी है।

Digitization

Under digitization, the following initiatives have been undertaken:

1 Introduction of E-Form 13/Form 11

Form 13 and Form 11 are the documents by which the entry of containers in the terminals is regulated. E-Form 13 and E-Form 11 have been introduced to reduce gate transaction time and avoid manual data feeding by customers.

2 Container tracking introduced for the first time in India

JNPT, in association with DMIDC, has commenced the tracking of containers moving towards and cleared from JNPT terminals. Transit integrity is now ensured by tracking containers. The importers/ exporters are able to keep track of their containers while in transit. The system provides a Data Bank on Destination-Source matrix for containers in transit in India.

3 E-delivery orders

In a major initiative to bring in ease of delivery of import containers, a PCS-driven e-DO module developed by IPA was introduced and currently, all major shipping lines are availing this mode. The e-DO facilitates quick and easier delivery, and tends to reduce the cost and time in the import supply chain. Presently, e-DO is transmitted through upgraded PCS, i.e., PCS 1x.

4 Upgradation of PCS System

PCS 1x (an upgraded version of PCS) was launched on 11 December 2018, which enables all stakeholders to exchange data / transactions on the PCS 1x platform on a real-time basis. It offers a database that acts as a single data point for all transactions. This upgraded single window platform intends to integrate 27 maritime stakeholders on a common platform, including ICEGATE, DGFT, and TOS. Currently, 26 stakeholders are on board in the PCS 1x system.

PCS 1x has provided one communication platform for all maritime stakeholders which has reduced the time and overall cost for documentary and border compliance for imports and exports by eliminating unnecessary duplication of activities on different portals.

5 Upgradation of Navis system with Navis N4 terminal operating system

JNPCT upgraded its terminal operating system (TOS) to Navis SPARCS N4, which is the next generation TOS, specifically designed to offer unparalleled value and grow with the customer at the lowest possible total cost of ownership (TCO).

डिजिटाइजेशन :

डिजिटलीकरण के अंतर्गत निम्न प्रयास किए गए हैं:

1 ई- प्रपत्र 13/ प्रपत्र 11 का आरंभ

प्रपत्र 13 और प्रपत्र 11 ऐसे दस्तावेज हैं जिनके द्वारा टर्मिनलों में कंटेनरों के प्रवेश को विनियमित किया जाता है। प्रवेश द्वारा पर लेनदेन समय को कम करने और ग्राहकों द्वारा मैन्युअल डेटा फीडिंग से बचने के लिए प्रपत्र 13 और प्रपत्र 11 का आरंभ किया गया है।

2 भारत में पहली बार कंटेनर ट्रैकिंग शुरु की गई

जनेप न्यास ने डीएमआईडीसी के सहयोग से जनेप न्यास टर्मिनलों की ओर जाने वाले और क्लियर किए गए कंटेनरों की ट्रैकिंग शुरु की। कंटेनरों को ट्रैक करके पारगमन सत्यता सुनिश्चित की जाती है। आयातक/ निर्यातक अब पारगमन के दौरान कंटेनर का ट्रैक रखने में सक्षम हैं। यह प्रणाली भारत में पारगमन में कंटेनरों के लिए गंतव्य-स्रोत मैट्रिक्स पर डेटा बैंक प्रदान करती है।

3 ई-सुपुर्दगी आदेश

आयात कंटेनरों की सुपुर्दगी में आसानी लाने के लिए की गई प्रमुख पहल में, आईपीए द्वारा विकसित पीसीएस संचालित ई-डू मॉड्यूल पेश किया गया था और वर्तमान में सभी प्रमुख शिपिंग लाइनें इस का उपयोग कर रही हैं। ई-डू शीघ्र और आसान सुपुर्दगी की सुविधा देता है और आयात आपूर्ति श्रृंखला में लागत और समय को कम करता है। वर्तमान में ई-डू को उन्नत पीसीएस यानी पीसीएस 1x के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।

4 पीसीएस प्रणाली का उन्नयन:

पीसीएस 1x (पीसीएस का एक उन्नत संस्करण) को दिनांक 11 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया जो सभी भागधारकों को वास्तविक समय के आधार पर पीसीएस 1x प्लेटफॉर्म पर डेटा / लेनदेन का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह एक डेटाबेस प्रदान करता है जो सभी लेनदेन के लिए एकल डेटा बिंदु के रुप में कार्य करता है। यह अद्यतन सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म 27 मैरिटाइम भागधारकों को एक साझा मंच प्रदान करता है, जिसमें ICEGATE, DGFT और TOS भी शामिल हैं। वर्तमान में 26 हितधारक पीसीएस 1x प्रणाली में शामिल हैं।

पीसीएस 1x ने सभी मैरिटाइम भागधारकों के लिए एक संपर्क मंच प्रदान किया है जिसने विभिन्न पोर्टलों पर गतिविधियों के अनावश्यक पुनरावृति को समाप्त करके आयात और निर्यात के दस्तावेजी और सीमा अनुपालन के समय और समग्र लागत को कम कर दिया है।

5 नेविस एन4 टर्मिनल प्रचालन प्रणाली के साथ नेविस प्रणाली का उन्नयन:

जनेप कंट ने टर्मिनल प्रचालन प्रणाली को नेविस स्पर्क्स एन4 में उन्नयन किया, जो कि अगली पीढ़ी की टर्मिनल प्रचालन प्रणाली है, जिसे बेजोड़ मूल्य प्रदान करने और स्वामित्व की न्यूनतम संभावित लागत पर ग्राहक के साथ आगे बढ़ने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।

ENVIRONMENT MANAGEMENT

पर्यावरण प्रबंधन

Environment Management

Environmental Impact

Air Quality

JNPT is conscious of the emissions from land and sea-based sources which contribute to increasing pollution levels in the port areas due to terminal activities. As part of its commitment to maintain air quality and adhering to its Environmental Management and Monitoring Plan (EMMP), JNPT conducts environmental sampling and analysis of ambient air, marine water, marine ecology, drinking water, sewage quality, noise levels arising out of port operations with the help of IIT Madras. Under the initiative, IIT Madras has established an environmental monitoring laboratory at JNPT township and an online real-time air monitoring set-up on the port premises. JNPT strives to ensure that the ambient air quality at JN Port areas is within the CPCB-prescribed permissible limits. The 24-hour average concentrations of PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, and NO_2, and other parameters are measured regularly at eight locations using high volume samplers (Figure 15).

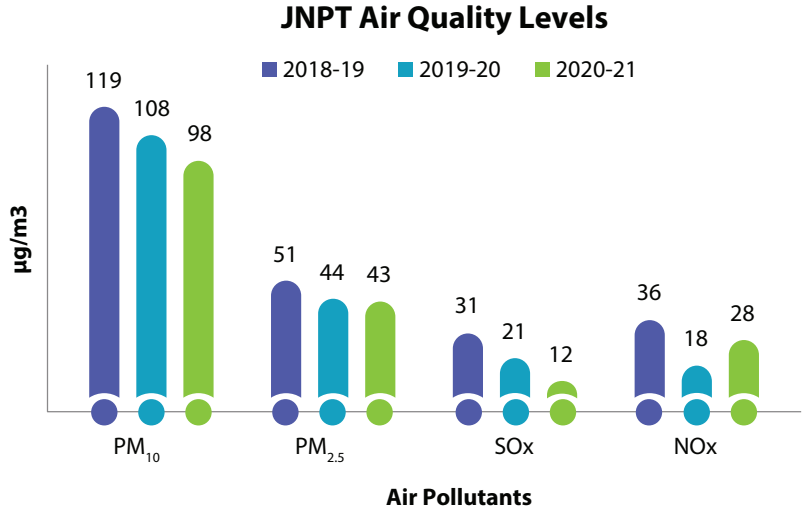

Figure 15: Air quality levels

Detailed monthly environmental monitoring reports are available on the JNPT website.

For FY2018–19 and FY2019–20, it may be noted that the PM_{10} values are above the CPCB-prescribed permissible limits. JNPT has been implementing several initiatives in alignment with the Green Ports Initiative to address this issue beginning FY2017–18.

पर्यावरण प्रबंधन

पर्यावरणीय प्रभाव

वायु गुणवत्ता

जनेप न्यास भूमि और समुद्र आधारित स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन के प्रति सजग है; जो टर्मिनल गतिविधियों के कारण पत्तन क्षेत्र में प्रदूषण के लिए वजह बने है । वायु गुणवत्ता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप और पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना का अनुपालन करने हेतु जनेप न्यास आयआयटी-मद्रास के माध्यम से परिवेशी वायु, समुद्री जल, समुद्री पारिस्थितिकी, पीने का पानी, मलजल गुणवत्ता, पत्तन प्रचालन के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि स्तर आदि के नमूनों का संकलन करता है और उनका विश्लेषण करता है। हरित पहल के तहत आयआयटी मद्रास ने जनेप न्यास नगर क्षेत्र में एक पर्यावरण निगरानी प्रयोगशाला के साथ-साथ पत्तन क्षेत्र में ऑनलाइन वास्तविक समय वायु निगरानी सयंत्र स्थापित किया है। जनेप न्यास यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि जन पत्तन क्षेत्र में परिवेशी वायु की गुणवत्ता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित अनुमत सीमा के भीतर है। PM10, PM2.5, SO2 और NO2 और अन्य मापदंडों की 24-घंटे की औसत सांद्रता को पत्तन क्षेत्र के आठ स्थानों पर नियमित रूप से उच्च मात्रा के नमूनों का उपयोग करके मापा जाता है (चित्र 15) ।

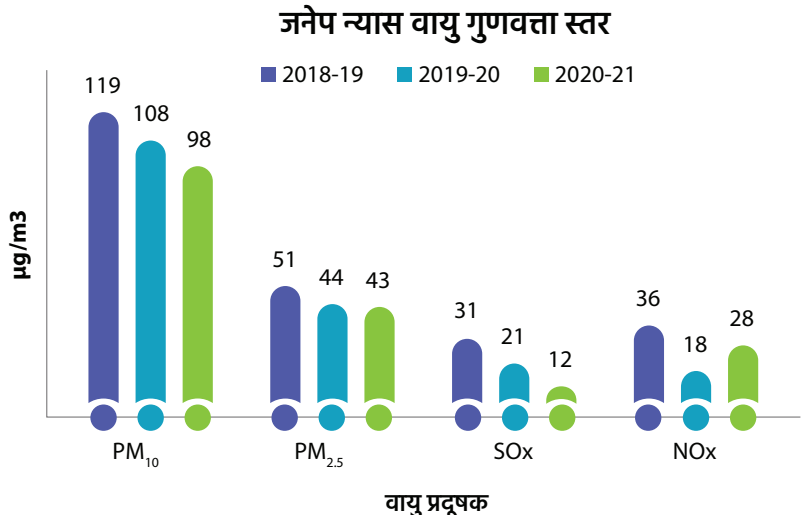

चित्र 15 : वायु गुणवत्ता स्तर

जनेप न्यास की वेबसाइट पर विस्तृत मासिक पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में यह देखा गया है कि PM_{10} की मात्रा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा निर्धारित अनुमत सीमा से अधिक है। जनेप न्यास इस मामले को हल करने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 से बनाई गई योजना के तहत हरित पत्तन पहल के साथ कई पहलों को लागू कर रहा है।

These include the following:

- Maintaining a wide expanse of green zone
- Initiated Inter-Terminal Transfer (ITT) of tractor-trailers
- JNPT has switched from diesel to electrically powered e-RTGCs which also help in cost saving
- Periodic cleaning of paved and unpaved roads, and
- Use of tarpaulin sheets to cover dumpers at project sites

The success of these initiatives has resulted in the reduction of PM10 levels bringing them within the permissible limits in FY2020–21. JNPT conducts environmental sampling and analysis of ambient air, marine water, marine ecology, drinking water, sewage quality, noise levels through IIT Madras. Under the initiative, IIT Madras has established an environmental monitoring laboratory at JNPT township and an online real-time air monitoring set-up at Port Operation Centre.

Planned actions by JNPT:

In accordance with Maritime India Vision 2030, the following initiatives have been identified to be undertaken by the major ports in India, including JNPT, in order to improve air quality:

Sr. No.	Initiative	Proposed Recommendations	Planned Activities by JNPT
1.	Clean Fuels to Reduce Vehicle Emissions at Ports	Indian ports shall look to achieve 50% vehicle switch towards cleaner fuels – CNG, LNG, and Electricity by 2030	JNPT is exploring the feasibility of using bio-diesel for RTGCs
2.	Reducing Air Emissions by Ships Inside Port Ecosystem	Ports shall mandate and adopt current SOPs of providing shore power to all vessels up to 150 KW. For other vessels rated above 150 KW or working on 60 Hz power supply, ports shall adopt a 3-phase targeted approach	Project for providing shore power to all ships is in conceptual stage
3.	Port Equipment Electrification	Indian ports shall drive a 2-phased pan-India electrification programme aimed to achieve more than 50% electrified material handling equipment by 2030	JNPT has already hired 09 nos. electrically operated light motor vehicles for internal movement
4.	LNG Bunkering	Indian ports shall aim to increase adoption of LNG to reduce carbon footprint and greenhouse gas emissions. Indian ports shall adopt a 3-phased approach to increase the adoption of LNG with bunkering facilities in next 5-10 years	Market assessment has been carried out for LNG bunkering facilities
5.	Dust Emissions Management	Indian ports shall deploy a dust emission management programme leveraging sensor-based tracking technology	Port has commissioned Real Time Continuous Ambient Air Quality Monitoring for tracking air quality Fine aerosol dust particles are identified by IIT Madras using Dust Track to find the level of dust deposition. In future, vehicle dust emission will also be calculated as part of research activities

इसमे निम्नलिखित शामिल है :

- हरित क्षेत्र का व्यापक विस्तार बनाए रखना
- ट्रैक्टर-ट्रेलरों का अंतर-टर्मिनल स्थानांतरण आरंभ किया गया,
- जनेप न्यास ने डीजल पर चलने वाले वाहनों को बिजली से चलने वाले ई-आरटीजीसी वाहनों में परिवर्तित किया है जिससे लागत में बचत हो रही है
- पक्की और कच्ची सड़कों की समय-समय पर सफाई, और
- परियोजना स्थलों पर डंपरों को ढकने के लिए तिरपाल शीट का उपयोग

जने पत्तन द्वारा उठाए गए कदमों की सफलता के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020-21 में PM10 के स्तर को अनुमत सीमा के अंदर लाने में सफलता मिली है । जनेप न्यास आईआईटी मद्रास के माध्यम से परिवेशी वायु, समुद्री जल, समुद्री पारिस्थितिकी, पेयजल, मलजल गुणवत्ता, ध्वनि स्तर के नमूने संकलित करता है और उनकी जांच करता है। इस पहल के तहत, आईआईटी मद्रास ने जनेप न्यास नगर क्षेत्र में पर्यावरण निगरानी प्रयोगशाला और पत्तन प्रचालन केंद्र में ऑनलाइन वास्तविक समय वायु अनुवीक्षण सयंत्र स्थापित किया है।

जनेप न्यास द्वारा नियोजित कार्य:

मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुसार, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जनेप न्यास सहित भारत के प्रमुख पत्तनों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाएँ जाएँगे :

क्र.सं.	पहल	प्रस्तावित सिफारिशें	जनेप न्यास द्वारा नियोजित गतिविधियां
1.	पत्तनों में वाहन उत्सर्जन कम करने हेतु स्वच्छ ईंधन	भारतीय पत्तनों को 2030 तक 50 प्रतिशत वाहन को सीएनजी, एलएनजी और बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन देने का लक्ष्य करना होगा।	जनेप न्यास आरटीजीसी के लिए बायो-डीजल का उपयोग करने की व्यवहार्यता खोज रहा है।
2.	पत्तन क्षेत्र में जलयानों द्वारा वायु उत्सर्जन को कम करना	पत्तनों को 150 किलोवाट तक के सभी जलयानों को बिजली प्रदान करने के वर्तमान एसओपी को अनिवार्यरूप से अपनाना होगा। 150KW से ऊपर की रेटिंग वाले या 60Hz बिजली आपूर्ति पर काम करने वाले अन्य जलयानों के लिए पत्तनों को तीसरे चरण में लक्षित दृष्टिकोण अपनाना होगा।	सभी जलयानों को तट पर बिजली प्रदान करने की परियोजना पर विचार किया जा रहा है।
3.	पत्तन उपकरणों का विद्युतीकरण	भारतीय पत्तन 2030 तक सामग्री प्रहस्तन उपकरण 50% से अधिक विद्युतीकृत करने के उद्देश्य से दूसरे चरण में अखिल भारतीय विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाएंगे,	जनेप न्यास ने अपने आंतरिक संचालन के लिए 9 विद्युत संचालित हल्के मोटर वाहन किराए पर लिए है।
4.	एलएनजी बंकरिंग	भारतीय पत्तनों का लक्ष्य कार्बन फुटप्रिंट और ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए एलएनजी को अपनाना होगा। भारतीय पत्तन अगले 5-10 वर्षों में बंकरिंग सुविधाओं के साथ एलएनजी को अपनाने के लिए 3-चरणीय दृष्टिकोण अपनाएंगे।	एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं के लिए बाजार मूल्यांकन किया गया है।
5.	धूल उत्सर्जन प्रबंधन	पत्तन ने वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए वास्तविक समय निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी आरंभ की है।	धूल के जमाव के स्तर का पता लगाने के लिए धूल ट्रैक का उपयोग करके आईआईटी मद्रास द्वारा महीन एरोसोल धूल कणों की पहचान की जाती है। भविष्य में, वाहन धूल उत्सर्जन की गणना भी अनुसंधान गतिविधियों के एक भाग के रूप में की जाएगी।

Water Management

On the one hand, the port industry contributes to maritime transport, trade, and socio-economic growth; on the other, it can have significant adverse effects on the local environment and the local community. The port activities and ship movement can considerably impact the water resources and water quality.

The water quality gets affected on account of terminal operations, infrastructure development, discharge of effluents, ship waste, cargo residue, waste discharges, and so on. As cited in the Maritime India Vision 2030, activities such as deck cleaning, cargo transfer, movement of ships, dredging, reclamation, and oil spillages lead to sediment suspension, thereby resulting in poor surface and groundwater quality. Substantial amounts of freshwater are consumed in port operations through activities such as gardening and landscaping, drinking water consumption, domestic water consumption in the township, greenbelt development and maintenance, and so on.

Mumbai is one of the water-stressed cities in India. On the issue of water resources, the State Action Plan on Climate Change of Maharashtra recommends the implementation of measures for the: a) enhancement of water storage and groundwater recharge, and b) improvement of water-use efficiency.

JNPT is continuously striving towards reducing its demand for freshwater consumption for port operations and integrating reuse and recycling measures in its environmental management strategy. This approach will not only reduce the Port's dependence on current drinking water service provider, but also help in saving costs in the long run. JNPT is managing and monitoring the marine waters as well as its freshwater requirements as part of its Environmental Management and Monitoring Plan.

For water catchment management, waterbodies at four locations within the port premises have been identified for rejuvenation and carrying out desiltation in order to improve the groundwater table level, maintain greenery and availability of water for birds and animals in the port estate. The rejuvenation of all four water reservoirs is scheduled to be completed by FY2023.

Water quality

To combat oil spills at JNPT and MbPT harbour, a common Oil Spill Tier-I facility was commissioned in 2015 at Jawahar Dweep, Mumbai Port Trust. The facility is managed by a third party with Mumbai Port Trust acting as the nodal agency. In line with the goal of developing a robust oil spill response plan as outlined in MIV 2030, JNPT has already updated its Local Oil Spill Disaster Contingency Plan. The Plan has been approved by the Coast Guard Regional Headquarter and has subsequently been forwarded to Coast Guard HQ, Delhi for vetting. In order to combat minor local oil spills at JNPT, a multipurpose utility launch has been hired on chartered basis.

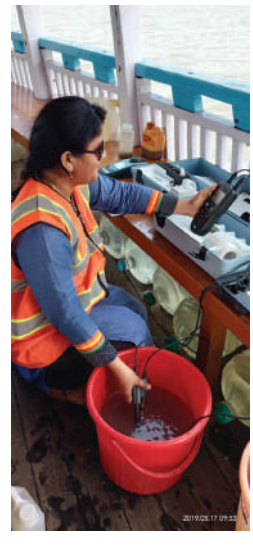

जल प्रबंधन

जहां एक ओर पत्तन उद्योग समुद्री परिवहन, व्यापार और सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है; दूसरी ओर यह स्थानीय पर्यावरण और क्षेत्र पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। पत्तन गतिविधियाँ और जलयान की आवाजाही जल संसाधनों और पानी की गुणवत्ता को काफी प्रभावित कर सकती है।

टर्मिनल प्रचालन, बुनियादी ढांचे का विकास, अपशिष्टों के निर्वहन, जलयान के अपशिष्ट, कार्गो अवशेष, अपशिष्ट निर्वहन, आदि के कारण पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जैसा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में उद्धृत किया गया है, डेक की सफाई, कार्गो स्थानांतरण, जलयानों की आवाजाही, निकर्षण, भूमि सुधार और तेल रिसाव जैसी गतिविधियों से तलछट बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप सतह और भूजल गुणवत्ता खराब होती है। बागवानी और भूनिर्माण, पीने के पानी की खपत, नगरक्षेत्र में घरेलू पानी की खपत, हरित पट्टे का विकास और रखरखाव जैसी गतिविधियों के माध्यम से पत्तन प्रचालन में अधिक मात्रा में ताजे पानी की खपत होती है।

मुंबई भारत के जल की कमी रहने वाले शहरों में से एक है। जल संसाधनों के मुद्दे पर, महाराष्ट्र की जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन की सिफारिश करती है: क) जल भंडारण और भूजल पुनर्भरण में वृद्धि, और ख) जल उपयोग दक्षता में सुधार।

जनेप न्यास पत्तन, प्रचालन हेतु मीठे पानी की खपत की अपनी मांग को कम करने और पर्यावरण प्रबंधन रणनीति में पुन: उपयोग और पुर्नप्रयोग उपायों को एकीकृत करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। यह दृष्टिकोण न केवल वर्तमान पेयजल सेवा प्रदाता पर पत्तन की निर्भरता को कम करेगा, बल्कि लंबे समय में लागत बचाने में भी मदद करेगा। जनेप न्यास अपने पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना के हिस्से के रूप में समुद्री जल के साथ-साथ मीठे पानी की आवश्यकताओं का प्रबंधन और निगरानी कर रहा है।

जलग्रहण प्रबंधन के लिए, पत्तन क्षेत्र के भीतर चार स्थानों पर जल निकायों की पहचान की गई है, ताकि भूजल स्तर में सुधार, हरियाली बनाए रखने और पत्तन संपदा में पक्षियों और जानवरों के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। सभी चार जलाशयों का कायाकल्प वित्त वर्ष 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

जल गुणवत्ता

जनेप न्यास और मुंबई पत्तन न्यास में तेल रिसाव से निपटने के लिए, जवाहर द्वीप, मुंबई पत्तन न्यास में 2015 में एक सामान्य तेल रिसाव टियर- I सुविधा शुरू की गई थी। इस सुविधा का प्रबंधन तीसरे पक्ष द्वारा किया जाता है, जिसमें मुंबई पत्तन न्यास नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में उल्लिखित एक मजबूत तेल रिसाव प्रतिक्रिया योजना विकसित करने के लक्ष्य के अनुरूप, जनेप न्यास ने अपनी स्थानीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना को पहले ही अद्यतन कर दिया है। योजना को तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है और बाद में इसे तटरक्षक मुख्यालय, दिल्ली को पुनरीक्षण के लिए भेज दिया गया है। जनेप न्यास में मामूली स्थानीय तेल रिसाव से निपटने के लिए, चार्टर्ड आधार पर एक बहुउद्देशीय उपयोगिता लॉन्च को किराए पर लिया गया है।

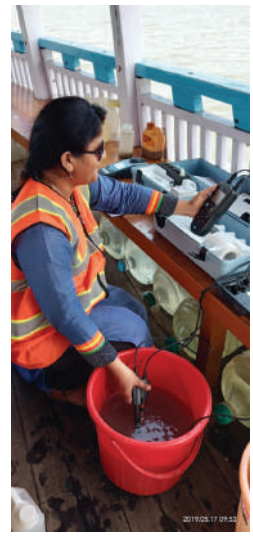

Water consumption

JNPT is continuously striving to reduce its freshwater requirements by bringing about improvements in water-use efficiency and increasing the use of treated wastewater from port operations.

JNPT's water supply scheme is designed for 15 MLD water demand for the JNPT area and JNPT township, combined. Currently, water is being supplied to JNPT township through tap system from City and Industrial Development Corporation (CIDCO), Maharashtra. The water requirement at JNPT port area has been constant at 8.0 MLD in the last three years from FY2018–19 through FY2020–21.

Wastewater Management

Towards achieving the goal of leading the world in safe, sustainable, and green maritime sector, as outlined in the MIV 2030 document, JNPT is working on building the required infrastructure (sewage treatment plant, hull cleaning) for sewage wastewater and oily waste treatment. Another proposal for developing the infrastructure worth ₹ 1.5 crore for wastewater treatment and recycling of treated water is in the pipeline with the work envisaged to commence in the last quarter of FY2021–22.

The installation of a Sewage Treatment Plant (STP) of 4.0 MLD capacity at JNPT township and a 6.5 MLD capacity STP at JNPT SEZ was completed by the end of FY2020–21. The treated water from the township STP is proposed to be utilized for gardening purposes. The STP at JNPT township is expected to start functioning from FY 2021–22. The STP established in the SEZ is expected to start functioning by 2022 once the SEZ operations begin.

Waste Management

Solid waste and hazardous waste management

JNPT recognizes the negative impacts that improper handling of waste has on the environment, especially its potential impact on vulnerable marine ecosystems. In alignment with the Government of India's various initiatives such as the Swachh Bharat Mission, Sagarmala Project, and the Maritime Vision 2030, JNPT has been consciously taking steps and implementing measures to ensure that waste management is carried out in an efficient and effective manner.

The Maritime India Vision 2030 and the Green Ports Initiative stress upon the need for major ports to address waste management issues in port areas. In this regard, JNPT has undertaken several initiatives for the establishment of waste management facilities.

JNPT Township: Solid Waste Management Project

In February 2021, the Port inaugurated a comprehensive Solid Waste Management Project in JNPT township. The 10 MT/day Solid Waste Management facility has been designed as per Solid Waste Management Rules, 2016 (MoEFCC, GoI), and is based on BARC (Bhabha Atomic Research Centre) technology. The facility comprises a 5 MT/day plant which utilizes biogas for power generation, hydraulic baling press machine for compression of dry waste, and facility for segregating collected dry and wet waste. The facility is intended for port users, port township, and the villages within the port estate.

जल उपभोग

जनेप न्यास जल-उपयोग दक्षता में सुधार लाकर और पत्तन प्रचालन से उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को बढ़ाकर अपनी मीठे पानी की आवश्यकताओं को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

जनेप न्यास क्षेत्र और नगरक्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से 15 एमएलडी पानी की मांग के लिए जनेप न्यास की जलापूर्ति योजना तैयार की गई है। वर्तमान में शहर और औद्योगिक विकास निगम (सिडको), महाराष्ट्र नल प्रणाली के माध्यम से जनेप न्यास नगरक्षेत्र को जल आपूर्ति की जाती है। वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 तक पिछले तीन वर्षों से जनेप न्यास पत्तन क्षेत्र में पानी की आवश्यकता 8.0 एमएलडी पर स्थिर रही है।

अपशिष्ट जल प्रबंधन

मैरीटाइम इंडिया विजन में स्पष्ट किए गए अनुसार सुरक्षित, स्थिर और हरित समुद्री क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनेप न्यास मलजल अपशिष्ट जल और तैलीय अपशिष्ट पर अभिक्रिया करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे (जलमल उपचार संयंत्र, हल की सफाई) के निर्माण पर काम कर रहा है। अपशिष्ट जल अभिक्रिया और उपचारित जल के पुर्नप्रयोग के लिए रु.1.5 करोड़ से अधिक की मूलभूत सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव विचारधीन है, जिसका कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम तिमाही में आरंभ किया जाना पूर्वानुमानित है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक जनेप न्यास नगरक्षेत्र में 4.0 एमएलडी क्षमता का जलमल अभिक्रिया संयंत्र और जनेप न्यास विशेष आर्थिक क्षेत्र में 6.5 एमएलडी क्षमता का जलमल अभिक्रिया संयंत्र का संस्थापन किया गया । नगरक्षेत्र जलमल अभिक्रिया संयंत्र से अभिक्रिया किए गए जल का उपयोग बागवानी के लिए किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जनेप न्यास नगरक्षेत्र में जलमल अभिक्रिया संयंत्र का कार्य आरंभ होना अपेक्षित है। विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्रचालन आरंभ होने के बाद विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित जलमल अभिक्रिया संयंत्र वर्ष 2022 तक आरंभ होना अपेक्षित है । होगा।

अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

जनेप न्यास ने अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन के कारण पर्यावरण पर होनेवाले नकारात्मक प्रभावों, विशेष रूप से सामुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र पर इसके संभावित प्रभावों की पहचान की है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, सागरमाला परियोजना और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुरूप जनेप न्यास सजगतापूर्वक कदम उठा रहा है और अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य कुशल और प्रभावी तरीके किया जाना सुनिश्चित करने के उपायों को लागू कर रहा है।

प्रमुख पत्तनों द्वारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और हरित पत्तन पहल कार्यक्रम पत्तन क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन कि समस्याओं के समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस दिशा में, जनेप न्यास ने अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना के लिए कई उपाय किए हैं।

जनेप न्यास नगरक्षेत्र : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना

पत्तन ने फरवरी 2021 में जनेप न्यास नगरक्षेत्र में समग्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का उद्घाटन किया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 भारत सरकार के अनुसार 10 मीट्रिक टन/दिन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा को डिजाइन किया गया है, यह भाभा परमाणु अनुसंधान की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। इस सुविधा में 5 मीट्रिक टन / प्रतिदिन का संयंत्र शामिल है जो बिजली उत्पादन के लिए बायोगैस का उपयोग करता है। सूखे कचरे के संपीड़न के लिए हाइड्रोलिक बेलिंग प्रेस मशीन, और एकत्रित सूखे और गीले कचरे को अलग करने की सुविधा है। यह सुविधा पत्तन उपयोगकर्ताओं, पत्तन नगरक्षेत्र और पत्तन क्षेत्र में आनेवाले गांवों के लिए है।

In the reporting period, JNPT celebrated Swachhta Pakhwada during 16–30 September 2020, organizing trainings on Solid Waste Management and the importance of a clean environment and better sanitation for about 225 participants including port employees, terminal operators, tank farms operators, and other port users. In 2019, towards an effort to reduce open defecation in the port area, e-toilets with self-digestive systems have been installed in the wharf area.

In the last three years, JNPT has conducted approximately

70

awareness and training sessions on solid waste management for

3000

JN Port employees, schools, township residents, CISF staff, JN Port cleaning workers, truck drivers, etc.

Recognizing the severe impacts of oil spills on the environment and in accordance with the Maritime India Vision 2030, JNPT has developed a fully updated Oil Spill Contingency Plan in line with NOS-DCP (National Oil Spill-Disaster Contingency Plan), Guidelines (2015). The plan has been appropriately forwarded to the Indian Coast Guard for vetting. The Coast Guard Regional Headquarters (West) has approved the Plan and recommended it to the Coast Guard Headquarters in Delhi for vetting and approval vide letter dated 5 August 2019. As part of the response plan, an Oil Spill Response Tier-I facility is operational around MBPT and JNPT harbour that can handle spillage up to 700 MT. The detailed JNPT Oil Spill Response (OSR) is given in the annexures. JNPT will strive to ensure the plan is consistently updated vis-a-vis the latest required standards.

JNPT Hospital: Biomedical waste management

Segregation, collection, storage and disposal of biomedical waste is carried out at JNPT Hospital as per the Biomedical Waste management Rules 2016, and amendments thereof. Waste is segregated into Red, Yellow, Blue and White bins, and then transported to the authorized waste disposal vendor site. COVID waste is also separately stored and disposed as per the CPCB Guidelines for Handling, Treatment and Disposal of Waste Generated during Treatment/Diagnosis/ Quarantine of COVID-19 Patients. Regular training of staff and monitoring by Infection Control Nurse is carried out to ensure compliance to guidelines.

रिपोर्टिंग अवधि में जनेप न्यास ने 16-30 सितंबर 2020 के दौरान 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया, जिसमें पत्तन कर्मचारियों, टर्मिनल प्रचालकों, टैंक फार्म प्रचालकों सहित लगभग 225 प्रतिभागियों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण और बेहतर स्वच्छता के महत्व पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। पत्तन क्षेत्र में खुले में शौच को कम करने के प्रयास की दिशा में वर्ष 2019 में घाट क्षेत्र में स्वपाचित्र प्रणाली वाले ई-शौचालय स्थापित किए गए।

विगत तीन वर्षों में, जेएनपीटी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर लगभग

70

जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए, जो

3000

जेएन पोर्ट कर्मचारियों, स्कूलों, टाउनशिप निवासियों, सीआईएसएफ कार्मिकों, जेएन पोर्ट के सफाई कर्मचारियों, ट्रक चालकों आदि के लिए थे।

पर्यावरण पर तेल रिसाव के गंभीर प्रभावों को स्वीकार करते हुए और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अनुसार जनेप न्यास राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना,2015 दिशानिर्देशों के अनुरुप अद्यतन तेल रिसाव आकस्मिक योजना तैयार की है। योजना को भारतीय तटरक्षक बल को पुनरीक्षण के लिए भेज दिया गया है। तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (पश्चिम) ने योजना को मंजूरी दे दी है और दिनांक 5 अगस्त 2019 के पत्र के माध्यम से समीक्षा और अनुमोदन के लिए दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय को अग्रेषित किया है। जवाबी योजना के रूप में, तेल रिसाव प्रतिक्रिया टियर- I सुविधा मुंबई पत्तन न्यास और जनेप न्यास बन्दरगाह क्षेत्र में प्रचालनीय है जो 700 एमटी तक रिसाव देखा सकता है। विस्तृत जनेप न्यास तेल रिसाव प्रतिक्रिया अनुलग्नकों में संदर्भ के लिए हाइपरलिंक है। जनेप न्यास यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि नवीनतम आवश्यक मानकों के अनुसार योजना को लगातार अद्यतन किया जाए।

जनेप न्यास अस्पताल : जैवचिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और उसके संशोधनों के अनुसार जनेप न्यास अस्पताल में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण और निपटान किया जाता है। कचरे को लाल, पीले, नीले और सफेद डिब्बे में अलग किया जाता है, और फिर प्राधिकृत कचरा निपटानकर्ता प्रसंस्करण क्षेत्र पर ले जाता है । कोविड-19 रोगियों के उपचार/निदान/क्वारंटाइन के दौरान उत्पन्न कचरे के प्रबंधन, उपचार और निपटान के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड कचरे को अलग से संग्रहित और निपटाया जाता है। दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण और संक्रमण नियंत्रण नर्स द्वारा निगरानी की जाती है।

JNPT has also established requisite waste reception facilities as per MARPOL 73/38 (Annex I to Annex VI).

Reception Facility as per MARPOL 73/78	JNPT's Compliance Measures
Annex I (Regulations for the Prevention of Pollution by Oil)	◆ Registered three recyclers /re-processors (holding necessary clearances from State Pollution Control Board (SPCB)) for removal of oily waste and bulk noxious liquid substances from vessels ◆ Appropriate reception facilities are in place for collection of wastes
Annex II (Regulations for the Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk)	◆ Port has allotted work to three recyclers / re-processors authorized by the SPCB
Annex III (Prevention of Pollution by Harmful Substances Carried by Sea in Packaged Form)	◆ All container terminals at JNPT have a HAZBUND for safe keeping of leaking /damaged IMDG containers where spills can be collected for safe and secure disposal of hazardous waste /goods ◆ JNPT is also a registered member of the Common Hazardous Waste – Treatment, Storage and Disposal Facility (CHW-TSDF) in Navi Mumbai
Annex IV (Prevention of Pollution by Sewage from Ships)	◆ Reception facility in place for transfer of sewage from ships to the septic tank at port through tanker ◆ No request from any vessel till date for discharge of sewage, as per Annex IV of MARPOL 73/78
Annex V (Prevention of Pollution by Garbage from Ships)	◆ Facility for removal of garbage from vessels is provided ◆ Collected garbage is sent to the Solid waste Management plant commissioned by JNPT
Annex VI (Prevention of Air Pollution from Ships)	◆ Port has allotted work to three recyclers / re-processors authorized by the SPCB

जेएनपीटी ने मारपोल 73/38 (परिशिष्ट I से परिशिष्ट VI) के अनुसार अपेक्षित अपशिष्ट प्राप्ति इकाइयां भी स्थापित की हैं।

मारपोल 73/78 के अनुसार प्राप्ति इकाई	जेएनपीटी के अनुपालना संबंधी उपाय
परिशिष्ट I (तेल द्वारा प्रदूषण की रोकथाम के लिए विनियम)	• जहाजों से तेल आधारित अपशिष्ट और स्थूल विषाक्त तरल पदार्थों को हटाने के लिए तीन रिसाइकलर / री-प्रोसेसर पंजीकृत किए गए (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त है) • अपशिष्ट संकलन के लिए उपयुक्त प्राप्ति इकाइयां स्थापित हैं
अनुलग्नक II (स्थूल विषाक्त तरल पदार्थों द्वारा प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियम)	• पत्तन ने एसपीसीबी द्वारा प्राधिकृत तीन रिसाइकिलर्स / रिप्रोसेसर्स को कार्य आवंटित किया है
परिशिष्ट III (पैकेज्ड स्वरुप में समुद्र द्वारा वहन किए जाने वाले हानिकारक पदार्थों द्वारा प्रदूषण की रोकथाम)	• जेएनपीटी के सभी कंटेनर टर्मिनलों में लीकेज / क्षतिग्रस्त आईएमडीजी कंटेनरों को सुरक्षित रखने के लिए एक हेज़बंड (HAZBUND) है जहां खतरनाक अपशिष्ट / माल के सुरक्षित और सुरक्षित निपटान के लिए रिसाव एकत्रित किए जा सकते हैं। • जेएनपीटी नवी मुंबई में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट - उपचार, भंडारण और निपटान इकाई (सीएचडब्ल्यू-टीएसडीएफ) का एक पंजीकृत सदस्य भी है
परिशिष्ट IV (जहाजों से सीवेज द्वारा प्रदूषण की रोकथाम)	• जहाजों से टैंकर के माध्यम से पत्तन पर सेप्टिक टैंक में सीवेज स्थानांतरण के लिए प्राप्ति इकाई। • मारपोल 73/78 के परिशिष्ट IV के अनुसार सीवेज निस्सारण के लिए अब तक किसी जहाज द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है
परिशिष्ट V (जहाजों के कचरे से प्रदूषण की रोकथाम)	• जहाजों से कचरा हटाने की सुविधा प्रदान की जाती है • एकत्रित कचरा जेएनपीटी द्वारा स्थापित सोलीड वेस्ट मेनेजमेन्ट प्लान्ट को भेजा जाता है
परिशिष्ट VI (जहाजों से वायु प्रदूषण की रोकथाम)	• पोर्ट ने SPCB द्वारा अधिकृत तीन रिसाइकलर/री-प्रोसेसर को काम आवंटित किया है

Reducing Noise Pollution and Land Contamination

Noise Pollution

Noise pollution from terminal operations, construction work, rail, truck and ship movement, and other activities affect marine ecosystems and the surrounding communities considerably. Studies have established that low-frequency underwater noise can have adverse impacts on marine life. However, the port industry and related activities are expected to grow even more in the times to come, which call for urgent and stringent measures to mitigate noise pollution along with ensuring the fulfillment of economic objectives. A collaborative approach to implement measures ensuring ambient noise levels around the port and reducing underwater noise levels is essential. Additionally, real-time monitoring of noise levels both underwater and around the port area would ensure the well-being of marine life and coastal communities.

JNPT, in collaboration with IIT Madras, conducts regular environmental sampling and analysis of the noise levels arising out of port operations as part of its Environmental Management and Monitoring Plan (EMMP), and takes appropriate measures to maintain the decibel levels within permissible limits.

Land Contamination

Oil spillage, cargo residue, waste discharge, and terminal operations can have significant impact on the land and soil in and around the port area. Contaminated soil can have potentially harmful effects on community health, along with adverse impacts on terrestrial and marine life. At the same time, the reclamation of contaminated lands is not only cost intensive, but a long-drawn process, spanning over several years.

JNPT takes an integrated approach to mitigate and avoid harmful effects of its operations that could possibly impact the land and soil in and around the port area. The various ongoing and planned interventions towards water, waste, wastewater management, including JNPT's Oil Spill Contingency Plan and so on, are all aimed at reducing the adverse effects of the Port's operations on terrestrial and marine life.

Ecological Conservation

Biodiversity Conservation and Greenbelt Development

Green belt development in ports plays a role in not only mitigating fugitive emissions but also acts as a system for noise reduction. Additionally, green belts support biological diversity and are instrumental in soil erosion control, coastal protection, and recharging of groundwater.

JNPT complies with the stipulation in the Guidance Manual for Environmental Management Plan (EMP) prepared by MoEFCC, which mandates that the total green area including landscaping area has to be about 33% of the port area.

ध्वनि प्रदूषण और भूमि संदूषण को कम करना

ध्वनि प्रदूषण

टर्मिनल प्रचालन, निर्माण कार्य, रेल, ट्रक और जहाजों का आवागमन और अन्य गतिविधियों से होने वाला ध्वनि प्रदूषण, सामुद्रिक पारितंत्र और आस-पास के समुदायों को अत्यधिक प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चला है कि पानी के अंदर कम आवृत्ति वाला शोर सामुद्रिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हालाँकि, आगामी समय में पत्तन उद्योग और संबंधित गतिविधियों के और भी बढ़ने की अपेक्षा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल और कड़े उपायों की आवश्यकता उत्पन्न होती है। पत्तन के आस-पास परिवेशी शोर स्तर कम रखना सुनिश्चित करने और पानी के भीतर शोर के स्तर को कम करने के उपायों को लागू करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण आवश्यक है। इसके अलावा, पानी के अंदर और पत्तन क्षेत्र के आस-पास शोर के स्तर की वास्तविक समय की निगरानी से सामुद्रिक जीवन और तटवर्ती समुदायों की बेहतरी सुनिश्चित होगी।

आईआईटी मद्रास के सहयोग से जेएनपीटी, अपनी पर्यावरण प्रबंधन और निगरानी योजना (ईएमएमपी) के भाग के रूप में, पत्तन प्रचालन से उत्पन्न होने वाले शोर के स्तर के नियमित पर्यावरणीय नमूने लेने और विश्लेषण करने का कार्य करता है और डेसिबल स्तर को स्वीकार्य सीमा के अंदर बनाए रखने के लिए समुचित उपाय करता है।

भूमि संदूषण

पत्तन क्षेत्र में और उसके आस-पास की भूमि और मिट्टी पर, तेल रिसाव, कार्गो अवशेष, अपशिष्ट निस्सारण और टर्मिनल प्रचालन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। दूषित मिट्टी के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य पर संभावित हानिकारक प्रभावों के अलावा, स्थलीय और सामुद्रिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। इसके अलावा दूषित भूमि का रिक्लेमेशन (पुनर्ग्रहण) न केवल अधिक लागत वाला होता है, बल्कि यह कई वर्षों तक विस्तृत एक लंबी प्रक्रिया होती है।

जेएनपीटी ने अपने प्रचालनों के ऐसे हानिकारक प्रभाव कम करने और उनसे बचाव करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है जो संभवतः पत्तन क्षेत्र में और उसके आस-पास की भूमि और मिट्टी को प्रभावित कर सकते हैं। जल, अपशिष्ट, अपशिष्ट जल प्रबंधन, जिसमें जेएनपीटी की तेल रिसाव आकस्मिक योजना व अन्य शामिल हैं, के साथ विभिन्न संचालित और नियोजित हस्तक्षेपों का उद्देश्य यह है कि पत्तन के प्रचालन के कारण स्थलीय और सामुद्रिक जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जाए।

पारिस्थितिक संरक्षण

जैव विविधता संरक्षण और हरित पट्टी विकास

पत्तनों में हरित पट्टी का विकास न केवल पलायक (फ्यूजिटिव) उत्सर्जन को कम करने में भूमिका निभाता है बल्कि शोर में कमी करने वाली प्रणाली के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, हरित पट्टियां जैविक विविधता में सहायक होती हैं और मृदा अपरदन नियंत्रण, तटीय संरक्षण और भूजल के पुनर्भरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

जेएनपीटी, एमओईएफसीसी द्वारा तैयार पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करता है, जिसमें कहा गया है कि लैंडस्केपिंग क्षेत्र सहित कुल हरित क्षेत्र, पत्तन क्षेत्र का लगभग 33% होना चाहिए।

The total land available with JNPT is around

3402 ha,

out of which,

34%

area of the port is under green cover, including various species of mangroves.

Under the Green Port Initiative, JNPT has annually planted

5000 *trees*

in the port estate from

FY2018 to FY2020.

Species such as Karanj, Jamun, Arjuna, Kadamba, Neem, Gulmohar, Peepal, Vad, Ashok, Palm, Gulmohar, etc., have been planted in the port premises.

JNPT is committed to sustainable development and ensures adequate measures are undertaken to maintain the ecological balance.

Marine Ecology

The sea is the lifeline for ports since prominent port activities are possible because of the sea. The JNPT area plays host to a rich and diversified species of flora and fauna. Striving towards a sustainable future, JNPT considers that maintaining sea quality and marine life is a primary responsibility. The Port has undertaken several key initiatives to ensure marine ecology is protected within the port boundaries and is not negatively affected by its operations. These initiatives are also directly in line with JNPT's goal to achieve the Green Port Status under the Green Port Initiative.

GRI 304-2

जेएनपीटी के पास कुल लगभग

3402 हेक्टेयर

भूमि उपलब्ध है जिसमें से पत्तन का

34% *क्षेत्र हरित है जिसमें मैन्ग्रोव की विविध प्रजातियां शामिल हैं।*

हरित पत्तन पहल के अंतर्गत, जेएनपीटी ने

वित्तीय वर्ष 2018 से वित्तीय वर्ष 2020

के दौरान, पत्तन क्षेत्र में प्रती वर्ष

5000 *पौधे लगाए।*

करंज, जामुन, अर्जुन कदंब, नीम, गुलमोहर, पीपल, वड़, अशोक, ताड़, गुलमोहर आदि प्रजातियों के पौधे पत्तन परिसर में लगाए गए।

जेएनपीटी, संपोषणीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करता है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं।

समुद्री पारिस्थितिकी

समुद्र, पत्तनों की जीवन रेखा है क्योंकि प्रमुख पत्तन गतिविधियां समुद्र की वजह से संभव होती हैं। जेएनपीटी क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध और विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। संपोषणीय भविष्य की दिशा में प्रयास करते हुए, जेएनपीटी का मानना है कि समुद्र की गुणवत्ता और समुद्री जीवन का संरक्षण, एक मूलभूत जिम्मेदारी है। पत्तन की सीमाओं में समुद्री पारिस्थिति का संरक्षण करना और इसके प्रचालनों से पत्तन परिसर में होने वाले दुष्परिणामों की रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए पत्तन ने कई महत्वपूर्ण उपाय किए अपनाए हैं। ये प्रयास, हरित पत्तन पहल के तहत हरित पत्तन का दर्जा प्राप्त करने के जेएनपीटी के लक्ष्य के भी अनुरुप हैं।

JNPT works towards obtaining necessary environmental clearances for a project and monitors pollutants during the execution of the project as per the approved Environmental Management Plan (EMP). Under these clearances, studies are conducted by institutes such as National Institute of Oceanography (NIO) on the impacts of port activities (such as expansion of infrastructure) on marine ecology and marine water quality.

Through its partnership with IIT Madras, JNPT manages both marine water quality (regular monitoring of temperature, pH, salinity, TSS, oil and grease, COD and BOD, etc.) and marine ecosystem (regular monitoring of net primary productivity, chlorophyll a, phytoplankton, zooplankton, benthos, phosphates, nitrates, etc.). There is continuous monitoring of the effects of the Port's working on the environmental parameters to check the pollutants' level with respect to the EMP. Monthly marine water quality and marine ecosystem monitoring reports are available for public access on JNPT's official website.

JNPT is conscious of the negative impacts of oil/grease spillages on the marine environment. To address these issues, in 2018, JNPT developed a robust Oil Spill Response (OSR) plan, which is in alignment with the NOS-DCP 2015 Guidelines. Additionally, in 2018, an Oil Spill Response Tier-I facility (capable of handling spillage up to 700 MT) around MBPT and JNPT harbour was made operational.

Another key initiative is the commissioning of a 10 MT/day Solid Waste Management Facility in February 2021 as per SWM Rules, 2016 for port users, port township, and the villages within the port estate. The facility ensures that no untreated sewage is discharged from the port area into the sea.

Energy and Climate Change

Considering their location in coastal regions and proximity to the seas, ports are inherently vulnerable to climate change risks. The rising sea levels, strong winds, storms, extreme weather conditions pose serious risks to port operations, infrastructure and assets, along with impacting the people living in and around the port areas. With the crucial role that ports play in international trade and economic growth, taking urgent measures on climate change mitigation and adaptation becomes critically important for the port industry.

Recognizing the need to limit global warming, JNPT is working with a two-pronged approach – efficient use of energy, and integrating renewables in its energy – aimed at lowering its greenhouse gas emissions and transitioning to a low-carbon economy.

JNPT is actively working towards becoming a green and sustainable port. In line with the Maritime India Vision 2030, JNPT is adhering to International Marine Organization's alignment with UN SDG9 to "build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization, and foster innovation".

The Port is pursuing energy management strategies to bring about efficiencies in its operations and energy use. The Port is deploying energy-saving and enhancement techniques across its assets, infrastructure, and operations.

To further bolster India's goal of leading the world in safe, sustainable, and green ports, JNPT is working on implementing renewable energy projects to meet its energy demands. The MIV 2030 emphasizes increasing the share of renewable energy to more than 60% of the total energy by 2030 across major ports in India, with primary focus on solar and wind. JNPT is in the process of setting a 2.0 MW floating solar power plant which shall boost the renewable energy share at the port.

जेएनपीटी किसी परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करता है और परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अनुमोदित पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के अनुरूप प्रदूषकों की निगरानी करता है। इन स्वीकृतियों के अधीन, समुद्री पारिस्थितिकी और समुद्री जल की गुणवत्ता पर पत्तन की गतिविधियों (जैसे कि अवसंरचना का विस्तार) के प्रभावों के बारे में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) आदि संस्थानों द्वारा अध्ययन किया जाता है।

आईआईटी मद्रास के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से, जेएनपीटी सामुद्रिक जल गुणवत्ता (तापमान, पीएच, लवणता, टीएसएस, तेल और ग्रीस, सीओडी और बीओडी, आदि की नियमित निगरानी) और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र (शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, क्लोरोफिल ए, फाइटोप्लांकटन, जूप्लांकटन, बेंथोस, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स, आदि की नियमित निगरानी) का प्रबंधन करता है। ईएमपी के संदर्भ में प्रदूषकों के स्तर की जांच करने के लिए पर्यावरणीय मापदंडों पर पत्तन के कामकाज के प्रभावों की निरंतर निगरानी की जाती है। जेएनपीटी की सामुद्रिक जल गुणवत्ता और सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र निगरानी की मासिक रिपोर्टें, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

तेल/ग्रीज़ के रिसाव के कारण सामुद्रिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को लेकर भी जेएनपीटी सजग है। इन समस्याओं के समाधान के लिए, जेएनपीटी ने 2018 में एक सशक्त तेल रिसाव प्रतिक्रिया (ओएसआर) योजना विकसित की, जो एनओएस-डीसीपी 2015 के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, 2018 में, मुम्बई पत्तन न्याय और जेएनपीटी बंदरगाह के आस-पास एक तेल रिसाव प्रतिक्रिया टियर-I सुविधा (700 मीट्रिक टन तक रिसाव को संभालने में सक्षम) शुरू की हैं।

पत्तन उपभोक्ताओं, पत्तन नगरक्षेत्र और पत्तन के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित गांवों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार फरवरी 2021 में 10 मीट्रिक टन/प्रतिदिन क्षमता वाली एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाई की स्थापना, एक अन्य महत्वपूर्ण पहल है। यह इकाई, पत्तन क्षेत्र से किसी अनुपचारित अपशिष्ट जल को समुद्र में न डाला जाना सुनिश्चित करती है।

ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन

तटवर्ती क्षेत्रों में पत्तनों की अवस्थिति और समुद्र से निकटता को ध्यान में रखते हुए, ये जलवायु परिवर्तन जोखिमों के प्रति स्वाभाविक रूप से असुरक्षित होते हैं। बढ़ता समुद्र स्तर, तेज़ हवाएं, तूफान, चरम मौसम दशाएं आदि पत्तन के प्रचालनों, अवसंरचना और परिसंपत्तियों के अलावा पत्तन क्षेत्रों में और आस-पास रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हुए उनके लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती है। जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक विकास में पत्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन के तत्काल उपाय किया जाना, पत्तन उद्योग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है।

वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) को सीमित करने की आवश्यकता को घ्यान में रखते हुए, जेएनपीटी दो-आयामी विधि के साथ काम कर रहा है जिसका ध्येय - ऊर्जा का कार्यकुशल उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में एकीकृत करना - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों को कम करना और निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर रूपांतरण करना है।

जेएनपीटी एक पर्यावरण अनुकूल और संपोषणीय पत्तन बनने की दिशा में सक्रियतापूर्वक कार्यरत है। मैरिटाइम इंडिया विज़न (एमआईवी) 2030 के अनुरूप जेएनपीटी "लोचशील अवसंरचना का निर्माण, समावेशी और सस्टेनेबल औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और नवप्रवर्तन को प्रेरित करने" के संयुक्त राष्ट्र एसडीजी9 के लक्ष्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की अनुरूपता का पालन कर रहा है।

पत्तन अपने प्रचालनों और ऊर्जा उपयोग में दक्षता बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रबंधन रणनीतियों का पालन करता है। पत्तन अपनी सभी परिसंपत्तियों, अवसंरचना और प्रचालन में ऊर्जा की बचत करने वाली और संवर्धन तकनीकों का प्रयोग कर रहा है।

सुरक्षित, संपोषणीय और पर्यावरण अनुकूल पत्तनों में विश्व का नेतृत्व करने के भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, जेएनपीटी अपनी ऊर्जा संबंधी माँगें पूरी करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करने पर काम कर रहा है। एमआईवी 2030 में, भारत के प्रमुख पत्तनों में सौर (सोलर) और पवन ऊर्जा पर प्राथमिक रूप से ध्यान देने के साथ 2030 तक कुल ऊर्जा में नवीकरणीय ऊर्जा का भाग 60% से अधिक तक बढ़ाने पर जोर दिया गया है। जेएनपीटी में 2.0 मेगावाट का फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना कार्य प्रक्रियाधीन है जो पत्तन में नवीकरणीय ऊर्जा का भाग बढ़ाएगा।

Energy and Emissions

Since the time of embarking upon its sustainability journey, JNPT has been moving ahead steadily, continuously challenging itself with more and more ambitious goals and targets. Learning from its past experiences, the Port is always looking for avenues to step up its ongoing efforts and taking up newer challenges.

Energy Usage

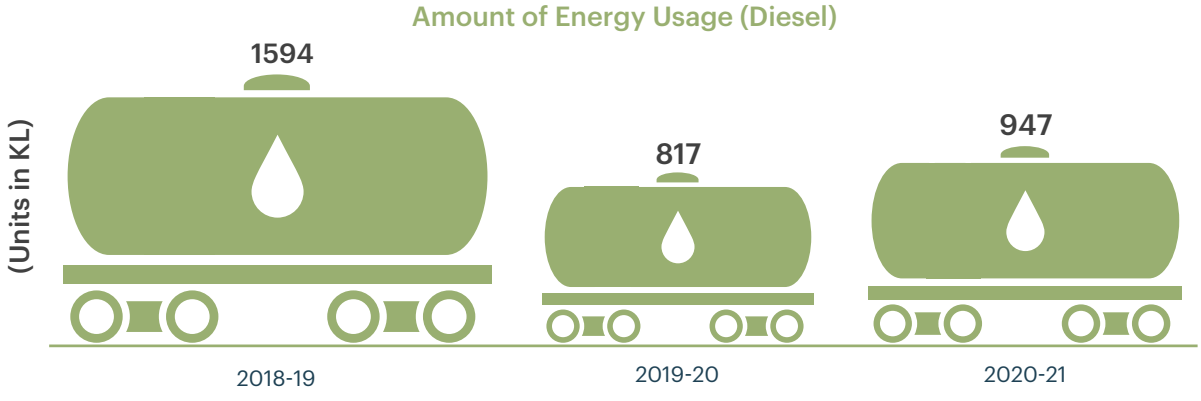

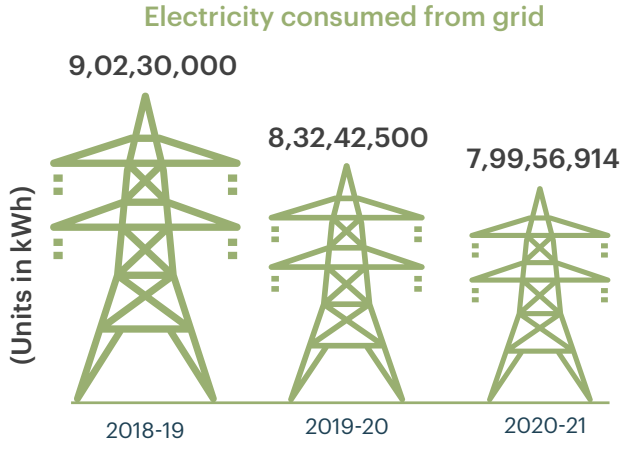

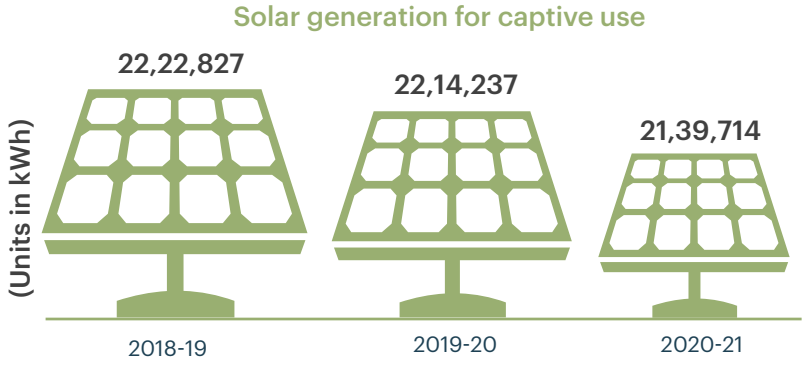

The diesel consumption has decreased by 59% in the last three years on account of many activities.

ऊर्जा और उत्सर्जन

अपनी संपोषणीयता की यात्रा शुरू करने के समय से, जेएनपीटी निरंतर दृढ़तापूर्वक, अनवरत रूप से, अधिक से अधिक महत्वाकांक्षी उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ स्वयं को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहा है। अपने पिछले अनुभवों से सीखते हुए, पत्तन ने सदैव ही अपने मौजूदा प्रयासों को आगे बढ़ाने और नई चुनौतियों का सामना करने के उपाय किए हैं।

ऊर्जा उपयोग

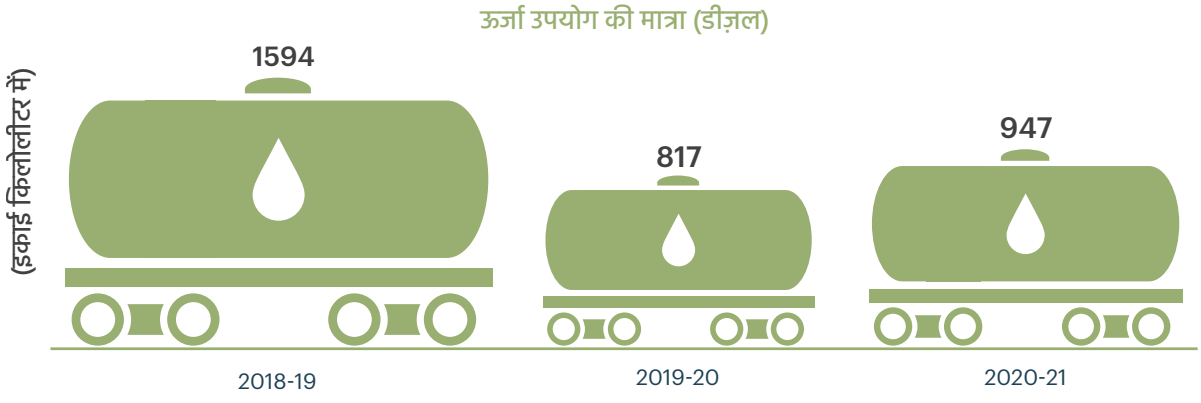

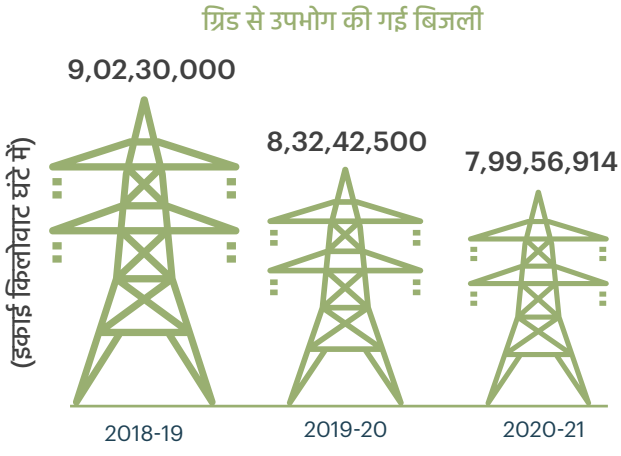

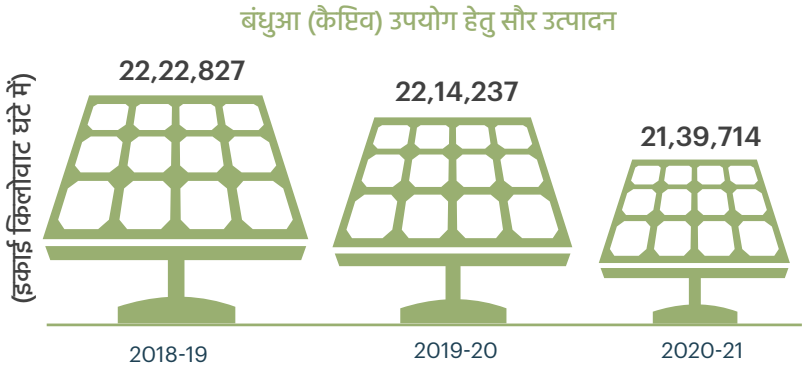

अनेक गतिविधियों के कारण पिछले तीन वर्षों में डीज़ल की खपत में 59% की कमी आई है।

Enhancing Energy Efficiency

Towards the goal of limiting its GHG emissions in line with India's MIV 2030, JNPT is stepping up its efforts to increase the use of efficiency improvement and enhancement measures and techniques.

All JNPT-bound ships are tracked by VTMS to ensure that they adjust their speed to arrive at pilot station at the appointed time and not be held offshore for extended time periods consuming large amounts of energy. In the township, JNPT is currently carrying out a pilot introducing smart street lighting through IoE sensors to save energy.

Other energy-saving initiatives and interventions taken up by JNPT are listed in Table 8.

Table 8: Energy-saving initiatives by JNPT

Initiative	Year of Intervention
Tube lights and bulbs replaced with LEDs lamps at all locations within the port area and township	2018–2020
Conventional air conditioners replaced with energy-efficient VRF system/5-star split inverter air conditioners of capacities varying from 40 tonne to 258.4 tonne	2018–2020
Electric carts purchased for transportation of men and material within port premises	2019
600 HP prime mover diesel engines (7 nos), old RTGCs repowered with 450 HP engines on existing RTGC	2019

As outlined in MIV 2030, JNPT is working on achieving electrification of all material handling equipment over the next 10 years, by (1) converting all cargo handling equipment (e.g. ship to/from shore cargo movers and within-port cargo movers) to electricity-driven; and (2) mandating the purchase of electrical equipment as replacement for all further purchase. In line with this goal, all ship-to-shore container handling cranes, i.e. RMQCs at JNPT are electrically driven. JNPT has acquired 15 new electrically operated RTGCs in the past few years. With the induction of these e-RTGCs, there has been a reduction in the consumption of high-speed diesel, of around 15-20 litre of diesel per hour. In their second phase of operations, BOT Operator–Bharat Mumbai Container Terminals Pvt. Ltd (BMCTPL) is also planning to purchase e-RTGCs.

Alternate Fuels

For the MIV 2030 goal of driving adoption of multi-clean fuels (electric, CNG, LNG) for vehicles in port ecosystem, JNPT is working on developing a well-defined road map for the adoption of multi-clean fuel, targeted to be completed by 2022, and the creation of required infrastructure by 2025. The port is ISO:14001 certified and came up with its Green Port Development Plan in 2016.

In line with fuel adoption trends by shipping liners, JNPT is working on establishing LNG bunkering stations at select ports. The first phase, to be completed in 2021 as per MIV 2030, will involve the appointment of a consultant for carrying out market assessment and identifying ports on the west coast of India that are strategically advantageous to provide LNG bunkering facilities. The development of LNG bunkering facilities at JNPT is already in the pipeline, and scheduled to be completed by 2024. Presently, all available data on LNG-powered vessels is being studied for the formulation of scope of work for the consultant. The MIV 2030 aims to establish LNG bunkering stations on pilot-basis in prioritized, select LNG terminal ports for ship-to-ship bunkering by 2028.

Towards the creation of non-monetary incentives for trade to shift to alternate fuels by 2025 and implementation of clean fuel vehicle programme by 2030, JNPT is in the final stage of hiring eight

ऊर्जा दक्षता में बढ़ोत्तरी

भारत के एमआईवी 2030 के अनुरूप अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में जेएनपीटी, दक्षता में सुधार और संवर्धन के उपायों और तकनीकों का उपयोग बढ़ाने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है।

जेएनपीटी की ओर जानेवाले सभी जहाजों को वीटीएमएस द्वारा ट्रैक करते हुए यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे निर्धारित समय पर पायलट स्टेशन पर पहुंचने के लिए अपनी गति को समायोजित करें और बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत करने के साथ अधिक समय अवधि तक ऑफशोर में न रहें। जेएनपीटी अपने नगरक्षेत्र में वर्तमान में एक पायलट योजना पर काम कर रहा है जिसके अंतर्गत, आईओई सेंसर के माध्यम से ऊर्जा की बचत करने वाली स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग लगाई गई हैं।

जेएनपीटी द्वारा की गई अन्य ऊर्जा की बचत वाली पहलों और हस्तक्षेपों को तालिका 8 में दिया गया है।

तालिका 8: जेएनपीटी के ऊर्जा की बचत वाली पहले

कार्यक्रम	हस्तक्षेप का वर्ष
पत्तन क्षेत्र और टाउनशिप के भीतर सभी स्थानों पर ट्यूब लाइट और बल्ब को बदलकर एलईडी लैंप लगाए गए।	2018–2020
पारंपरिक वातानुकूलन यंत्रों को बदलकर उनके स्थान पर ऊर्जा की बचत करने वाले, 40 टन से 258.4 टन तक की क्षमता वाले वीआरएफ सिस्टम/5-स्टार स्प्लिट इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगाए गए हैं।	2018–2020
पत्तन परिसर के भीतर कार्मिकों और माल के परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी गईं।	2019
600 एचपी प्राइम मूवर डीजल इंजन (7 नग), पुराने आरटीजीसी को मौजूदा आरटीजीसी पर 450 एचपी के इंजनों से बदला गया	2019

मैरीटाइम इंडिया वीज़न 2030 में उल्लेखित रुपरेखा के अनुसार जेएनपीटी अगले 10 वर्षों में सभी सामग्री प्रहस्तन उपकरणों का विद्युतीकरण करने की दिशा में काम कर रहा है, जिसके लिए निम्न कार्य किए जाने हैं (1) सभी कार्गो प्रहस्तन उपकरण (जैसे कि जहाज से तट तक आने-जाने वाले कार्गो मूवर्स और पत्तन में कार्गो मूवर्स) को बिजली से चलने वाले वाहनों में बदलना; और (2) भविष्य में प्रतिस्थापन संबंधी सभी खरीद के लिए बिजली के उपकरणों की खरीद को अनिवार्य बनाना। इस लक्ष्य के अनुरूप जेएनपीटी में जहाज से तट तक सभी कंटेनर प्रहस्तन क्रेनें, अर्थात आरएमक्यूसी, बिजली से संचालित हैं। जेएनपीटी ने पिछले कुछ वर्षों में 15 नए विद्युत संचालित आरटीजीसी का अधिग्रहण किया है। इन ई-आरटीजीसी के शामिल होने से हाई-स्पीड डीजल की खपत में लगभग 15-20 लीटर डीजल प्रति घंटे की कमी आई है। अपने दूसरे प्रचालन चरण में, बीओटी ऑपरेटर-भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल्स प्रा. लिमिटेड (बीएमसीटीपीएल) भी ई-आरटीजीसी खरीदने की योजना बना रही है।

वैकल्पिक ईंधन

पत्तन के परिवेश में वाहनों के लिए बहु-स्वच्छ (मल्टी-क्लीन) ईंधन (इलेक्ट्रिक, सीएनजी, एलएनजी) को अपनाने के लिए एमआईवी 2030 लक्ष्य के अनुरूप, जेएनपीटी बहु-स्वच्छ ईंधन को अपनाने की दिशा में एक सुपरिभाषित रोड मैप विकसित करने पर काम कर रहा है, जिसे 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है और आवश्यक अवसंरचना का निर्माण 2025 तक किया जाएगा। पत्तन आईएसओ:14001 प्रमाणित है और पत्तन ने 2016 में अपनी हरित पत्तन विकास योजना की शुरुआत की थी।

नौवहन कंपनियों द्वारा ईंधन को अपनाए जाने के रुझानों के अनुरूप, जेएनपीटी चुनिंदा पत्तनों पर एलएनजी बंकरिंग स्टेशन स्थापित करने पर काम कर रहा है। एमआईवी 2030 के अनुसार पहला चरण जो 2021 में पूरा होना था, उसमें बाजार का मूल्यांकन करने और भारत के पश्चिमी तट पर ऐसे पत्तनों के चिन्हांकन के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति किया जाना शामिल है जो एलएनजी बंकरिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए रणनीतिक रुप से लाभप्रद हों। जेएनपीटी में एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं का विकास पहले से ही प्रक्रियाधीन है और इसे 2024 तक पूरा किया जाना निर्धारित है। सलाहकार के लिए कार्य का दायरा निर्धारित करने के लिए वर्तमान में, एलएनजी संचालित जहाजों पर सभी उपलब्ध आंकड़ों का अध्ययन किया जा रहा है। 2028 तक एक से दूसरे जहाज तक बंकरिंग के लिए प्राथमिकता पर आधारित, चयनित एलएनजी टर्मिनल पत्तनों पर पायलट आधार पर एलएनजी बंकरिंग स्टेशन स्थापित करना एमआईवी 2030 का लक्ष्य है।

2025 तक वैकल्पिक ईंधन की दिशा में बदलाव हेतु और 2030 तक स्वच्छ ईंधन वाहन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए, व्यापारों द्वारा गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन सृजित करने के लिए जेएनपीटी आठ विद्युत चालित हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) किराए पर लेने के

electrically operated light motor vehicles (LMVs). As far as the Port echo system is concerned, the maximum movement of containers happens through tractor trailers and the Port is exploring the feasibility of using bio-diesel for internal trailers movement. It is planning to discuss the development of tractor trailers running on electrical energy/CNG/LNG with major manufacturing companies. In January 2022, one of the BOT operators at JNPT will be implementing a pilot project for using biodiesel for RTGCs.

Shore Power Supply

Shore power supply is provided to tugs and port crafts as an alternate energy source with the aim of reducing CO_2 emissions along with NOx, SOx, and particulate emissions in the port area. The electrical load per tug is around 50 KVA. At present, a total of eight tugs are supplied with shore power during their stay at the berth, achieving fuel savings to the tune of around 2000 litres of diesel/day.

The MIV 2030 outlines providing shore-to-ship electricity to vessels (tug-boats, coastal vessels and EXIM trade vessels) in a 3-phased targeted manner. The first phase involves on-boarding intermediary and drive commercialization for providing shore-to-ship electricity to vessels.

During 2021, JNPT worked on developing the second facility of shore power supply to tugs and port craft at coastal berth, and the appointment of a consultant for providing shore supply for coastal and EXIM vessels. In the third phase, scheduled to be completed by 2030, shore power at berths being operated under Public-Private Partnership (PPP) will be planned after examining the legal issue in line with the provisions of the Concessionaire Agreement.

Transition to Renewable Energy

A shift from fossil fuels to renewables is imperative for an emerging nation like India to meet its national and international commitments. JNPT understands that decarbonizing the port operations shall help in saving costs, energy, and making a way forward for future port operations.

In line with MIV 2030's goal of leading the world in safe, sustainable, and green maritime sector through increased use of renewable energy to >60% of total energy by 2030 across Indian ports with primary focus on solar and wind, JNPT has identified short, medium, and long-term goals of increasing renewables in its energy mix. In Phase 1 of implementation, JNPT aims to increase the share of renewable energy to 30% by 2024; while in Phase 2, to be achieved by 2027, it is proposed to increase the share of renewable energy to 50%. The target of 60% share of renewable energy is aimed to be achieved in Phase 3 by 2030.

Of the total capacity of 3.16 MW, the Port has already achieved the generation of 30% (2.3 MW) renewable energy through solar rooftop installations. As far as the target of 50% renewable energy to be achieved in Phase 2 is concerned, as outlined in MIV 2030, JNPT is the first major port to enter into a franchise agreement with a DISCOM. Subject to feasibility, the PPP terminals may now go for open access with renewable energy.

Apart from power generation through solar rooftop installations, JNPT is also setting up a floating solar PV, utilizing water bodies for boosting solar electricity generation. The infrastructure for floating solar would be set up in the lagoons behind berths in JNPT Container Terminal. Basis the feasibility study, the probable capacity of 2.0 MW of floating solar has been identified that will lead to the annual production of electricity to the tune of 3.83 x 106 KWh.

अंतिम चरण में है। पत्तन की परिसंस्था के संदर्भ में, कंटेनरों का अधिकतम आवागमन ट्रैक्टर ट्रेलरों के माध्यम से होता है और ट्रेलरों के आंतरिक आवागमन के लिए पत्तन बायोडीजल उपयोग करने की व्यावहारिकता का पता लगा रहा है। जेएनपीटी विद्युत ऊर्जा/सीएनजी/एलएनजी से चलने वाले ट्रैक्टर ट्रेलरों के विकास के संबंध में प्रमुख निर्माता कंपनियों के साथ बातचीत करने की योजना बना रहा है। जनवरी 2022 में, जेएनपीटी में एक बीओटी प्रचालक द्वारा आरटीजीसी के लिए बायोडीजल का उपयोग किए जाने हेतु एक पायलट परियोजना क्रियान्वित की जाएगी।

तटीय विद्युत आपूर्ति

पत्तन के क्षेत्र में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और कणीय उत्सर्जनों के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जनों को कम करने के उद्देश्य से टगों और पत्तन नौकाओं को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में तटीय बिजली की आपूर्ति की जाती है। प्रति टग विद्युत भार लगभग 50 केवीए होता है। वर्तमान में, घाट पर ठहराव के दौरान कुल आठ टगों को तटीय बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिससे लगभग 2000 लीटर डीजल/प्रतिदिन ईंधन बचत होती है।

एमआईवी 2030 में जहाजों (टग बोट, तटीय जलयानों और आयात-निर्यात व्यापारिक जहाजों को) तट पर 3-चरण में लक्षित तरीके से बिजली आपुर्ति करने का प्रावधान किया गया है। पहले चरण में जहाजों को तट पर बिजली आपुर्ति करने के लिए ऑन-बोर्डिंग मध्यस्थ और व्यावसायीकरण शामिल है।

2021 के दौरान, जेएनपीटी ने तटीय घाट पर टगों और पत्तन नौकाओं को तटीय बिजली की आपूर्ति के लिए दूसरी इकाई विकसित करने और तटीय और आयात-निर्यात जहाजों को तटीय आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति करने की दिशा में काम किया। 2030 तक पूरा होने वाले तीसरे चरण में, रियायती समझौते के प्रावधानों के अनुरूप कानूनी मसलों की जांच के उपरांत, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत संचालित घाटों पर तटीय बिजली आपूर्ति की योजना बनाई जाएगी।

नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में रूपांतरण

भारत तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है अत: अपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में बदलाव अनिवार्य है। जेएनपीटी इसे समझता है कि पत्तन प्रचालनों का विकार्बनीकरण करने से लागत बचत करने, ऊर्जा बचाने और भविष्य के पत्तन प्रचालनों का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिलेगी।

सौर और पवन ऊर्जा पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ भारतीय पत्तनों में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाकर कुल ऊर्जा का >60% तक करते हुए सुरक्षित, संपोषणीय और हरित सामुद्रिक क्षेत्र की दिशा में विश्व का नेतृत्व करने के एमआईवी 2030 के लक्ष्य के अनुरूप, जेएनपीटी ने अपने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने के लिए अल्पकालीन, मध्यम और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। क्रियान्वयन के चरण 1 में, 2024 तक नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 30% तक बढ़ाना जेएनपीटी का लक्ष्य है; जबकि 2027 तक प्राप्त किए जाने हेतु अपेक्षित चरण 2 में, नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 50% तक करना प्रस्तावित है। नवीकरणीय ऊर्जा के 60% भाग का लक्ष्य चरण 3 में 2030 तक हासिल करने का ध्येय है।

3.16 मेगावाट की कुल क्षमता में से, पत्तन ने सोलर रूफटॉप स्थापनाओं के माध्यम से 30% (2.3 मेगावाट) नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन पहले ही हासिल कर लिया है। जहां तक एमआईवी 2030 में उल्लेख किए गए अनुसार, चरण 2 में 50% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने का संबंध है, जेएनपीटी ऐसा पहला महा पत्तन है जिसने डिस्कॉम के साथ फ्रेंचाइजी करार किया है। इसकी व्यवहार्यता के अधीन, पीपीपी टर्मिनल्स नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं।

सोलर रुफटॉप स्थापनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन के अलावा, जेएनपीटी एक फ्लोटिंग सोलर पीवी भी स्थापित कर रहा है, जो सोलर बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए जल निकायों का उपयोग कर रहा है। फ्लोटिंग सोलर के लिए अवसंरचना को जेएनपीटी कंटेनर टर्मिनल में बर्थ के पीछे लैगून में स्थापित किया जाएगा। व्यावहारिकता अध्ययन के आधार पर, 2.0 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर की संभावित क्षमता की पहचान की गई है जिससे 3.83 x 106 किलोवाट घंटा बिजली का वार्षिक उत्पादन होगा।

SOCIAL & HUMAN CAPITAL

सामाजिक और मानवीय पूँजी

Social & Human Capital

Human Rights

As the world becomes more connected, there is an increased focus on how businesses and their operations are affecting human rights. Ports, by virtue of their operations, impact human beings and their rights both within the organization and outside of it. JNPT is committed to upholding human rights and values in all aspects of its operations. JNPT's business model of creating economic value is founded on the principles of ethics and responsibility. Stringent rules and a strict adherence to laws that ensure respect for rights of all the employees and stakeholders lie at the core of all of the Port's business activities.

JNPT's business strategy and policies ensure that all its employees uphold the highest standards of ethics. The organization follows a "zero-tolerance" policy towards issues, such as discrimination on the basis of race, religion, gender, disability, and so on. The partnership agreements with suppliers and vendors clearly spell out JNPT's policy on upholding human rights and values across its value chain. It works closely with its value chain partners to ensure they abide by the law of the country and meet all statutory liabilities, such as payment of minimum wages, provident fund, employee state insurance, and so on towards the engaged workers.

JNPT's robust grievance reporting and resolution framework ensures effective and timely redressal of issues related to violation of human rights within or outside the organization involving its employees and all other stakeholders.

Human Capital

JNPT's workforce is its core strength and the energy that drives it forward. With a workforce of more than 1000 employees, the Port today is a global brand in the maritime sector and the premier container port in the country. The workers in the past laid a solid foundation for the Port to build on and the workforce that followed has carried JNPT ahead one milestone after the other, and the journey continues scaling new heights. Recognizing that its employees are the key to achieve its business and sustainability goals, JNPT thrives to provide the required support to enrich their work while ensuring an enabling environment for the employees to develop and realize their true potential.

Employee Recruitment and Welfare

Employee Welfare

JNPT has a systematic recruitment policy and ensures benefits for its employees in the form of housing at JNPT township, scholarship opportunities for the employees' children, canteens with daily meal coupons to Class III and Class IV employees.

The surroundings and work culture bear a significant impact on the physical and mental well-being of a person. Taking cognizance of this, JNPT has developed recreational centres and sports facilities for all its employees. It is the first Port to provide air-conditioned bus facility to its employees.

GRI 102-41 | GRI 401-2 | GRI 406-1 | GRI 412-3

सामाजकि और मानवीय पूँजी

मानवाधिकार

बेहतर और आधुनिक संपर्क व्यवस्था के कारण पूरा विश्व अधिक अच्छी तरह से जुड़ रहा है जिसके कारण अधिक जुड़ते जाने के साथ, इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है कि व्यवसाय और उनके प्रचालन मानव अधिकारों को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। पत्तन, अपने प्रचालनों के कारण, संगठन के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर मनुष्यों और उनके अधिकारों को प्रभावित करते हैं। जेएनपीटी अपने प्रचालन के सभी आयामों में मानवाधिकारों और मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आर्थिक मूल्य सृजित करने के लिए जेएनपीटी का व्यावसायिक मॉडल, नैतिकता और जिम्मेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है। कड़े नियम और कानूनों का कड़ाई से पालन, जो सभी कर्मचारियों और हितधारकों के अधिकारों का पालन सुनिश्चित करते हों, ये पत्तन की सभी व्यावसायिक गतिविधियों का आधार हैं।

जेएनपीटी की व्यावसायिक रणनीति और नीतियां सभी कर्मचारियों द्वारा नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना सुनिश्चित करती हैं। संगठन, जाति, धर्म, लिंग, निःशक्तता आदि के आधार पर भेदभाव जैसे मुद्दों के बारे में "शून्य सहनशीलता" की नीति का पालन करता है। आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के साथ साझेदारी के अनुबंधों में जेएनपीटी की पूरी मूल्य श्रृंखला में मानवाधिकारों और मूल्यों को बनाए रखने की नीति स्पष्ट रुप से वर्णित की जाती है। यह अपनी मूल्य श्रृंखला के भागीदारों के साथ मिलकर काम करते हुए यह सुनिश्चित करता है कि वे देश के कानून का पालन करते हैं और सभी वैधानिक देयताओं, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा और अन्य को पूरा करते हैं।

शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए जेएनपीटी की विश्वसनीय व्यवस्था संगठन के अंदर या बाहर इसके कर्मचारियों और अन्य सभी हितधारकों से संबंधित, मानवाधिकारों के उल्लंघन संबंधी मुद्दों का प्रभावी और समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करती है।

मानवीय पूँजी

जेएनपीटी की कार्मिकशक्ति ही इसकी मुख्य शक्ति और इसे आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा है। 1000 से अधिक कर्मचारियों की शक्ति के साथ, पत्तन इस समय सामुद्रिक क्षेत्र में एक विश्वस्तरीय ब्रांड है और देश का प्रमुख कंटेनर पत्तन है। अतीत में कामगारों ने पत्तन के निर्माण के लिए जो ठोस नींव स्थापित की उसे ही बाद में कार्यबल ने विकसित करके जेएनपीटी को एक के बाद एक नए कीर्तिमानों तक पहुंचाया है और यह यात्रा निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। व्यवसाय और संपाषणीयता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपने कर्मचारियों की आधारभूत भूमिका को स्वीकार करते हुए जेएनपीटी, कर्मचारियों को उनके काम को समृद्ध बनाने के लिए ज़रूरी समर्थन प्रदान करने के साथ उनकी वास्तविक क्षमताएं विकसित और साकार करने के लिए एक सक्षमकारी वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

कर्मचारी नियुक्ति और कल्याण

कर्मचारी कल्याण

जेएनपीटी की एक सुव्यवस्थित नियुक्ति नीति है और यह अपने कर्मचारियों के लिए जेएनपीटी नगरक्षेत्र में आवास, कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए कैंटीन में भोजन के लिए दैनिक कूपन के रुप में लाभ सुनिश्चित करता है।

परिवेश और कार्य संस्कृति का हर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखकर जेएनपीटी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए मनोरंजन के केंद्र और खेलकूद की सुविधाएं विकसित की हैं। अपने कर्मचारियों को वातानुकूलित बस सुविधा प्रदान करने वाला यह पहला पत्तन है।

On the professional front, the Port has introduced *PRIDE – Leadership Dialogue & Communication, Employee Appreciation & Recognition* programme. The programme has a dual aim – (1) of creating a communication framework for all employees to interact with the management in a structured manner, and with a set frequency; and, (2) to recognize and appreciate individual employees and the team who have made specific contribution beyond the normal scope of work.

Through the Welfare Fund, the Port also provides for, (a) funds towards Officers Club, Staff Club; (b) meeting the cost of insurance premium for Group Personal Accident Insurance Scheme, Group Term Insurance; (c) Scholarship funds; and (d) funds for celebrations of festivals.

The Port has constructed 2033 residential units in its township along with pre-primary, primary, and secondary schools (English and Marathi medium). The schools are managed by Indian Education Society, Mumbai on behalf of the Port. Additionally, an English medium school, run by St. Mary's JNP High School, is also operational in the township. Each year, JNPT awards 335 scholarships to encourage the academically bright wards of the employees. The scholarships range from ₹ 450 to ₹ 1250 up to junior college level, ₹ 4000 for students who secure admission in professional degree courses on merit basis, and ₹ 6000 upon successful completion of a professional degree course in the first attempt.

Employee Recruitment

As on 31 March 2021, 1403 posts out of the total sanctioned strength of 1659 are filled. About 82% of the employees fall in the age group of 50 years and above, followed by 14% in the bracket of 40–50 years. Only 4% of the employees make up the younger population (18–40 years) at JNPT. No attrition has been observed in the age groups of 18–30, 30–40, and 40–50 years in the last three years (FY2018–19 to FY2020–21).

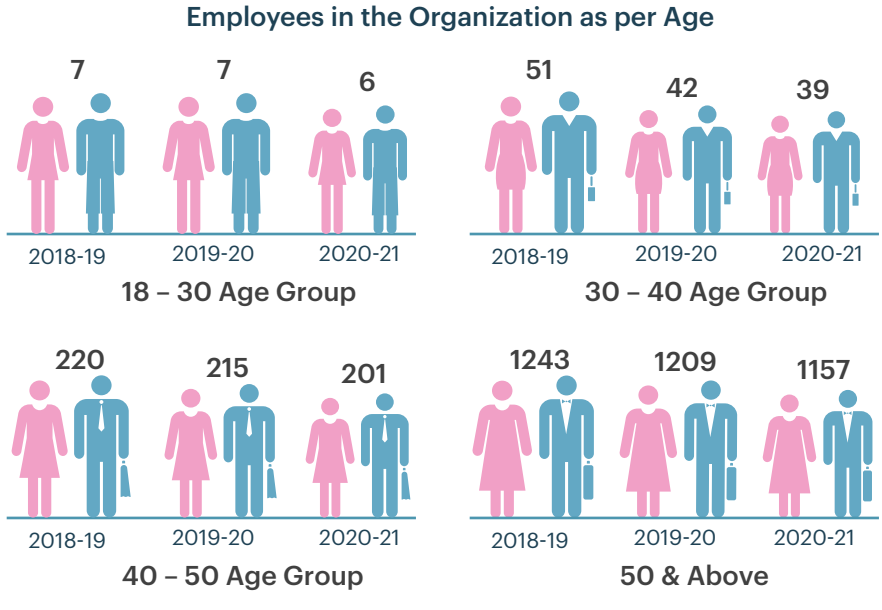

पेशेवर मामले में, पत्तन ने *प्राइड - लीडरशिप डायलॉग एंड कम्युनिकेशन, एम्प्लॉई एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन* कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का दोहरा उद्देश्य है - (1) सभी कर्मचारियों के लिए एक संरचित तरीके से और एक निर्धारित आवृत्ति के साथ, प्रबंधन से वार्तालाप करने के लिए एक संवाद रूपरेखा तैयार करना; और, (2) ऐसे व्यक्तिगत कर्मचारियों और टीमों को सम्मानित करना और उनकी सराहना करना जिन्होंने अपने सामान्य कार्यक्षेत्र से आगे बढ़कर कुछ विशिष्ट योगदान किया हो।

कल्याण निधि के माध्यम से, पत्तन निम्नलिखित के लिए भी प्रावधान करता है, (क) अधिकारी क्लब, कर्मचारी क्लब के लिए निधि; (ख) सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, सामूहिक सावधि बीमा के लिए बीमा प्रीमियम की लागत प्रतिपूर्ति करना; (ग) छात्रवृत्ति; और (घ) त्योहार मनाने के लिए निधि।

पत्तन ने अपने नगरक्षेत्र में पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों (अंग्रेजी और मराठी माध्यम) के साथ 2033 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है। इन स्कूलों का प्रबंधन पत्तन की ओर से मुंबई द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, सेंट मैरीज जेएनपी हाई स्कूल द्वारा संचालित एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी टाउनशिप में संचालित है। प्रत्येक वर्ष, जेएनपीटी अपने कर्मचारियों के बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 335 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। ₹ 450 से ₹ 1250 तक की छात्रवृत्ति जूनियर कॉलेज स्तर तक, ₹ 4000 उन छात्रों के लिए जिन्होंने श्रेष्ठता सूची के आधार पर पेशेवर डिग्री कोर्स में प्रवेश लिया हो और ₹ 6000 प्रथम प्रयास में कोई पेशेवर डिग्री कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिए जाते हैं।

कर्मचारियों की नियुक्ति

31 मार्च 2021 तक कुल स्वीकृत 1659 पदों में से 1403 पद भरे हुए हैं। लगभग 82% कर्मचारी 50 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में आते हैं, जिसके बाद 14% 40-50 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। जेएनपीटी में केवल 4% कर्मचारी युवा आयु समूह (18-40 वर्ष) के हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान (वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2020–21 तक) 18–30, 30–40 और 40–50 वर्ष के आयु समूहों के बीच कोई दुर्घटना नहीं पाई गई।

संगठन में आयु के अनुसार कर्मचारी

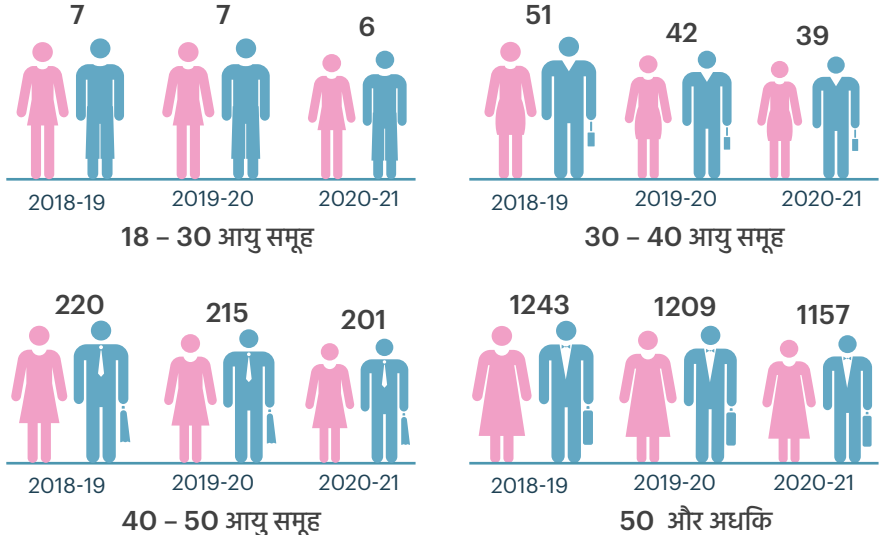

However, the past few years have witnessed a steady decline in the total number of full-time employees, with a corresponding dip in the number of both male and female employees, primarily on account of super-annuation or voluntary retirement among employees in the age group of 50 years and above.

With respect to the direct recruitment for Class I and Class II posts, as per Government of India directives, 50% of the posts are reserved for persons from Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), and Other Backward Class (OBC) categories (16.66%, 7.5%, and 25.84%, respectively) (Table 9). In case of Class III and Class IV posts, 46% of posts are reserved for SC, ST, and OBC categories (10%, 9%, and 27%, respectively). In all Classes, 15% and 7.5% of the posts are reserved to be filled by employees belonging to SC and ST categories in case of promotions.

Table 9: JNPT's employees' constitution as per hierarchy

Post	Sanctioned Strength	Filled	SC	ST	OBC
Class I	213	176	32	6	44
Class II	49	46	6	2	14
Class III	1284	1104	105	117	512
Class IV	113	77	4	9	45
Total	1659	1403	147	134	615

Competency Building of Employees

In a globalized world, rising competition and an increased reliance on the Internet and technology have resulted in a significant shift in the approach towards developing and managing human resources across industries and organizations. JNPT recognizes that its manpower is its key resource and catalyst in the achievement of its goals and objectives; and that investing in its employees will not only translate to an individual's growth, but also help the organization flourish. JNPT is continuously striving towards developing and introducing competency building programmes that would empower its employees to develop and enhance their capabilities in their current roles and future prospects. By developing the capacity of the existing workforce, the organization ensures: (a) enhanced productivity and (b) business continuity in the medium and long term.

Various programmes on topics such as soft skills, team building, customs' procedure, the Electricity Act, 2003, space technology and smart ports, and so on are conducted at the Port Training Centre on a regular basis for the officer-level employees and other staff members. Select staff members are also nominated for training sessions conducted by select institutions such as the Indian Institute of Management (IIM). Under the Apprenticeship Act of 1961, the Port engages graduate/diploma apprentices in engineering branches, and trade apprentices are involved in various trades.

Skill enhancement workshops and training programmes are conducted internally by different departments. Further, the employees are encouraged to attend different training courses at the JNPT–APEC Training Centre. The JNPT – Antwerp Port Training and Consultancy Foundation is a cooperation between JNPT, APEC – Antwerp/Flanders Port Training Centre, and the Port of Antwerp. The institute aims to provide state-of-the-art infrastructure and training modules, which are at par with global standards, to Port professionals in India and abroad. Apart from the key aspects of port operations, the underlying focus is to enhance and develop skills for business development strategies and marketing, in addition to instilling behavioural changes to lead effectively in the fast-changing business environment.

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, प्रमुख रूप से 50 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग वाले कर्मचारियों की अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के कारण पूर्णकालिक कर्मचारियों की कुल संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है और पुरुष और महिला दोनों प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में एक समान गिरावट हुई है।

श्रेणी I और श्रेणी II के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, 50% पद अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। (क्रमशः 16.66%, 7.5% और 25.84%) (तालिका 9)। श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों के संबंध में, 46% पद एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के लिए (क्रमशः 10%, 9% और 27%) आरक्षित हैं। सभी श्रेणियों में पदोन्नति के संबंध में 15% और 7.5% पद एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित हैं।

तालिका 9: पदानुक्रम के अनुसार जेएनपीटी के कर्मचारियों की रचना

डाक	स्वीकृत पद	भरे पद	एससी	एसटी	ओबीसी
श्रेणी I	213	176	32	6	44
श्रेणी II	49	46	6	2	14
श्रेणी III	1284	1104	105	117	512
श्रेणी IV	113	77	4	9	45
योग	1659	1403	147	134	615

कर्मचारियों का क्षमता सृजन

एक वैश्वीकृत दुनिया में, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और इंटरनेट और प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के फलस्वरूप उद्योगों और संगठनों में मानव संसाधनों के विकास और प्रबंधन के मामले में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। जेएनपीटी यह मानता है कि हमारे लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में हमारी कार्मिकशक्ति ही हमारे लिए प्रमुख संसाधन और उत्प्रेरक है; और यह कि अपने कर्मचारियों में निवेश न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक करेगा, बल्कि संगठन को भी फलने-फूलने में मदद करेगा। ऐसे क्षमता सृजन कार्यक्रमों को विकसित करने और शुरू करने की दिशा में जेएनपीटी लगातार प्रयास कर रहा है, जो हमारे कर्मचारियों को विकसित होने और उनकी वर्तमान भूमिकाओं और भविष्य की संभावनाओं के लिए उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें सशक्त बनाएंगे। मौजूदा कार्मिकशक्ति के क्षमता सृजन द्वारा संगठन निम्न को सुनिश्चित करता है: (क) बढ़ी हुई उत्पादकता और (ख) मध्यम और लंबी अवधि में व्यावसायिक निरंतरता।

पत्तन प्रशिक्षण केंद्र में अधिकारी स्तर के कर्मचारियों और अन्य स्टाफ सदस्यों के लिए, सॉफ्ट स्किल्स, टीम विकास, सीमा शुल्क प्रक्रिया, विद्युत अधिनियम, 2003, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और स्मार्ट पत्तन आदि अनेक विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। चयनित स्टाफ सदस्यों को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों के लिए भी नामित किया जाता है। 1961 के शिशिक्षुता अधिनियम के अंतर्गत, पत्तन में इंजीनियरिंग शाखाओं में स्नातक/डिप्लोमा प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया जाता है और विभिन्न ट्रेडों में ट्रेड अप्रेंटिस भाग लेते हैं।

विभिन्न विभागों द्वारा आंतरिक रूप से कौशल वृद्धि कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को जेएनपीटी-एपीईसी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जेएनपीटी – एंटवर्प पोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फाउंडेशन, जेएनपीटी, एपीईसी – एंटवर्प/फ़्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर और पोर्ट ऑफ़ एंटवर्प के बीच एक सहयोग है। भारत और विदेशों में पत्तन पेशेवरों को वैश्विक मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक अवसंरचना और प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना, इस संस्थान का उद्देश्य है। पत्तन प्रचालन के प्रमुख पहलुओं के अलावा, तेज़ी से बदलते कारोबारी माहौल में प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने के लिए व्यवहार में बदलाव लाने के अलावा, व्यवसाय विकास रणनीतियों और मार्केटिंग के लिए कुशलता का संवर्धन और विकास करने पर अंतर्निहित रूप से फोकस किया गया है।

The JNPT–APEC Training Centre receives participants from both public and private sector ports and terminals, including logistics operators, port consultants, port authorities, and port-related government bodies. Senior management, policymakers, operational management, and the middle management learn and acquire the requisite skills and knowledge to manage and operate ports and terminals in a better way to bring added value to the customers.

Diverse and Inclusive Workplace

A diverse and inclusive workplace can succeed and be future-ready if it fosters an environment of innovative thinking. Diversity not only adds to the talent pool, but it also goes a long way in inviting brighter minds to the organization.

Committed to ethical business standards and integrity, JNPT strives to develop a diverse, inclusive, and non-discriminatory workplace for women, differently abled, multi-cultural, and multi-generational employees. Therefore, it creates a value chain by meeting the expectations of its customers and shareholders.

While the port industry is traditionally male-dominated, JNPT's share of women workforce stands at ~7.5% of the total full-time employees. The strength of female employees has remained more

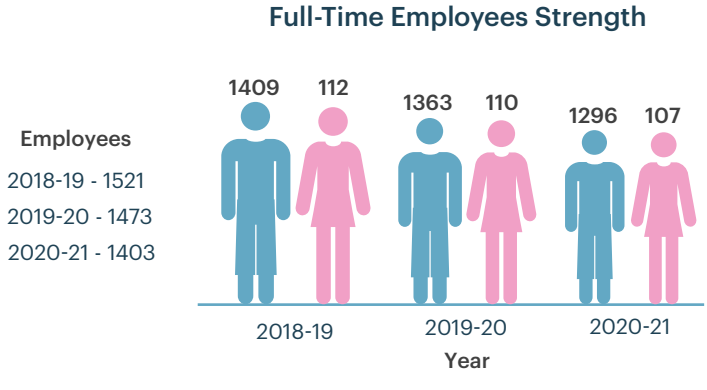

जेएनपीटी-एपीईसी प्रशिक्षण केंद्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पत्तनों और टर्मिनलों से प्रतिभागी आते हैं, जिनमें लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर, पत्तन सलाहकार, पत्तन प्राधिकारी और पत्तन से संबंधित सरकारी निकाय शामिल हैं। वरिष्ठ प्रबंधन, नीति निर्माता, प्रचालन प्रबंधन और मध्यस्तरीय प्रबंधन, पत्तनों और टर्मिनलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और संचालित करने के लिए आवश्यक कुशलताएं और ज्ञान सीखते और अर्जित करते हैं ताकि ग्राहकों को अतिरिक्त मूल्य प्रदान किया जा सके।

विविधतायुक्त और समावेशी कार्यस्थल

एक विविधतापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल यदि नई सोच के वातावरण को बढ़ावा देता है तो यह सफल हो सकता है और भविष्य के लिए तैयार हो सकता है। विविधता न केवल प्रतिभाओं का समूह (पूल) समृद्ध बनाती है, बल्कि यह संगठन में प्रतिभाशाली लोगों को लाने में भी एक बड़ी भूमिका निभाती है।

व्यवसाय के नैतिक मानकों और सत्यनिष्ठा के लिए प्रतिबद्ध, जेएनपीटी महिलाओं, मित्र-सक्षम, बहु-सांस्कृतिक और बहु-पीढ़ियों वाले कर्मचारियों के लिए एक विविधतापूर्ण, समावेशी और भेदभाव रहित कार्यस्थल विकसित करने का प्रयास करता है। इस तरह से, यह अपने ग्राहकों और शेयरधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए एक मूल्य श्रृंखला निर्मित करता है।

हालाँकि पत्तन उद्योग परंपरागत रूप से पुरुष-प्रधान है, लेकिन जेएनपीटी में महिला कार्मिकशक्ति का भाग कुल पूर्णकालिक कर्मचारियों का ~7.5% है। पिछले कुछ वर्षों में महिला कर्मचारियों की संख्या लगभग स्थिर रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में, 1403

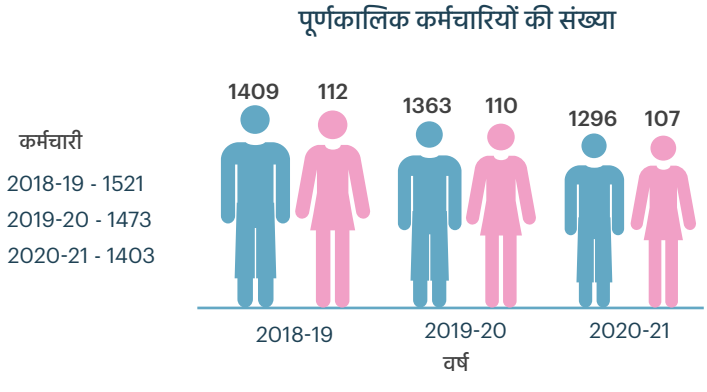

or less constant over the past few years. Of the 1403 full-time employees, the number of female employees for FY2020–21 stood at 107 (Table 10). JNPT has recruited 21 employees in the differently abled category and 39 employees on compassionate grounds.

Table 10: JNPT's workforce (in %)

Employee Strength	FY2018–19	FY2019–20	FY2020–21
Total employees	1521	1473	1403
Male employees	92.64	92.53	92.37
Female employees	7.36	7.47	7.63

Employee Health and Safety

For JNPT, the safety of its workers is of utmost importance and the Port strictly follows all mandatory guidelines and processes when it comes to the management of operations and equipment. JNPT operates under an integrated management system (IMS), meeting the requirements of ISO 9001 (Quality), ISO 14001 (Environment), and ISO 45001 (Health & Safety) certifications.

Regular quality checks, safety mock drills for different emergency scenarios, training and awareness on safety practices for the employees minimize risks and increase operational efficiency. All the terminals have their respective risk management policies for identification and mitigation of hazards at workplace. Moreover, world-class mitigation measures are in place in all the container terminals and in the liquid terminal too. All the terminals are either ISO 45001:2018/ OHSAS 18001:2017 compliant or have their own compliance standards.

The Port is working on inviting Expressions of Interest (EOI) from relevant parties in line with MIV 2030's goal of enhancing the infrastructure capabilities, availability of bed and staff at JNPT Hospital by 2022 via a PPP model. The hospital plans to add 25 more beds in the first quarter of FY2021–22 to meet COVID-19-related requirements.

According to MIV 2030, ports should implement special medical or occupational health services dedicated for port workers to ensure swift, essential aid for safety, thereby accomplishing the goal of "zero days lost due to health/safety". Towards strengthening the occupational health services in JNPT

पूर्णकालिक कर्मचारियों में से, महिला कर्मचारियों की संख्या 107 थी (तालिका 10)। जेएनपीटी ने भिन्न-सक्षम श्रेणी में 21 कर्मचारी और अनुकंपा के आधार पर 39 कर्मचारी नियुक्त किए हैं।

तालिका 10: जेएनपीटी की कार्मिक शक्ति (% में)

कर्मचारियों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2020–21
कुल कर्मचारी	1521	1473	1403
पुरुष कर्मचारी	92.64	92.53	92.37
महिला कर्मचारी	7.36	7.47	7.63

कर्मचारी स्वास्थ्य और संरक्षा

जेएनपीटी के लिए, अपने कर्मचारियों की संरक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है और प्रचालन प्रबंधन और उपकरणों के मामले में पत्तन द्वारा सभी अनिवार्य दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाता है। जेएनपीटी एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत काम करता है, जो आईएसओ 9001 (गुणवत्ता), आईएसओ 14001 (पर्यावरण) और आईएसओ 45001 (स्वास्थ्य और सुरक्षा) प्रमाणपत्रों की अपेक्षाएं पूरी करता है।

नियमित गुणवत्ता जांच, विभिन्न आपातकालीन परिदृश्यों के लिए संरक्षा मॉक ड्रिल, कर्मचारियों के लिए संरक्षा की विधियों से संबंधित प्रशिक्षण और जागरुकता गतिविधियां, जोखिम को कम करती है और प्रचालन दक्षता में वृद्धि करती है। कार्यस्थल पर खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए सभी टर्मिनलों की अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियां हैं। इसके अलावा, सभी कंटेनर टर्मिनलों और लिक्विड टर्मिनल में भी विश्व-स्तरीय न्यूनीकरण उपाय मौजूद हैं। सभी टर्मिनल या तो आईएसओ 45001:2018/ ओएचएसएएस 18001:2017 के अनुरुप हैं या उनके अपने अनुपालन मानक हैं।

एक पीपीपी मॉडल के माध्यम से 2022 तक जेएनपीटी अस्पताल में अवसंरचना क्षमताओं, बेड और कर्मचारियों की उपलब्धता में सुधार करने के एमआईवी 2030 के लक्ष्य के अनुरुप पत्तन, संबंधित पक्षों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। कोविड-19 संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अस्पताल में, वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 25 और बेड शामिल करने की योजना है।

एमआईवी 2030 के अनुसार, पत्तनों को विशेष चिकित्सकीय या व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित करनी चाहिए जो पत्तन के कर्मचारियों के लिए समर्पित हों, ताकि संरक्षा के लिए त्वरित, आवश्यक सहायता सुनिश्चित की जा सके और इस प्रकार "स्वास्थ्य/ संरक्षा के कारण शून्य कार्यदिवस हानि" का लक्ष्य पूरा किया जा सके। जेएनपीटी क्षेत्र में व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों से सुसज्जित एक व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है। घायल और बीमार

area, an occupational health centre with trained medical officers has been established. Fast speed boats for ferrying injured and sick persons, 24x7 availability of ambulance at port premises, availability of stretchers, and means to rescue employees from drowning have been introduced as well. The health records of the employees are maintained in a digital format as part of S/4 HANA implementation. Periodic health monitoring and regular follow-up of diagnosed cases are also undertaken by JNPT Hospital. These interventions were achieved before the initially planned deadline of 2022.

JNPT Hospital response to COVID-19

During the pandemic, JNPT Hospital admits and treats patients, who tested positive for COVID-19, in DCHC (Dedicated COVID Health Centre) with regular monitoring and by following strict infection control practices. Besides JNPT beneficiaries, most patients are from nearby villages. Almost all admitted patients were discharged after their successful recovery and they provided positive feedback on the excellent care provided at the hospital. All patients are provided free treatment in this hospital. A central oxygen MGPS (medical gas pipeline system) is installed at JNPT Hospital to provide uninterrupted oxygen supply to the patients. The facility of RT-PCR and Rapid Antigen testing for COVID-19 is available at JNPT Hospital and is in line with the government guidelines. A separate OPD located away from the regular one provides consultation services to suspected and positive patients. Regular sanitization is carried out in the township and the surrounding villages. Daily surveillance of all patients under home isolation is carried out. JNPT supported the setting up of another DCHC at Bokadvira Uran by providing facilities and infrastructure, including beds. Ambulance services are provided by JNPT to facilitate referral of patients from both the DCHC locations. A control room, manned by doctors, was set up during the peak of the pandemic to manage admissions, discharges, and address referral-related and other queries. All COVID-19 protocols and behavioural norms are reinforced through many IEC displays.

Due to the pandemic, eye camps and medical check-up camps could not be held during FY2020–21. However, regular monthly immunization camps and well-baby clinics continue to be organized by JNPT Hospital.

JNPT continuously strives to strengthen its training programmes for port workers, in line with MIV 2030 to achieve the goal of 100% staff, trained on areas specific to their jobs. Regular safety awareness and refresher training are imparted by the safety section, and regular inspection is undertaken to prevent unsafe activities. The Annual Safety Audit of container terminals and storage yards is conducted by National Safety Council and that of tank farms and jetty for flammable and hazardous cargo is conducted by OISD, and compliance to audit recommendations is ensured. Based on the needs of the identification processes, the Port organizes training programmes for all the employees every three to five years. Formal trainings on occupational health hazards with respect to port operations are conducted for medical officers in the health centre to enable better diagnosis and treatment.

To ensure better management of end-to-end handling of hazardous materials, an annual safety audit of container terminals is conducted by NSC. A detailed SOP is in place for handling of liquid medical oxygen. However, the OISD audit of POL and of flammable product handling and storage facilities at the Port is pending for 2020 due to the COVID-19 restrictions.

व्यक्तियों को लाने-ले जाने के लिए तेज़ गति वाली नौकाएं, पत्तन परिसर में एम्बुलेंस की 24x7 उपलब्धता, स्ट्रेचरों की उपलब्धता और कर्मचारियों को डूबने से बचाने के उपाय भी स्थापित किए गए हैं। एस/4 एचएएनए क्रियान्वयन के रूप में कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का डिजिटल रखरखाव किया जाता है। जेएनपीटी अस्पताल द्वारा आवधिक रूप से स्वास्थ्य निगरानी और पता लगाए गए मामलों में नियमित अनुवर्तन भी किया जाता है। इन हस्तक्षेपों को 2022 की प्रारंभिक नियोजित समय सीमा से पूर्व ही हासिल कर लिया गया था।

कोविड-19 को लेकर जेएनपीटी अस्पताल की प्रतिक्रिया

महामारी के दौरान कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए रोगियों को जेएनपीटी अस्पताल ने डीसीएचसी (डेडिकेटेड कोविड स्वास्थ्य केंद्र) में नियमित निगरानी के साथ और संक्रमण नियंत्रण की कड़ी विधियों का पालन करते हुए भर्ती किया और इलाज किया। जेएनपीटी के लाभार्थियों के अतिरिक्त, अधिकांश मरीज आस-पास के गांवों से हैं। लगभग सभी भर्ती रोगियों को उनके सफलतापूर्वक स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई और उन्होंने अस्पताल में प्रदान की गई उत्कृष्ट देखभाल पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इस अस्पताल में सभी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। मरीजों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति प्रदान करने के लिए जेएनपीटी अस्पताल में एक केंद्रीय ऑक्सीजन एमजीपीएस (मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम) स्थापित किया गया है। कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन परीक्षण की सुविधा जेएनपीटी अस्पताल में उपलब्ध है और यह सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। नियमित ओपीडी से दूर स्थित एक अलग ओपीडी संदिग्ध और पॉजिटिव रोगियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। टाउनशिप और आस-पास के गांवों में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। घरों में आइसोलेट किए गए सभी रोगियों की दैनिक निगरानी की जाती है। जेएनपीटी ने बेड सहित सुविधाएं और अवसंरचना उपलब्ध कराकर बोकाडवीरा उरण में एक अन्य डीसीएचसी की स्थापना में सहयोग किया है। दोनों डीसीएचसी लोकेशनों से रोगियों के रेफरल की सुविधा के लिए जेएनपीटी द्वारा एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान की जाती हैं। महामारी के चरम के दौरान भर्ती, छुट्टी और रेफरल से संबंधित और अन्य पूछताछ के समाधान के लिए डॉक्टरों की उपस्थिति वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था। कोविड-19 से संबंधित सभी नियम और व्यवहार संबंधी मानदंडों का आईईसी डिस्प्ले के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है।

महामारी के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नेत्र शिविर और चिकित्सा जांच शिविर आयोजित नहीं किए जा सके। हालांकि, जेएनपीटी अस्पताल द्वारा नियमित मासिक टीकाकरण शिविर और वेल-बेबी क्लीनिक का आयोजन किया जाता रहा है।

एमआईवी 2030 के अनुरूप जेएनपीटी, पत्तन कर्मचारियों के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर सुदृढ़ बनाने का प्रयास करता है, ताकि 100% कर्मचारियों का उनकी नौकरी से संबंधित विशिष्ट क्षेत्र में प्रशिक्षित होने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। संरक्षा अनुभाग द्वारा नियमित संरक्षा जागरूकता और रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाता है और असुरक्षित गतिविधियों की रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। कंटेनर टर्मिनल्स और स्टोरेज यार्डों का वार्षिक संरक्षा लेखापरीक्षण, राष्ट्रीय संरक्षा परिषद द्वारा तथा ज्वलनशील और खतरनाक कार्गो के लिए टैंक फार्मों और जेटी का ओआईएसडी द्वारा किया जाता है और लेखापरीक्षा सिफारिशें की अनुपालना सुनिश्चित की जाती है। चिन्हांकन प्रक्रियाओं की ज़रूरतों के आधार पर, पत्तन हर तीन से पांच वर्ष में समस्त कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पत्तन प्रचालनों के संदर्भ में व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के बेहतर निदान और उपचार सक्षम बनाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधिकारियों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

खतरनाक सामग्रियों को प्रहस्तन के बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, एनएससी द्वारा कंटेनर टर्मिनलों का वार्षिक संरक्षा लेखापरीक्षण किया जाता है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रहस्तन के लिए विस्तृत एसओपी लागू है। हालाँकि, कोविड-19 संबंधी प्रतिबंधों के कारण पत्तन पर पीओएल और ज्वलनशील उत्पाद हैंडलिंग और स्टोरेज सुविधाओं का 2020 का ओआईएसडी लेखापरीक्षण लंबित है।

Compliance is ensured through regular safety inspection and detection of unsafe work practices and unsafe conditions. Unsafe work practices are stopped immediately and unsafe conditions are brought to the notice of the concerned officials for rectification and remedial action.

The Port strictly follows safe operating procedures for handling of hazardous bulk liquid cargo. Government explosives are handled with prior permission on direct delivery-basis under the supervision of Naval Armament Depot, in line with the Gazette Notification of the Ministry of Defence, Government of India. No storage is permitted at the Port. Radioactive materials are also handled with prior permission as per AERB Guidelines under the supervision of respective organizations, such as Nuclear Fuel Complex, on direct delivery basis.

JNPT has a well-defined risk assessment framework as per the MTMSA Guidelines. In 2020, a detailed risk assessment report was prepared by IRS (Indian Register of Shipping), Mumbai. Regular mock drills are conducted for various emergency scenarios. The fire fighting system is in place as per OISD156 Guidelines, and mock drills are conducted on a monthly basis to check its operation. The National Safety Week raises awareness among the employees on safety protocols in port areas and port-related operations. Active incident reporting, digitization of safety inspection, and stringent incident reporting are in place in the terminals of JNPT operating under the PPP model. All fatal accidents and incidents of serious nature are investigated and preventive/corrective measures and recommendations are provided to avoid occurrence of similar incidents in the future (Table 11). In 2023, the Port plans to incorporate learnings from incident assessment and mock drills, and establish regional training centres to streamline its incidence response system.

Table 11: Nature of incidents

Nature of Accidents	FY2017–18	FY2018–19	FY2019–20
Fatal	2	0	4
Non-fatal	15	19	18

The Port Safety Committee is functioning under the chairmanship of the deputy chairman, comprising all heads of departments, representatives from inspectorate dock safety, recognized unions, private terminals, Tank Farm Association, MANSA, and Central Industrial Security Force as members and invitees. The Committee meets quarterly to discuss various safety and health-related matters. The minutes of each meeting are forwarded to all the members for compliance in a time-bound manner.

नियमित सुरक्षा निरीक्षण करते हुए और असुरक्षित कार्य विधियों और असुरक्षित स्थितियों का पता लगाते हुए अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। असुरक्षित कार्य विधियों को तुरंत रोक दिया जाता है और असुरक्षित स्थितियों के संबंध में सुधार और उपचार की कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाता है।

खतरनाक बल्क लिक्विड कार्गो के प्रहस्तन के लिए पत्तन, सुरक्षित प्रचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करता है। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार, नौसेना आयुध डिपो के पर्यवेक्षण के अधीन, सीधी डिलीवरी के आधार पर पूर्व अनुमति के साथ ही सरकारी विस्फोटकों को नियंत्रित किया जाता है। पत्तन में भंडारण की अनुमति नहीं है। रेडियोधर्मी सामग्रियों को भी एईआरबी दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित संगठनों, जैसे कि नाभिकीय ईंधन परिसर के पर्यवेक्षण के अधीन सीधी डिलीवरी के आधार पर पूर्व अनुमति के साथ प्रहस्तन किया जाता है।

एमटीएमएसए दिशानिर्देशों के अनुसार जेएनपीटी ने सुपरिभाषित जोखिम मूल्यांकन रूपरेखा को अपनाया है। 2020 में, आईआरएस (इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग), मुंबई द्वारा एक विस्तृत जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई थी। विभिन्न आपातस्थितियों के लिए नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित किए जाते हैं। ओआईएसडी156 दिशानिर्देशों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था स्थापित है और इसके प्रचालन की जांच के लिए मासिक रूप से मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। पत्तन के क्षेत्रों और पत्तन से संबंधित प्रचालनों में सुरक्षा नियमों को लेकर कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाता है। जेएनपीटी के पीपीपी मॉडल के तहत प्रचालित टर्मिनलों में सक्रिय हादसा रिपोर्टिंग, सुरक्षा निरीक्षणों का डिजिटलीकरण और गंभीर दुर्घटना की रिपोर्टिंग व्यवस्था स्थापित है। सभी घातक दुर्घटनाओं और गंभीर प्रकृति के हादसों की जांच की जाती है और भविष्य में समान प्रकार की घटनाओं से बचाव के लिए निवारक/सुधारात्मक उपाय और सिफारिशें की जाती हैं (तालिका 11)। 2023 में, पत्तन ने दुर्घटना मूल्यांकन और मॉक ड्रिल से सीख को शामिल करने और अपनी दुर्घटना प्रतिक्रिया प्रणाली को व्यवस्थित बनाने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

तालिका 11: दुर्घटनाओं की प्रकृति

दुर्घटनाओं की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19	वित्तीय वर्ष 2019–20
घातक	2	0	4
गैर घातक	15	19	18

पत्तन सुरक्षा समिति, उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यरत है, जिसमें सभी विभागों के प्रमुख, गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय, मान्यता प्राप्त यूनियनों, निजी टर्मिनलों, टैंक फार्म एसोसिएशन, एमएएनएसए और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रतिनिधिगण, सदस्यों और आमंत्रितों के रूप में शामिल हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी विविध मामलों पर चर्चा करने के लिए समिति की त्रैमासिक बैठक होती है। प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त, समयबद्ध तरीके से अनुपालन के लिए सभी सदस्यों को भेजा जाता है।

The safety audit of berths and terminals / facilities handling non-flammable products was conducted through National Safety Council in September 2020 and the final Audit Report was received in early 2021. The report has been forwarded to the concerned for information and for identifying appropriate actions to be undertaken. JNPT's Fire & Safety section attended to a total of 139 calls related to fire and other emergencies during FY2020–21. No casualties were reported while attending to the emergency calls and during any of the fire fighting operations. A total of six full-scale International Ship & Port Facility Security Code (ISPS) drills were carried out during the year and the annual verification audit was carried out by Mercantile Marine Department (DG Shipping). After the successful completion of the audit, JNPT received the "Statement of Compliance" certificate.

These measures ensure that the workplace is free of undue health and safety risks, and of any physical or emotional stress that could otherwise affect the Port employees and their well-being.

Future Outlook

The port industry and the complex nature of its operations present a unique set of challenges for itself and the people engaged in the operations. While on the one hand, if unaddressed, these challenges could pose a significant risk from business continuity viewpoint. On the other hand, these could also provide an impetus to strengthen the existing efforts by identifying newer opportunities in the Port's endeavour towards creating a value chain for all the stakeholders in a sustainable manner.

Presently, one of the terminals is grappling with an ageing workforce since most of JNPT's employees have crossed 50 years of age. Moreover, there is a shortage of trained and skilled young candidates who could fill the gaps left behind by the retiring staff. This is further compounded by the lack of awareness among today's youth on the diverse career options available within the port industry.

While adequate safety systems and measures are in place and the employees are being regularly trained on all aspects of safety pertaining to their respective operations, there have been instances that have resulted in both non-fatal and fatal accidents in the past few years. Through its various initiatives and interventions, JNPT strives for and works relentlessly towards maintaining the highest standards of safety to achieve the goal of "zero accidents" in the premises. Currently, an elaborate and effective incident management tool is being developed at JNPT, which is scheduled to be completed by the end of the year 2021.

The Port's commitment towards the welfare of its workforce is an ongoing effort. New programmes, processes, and developments are being implemented to make JNPT the foremost choice among professionals. Some of the interventions include the following:

Effective Knowledge Management

The perpetual shortage of skilled manpower and the prevalence of safety concerns owing to the nature of operations in the port sector make it imperative for the industry to plan and innovate on ways and means to enhance its workforce, both qualitatively and quantitatively, on a continuous basis.

A continuous dialogue among employees and industry associations, Port authorities and other relevant stakeholders on – (a) sharing knowledge and best practices, and (b) identifying challenges and opportunities, will be the key to being future-ready and maintaining a competitive edge in the market.

It is equally important to develop a management framework to drive knowledge sharing, exchange of perspectives, ideas, information, and experience across the organization to ensure timely access to the available expertise facilitating quick and informed decision-making by all the employees.

गैर-ज्वलनशील उत्पादों को प्रहस्तन करने वाली घाटों और टर्मिनल्स / इकाइयों का सुरक्षा लेखापरीक्षण राष्ट्रीय संरक्षा परिषद द्वारा सितम्बर 2020 में आयोजित किया गया था और अंतिम लेखापरीक्षण रिपोर्ट 2021 के आरंभ में प्राप्त हुई। इस रिपोर्ट को संबंधित लोगों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर दिया गया है। जेएनपीटी के अग्नि एंव सुरक्षा अनुभाग ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान आग और अन्य आपातस्थितियों से संबंधित कुल 139 कॉलें प्राप्त कीं। आपातकालीन कॉलों पर कार्यवाही किए जाने और किसी अग्निशमन अभियान के दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। वर्ष के दौरान पूरे विस्तार वाले कुल छह अंतर्राष्ट्रीय जहाज और पत्तन सुरक्षा संहिता (आईएसपीएस) अभ्यास किए गए और मर्केंटाइल सामुद्रिक विभाग (डीजी शिपिंग) द्वारा वार्षिक सत्यापन लेखापरीक्षण किया गया। लेखापरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद, जेएनपीटी को "अनुपालन का विवरण" प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ।

ये उपाय यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित अनुचित जोखिमों से और ऐसे किसी शारीरिक या भावनात्मक तनाव से रहित है जो अन्यथा पत्तन कर्मचारियों और उनके कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं।

भविष्य का दृष्टिकोण

पत्तन उद्योग और इसके प्रचालनों की जटिल प्रकृति, इसके स्वयं के लिए तथा प्रचालनों में लगे व्यक्तियों के लिए अद्वितीय प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। जहां यदि इन चुनौतियों का समाधान न किया जाए तो ये व्यवसायिक निरंतरता के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर, ये सभी हितधारकों के लिए सस्टेनेबल तरीके से मूल्य श्रृंखला निर्मित करने की दिशा में पत्तन के प्रयासों में नई संभावनाओं की पहचान करते हुए, मौजूदा प्रयासों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रोत्साहन भी प्रदान कर सकती हैं।

वर्तमान में, एक टर्मिनल, अधिक आयु के कार्मिकसमूह वाली समस्या से ग्रस्त है क्योंकि जेएनपीटी के अधिकांश कर्मचारियों की आयु 50 वर्ष से अधिक हो गई है। इसके अलावा, ऐसे प्रशिक्षित और कुशल युवा अभ्यर्थियों की कमी है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए अंतराल को भर सकते हों। पत्तन उद्योग में उपलब्ध कैरियर के विविध विकल्पों के बारे में आज के युवाओं के बीच जानकारी न होने से यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

हालाँकि पर्याप्त सुरक्षा प्रणालियां और उपाय स्थापित हैं और कर्मचारियों को उनके कार्यों से संबंधित सुरक्षा के सभी पहलुओं के बारे में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाता रहा है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिनके परिणामस्वरूप गैर-घातक और घातक दोनों प्रकार के हादसे सामने आए हैं। अपने विभिन्न कार्यक्रमों और हस्तक्षेपों के माध्यम से, जेएनपीटी अपने परिसर में "शून्य दुर्घटनाओं" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का अथक प्रयास और परिश्रम करता है। वर्तमान में, जेएनपीटी में एक विस्तृत और प्रभावी दुर्घटना प्रबंधन टूल विकसित किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2021 के अंत तक पूरा किया जाना है।

अपनी कार्मिकशक्ति के कल्याण के लिए पत्तन की प्रतिबद्धता एक निरंतर चलने वाला प्रयास है। जेएनपीटी को पेशेवरों का सबसे पसंदीदा विकल्प बनाने के लिए नए कार्यक्रम, प्रक्रियाएं और विकास कार्य लागू किए जा रहे हैं। कुछ हस्तक्षेपों में निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रभावी ज्ञान प्रबंधन

कुशल कर्मचारियों की निरंतर कमी और पत्तन क्षेत्र में प्रचालन की विशेष प्रकृति के कारण सुरक्षा चिंताओं की व्यापकता, इस उद्योग के लिए यह अनिवार्य बनाती है कि यह अपनी कार्मिकशक्ति को निरंतर गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाने के तरीकों और साधनों की योजना बनाए और नए तरीके खोजे।

कर्मचारियों और औद्योगिक संघों, पत्तन प्राधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच (क) ज्ञान और सर्वोत्तम विधियों की साझेदारी और (ख) चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने के बारे में निरंतर संवाद, भविष्य के लिए तैयार होने और बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने की दिशा में बुनियादी रुप से महत्त्वपूर्ण होगा।

एक ऐसी प्रबंधन रुपरेखा विकसित करना समान रुप से महत्त्वपूर्ण है जो उपलब्ध विशेषज्ञता तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, पूरे संगठन में ज्ञान की साझेदारी, दृष्टिकोणों, विचारों, जानकारी और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करती हो ताकि समस्त कर्मचारियों को त्वरित और सूचित निर्णय लेने में सुगमता हो। प्रचालन संबंधी कार्यदक्षता बढ़ाने और कार्मिकशक्ति को प्रतिस्पर्धी और प्रेरित बनाने के लिए संगठन में उपलब्ध समस्त जानकारी का विधिपूर्वक संकलन, संगठन, विश्लेषण, संश्लेषण,

An effective knowledge management system entails methodical collection, organization, analysis, synthesis, dissemination, and management of all information available within the organization to bring about operational efficiency and establish a competent and motivated workforce. In 2020, Knowledge management was identified as a key issue during the course of the stakeholder engagement and materiality assessment process undertaken by JNPT.

New Employment Opportunities

The projects under Government of India's Sagarmala initiative towards realizing the vision of port-led development for India offer an opportunity for JNPT to enable the creation of new jobs (direct and indirect).

In line with the objective of port-led industrialization, in 2014, a multi-product SEZ project was conceptualized to be developed on 277.38 ha area of JNPT's freehold land. The infrastructure is being developed and companies are invited for activities such as manufacturing, logistics, warehousing, trading and services as permissible under the SEZ Acts & Rules. The JNPT SEZ phase 1 became operational in June 2020. When fully operational, the project is envisaged to generate direct and indirect employment to the tune of 57,000 jobs.

Enhancing Maritime Knowledge through Partnerships

The World Ports Sustainability Program, launched to contribute to the sustainable development of ports, is led by International Association of Ports and Harbors (IAPH) in partnership with some of the world's major port industry-related organizations.

In their three-tier systematic approach for synergies between the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) – one pillar is "Hybrid" – where initiatives across the port shall aim at leveraging wider skills and assets beyond cash. In aligning ports' contribution to Goal 17: "Partnership for the Goals", a key point highlighted is "cooperating with other ports for educational/training purposes" (i.e., joint port training programmes).

The 12 major ports in India are equipped with manpower of ~29,000 comprising around 2800 officers and about 26,000 Group C and D employees. Mandatory training programmes are regularly conducted at the JNPT–APEC Training Centre for Class I and Class II officers, ranging from 25 days' induction programme for entry-level officers to 5 days' training session for mid-level, senior-level, and board-level officers to prepare them for the next functional level in the organization hierarchy.

Community

Inclusive growth is essential as it reflects the overall growth and economic development of the country. From the beginning of its operations, community development has been one of the key focus areas for JNPT. It strongly believes that the growth and development of the Port should drive the economic stability and prosperity among the communities surrounding its premises since the port activities have a direct/indirect impact on them. JNPT recognizes that addressing the needs and concerns of project affected persons (anyone affected by land acquisition, relocation, or loss of incomes associated with project-related changes due to operational and developmental activities) is a must for effective conflict management. The Port believes that engaging with local groups and associations to implement targeted programmes that emphasize good health, quality education, sustainable livelihoods, and community infrastructure are necessary to foster good relations.

प्रसार और प्रबंधन किया जाना, एक प्रभावी ज्ञान प्रबंधन प्रणाली में आता है। 2020 में, जेएनपीटी द्वारा हितधारक सहभागिता और यथार्थता मूल्यांकन प्रक्रिया के आयोजन के दौरान ज्ञान प्रबंधन को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में चिन्हित किया गया था।

रोजगार के नए अवसर

भारत के पत्तन आधारित विकास के विजन को साकार करने की दिशा मेंभारत सरकार के सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं नई नौकरियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का सृजन सक्षम बनाने के लिए जेएनपीटी के समक्ष एक अवसर उपस्थित करती हैं।

पत्तन के नेतृत्व में औद्योगीकरण के उद्देश्य के अनुरूप, 2014 में, जेएनपीटी की फ्रीहोल्ड भूमि के 277.38 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक बहु-उत्पाद एसईजेड परियोजना विकसित करने के लिए परिकल्पित की गई। अवसंरचना को विकसित किया जा रहा है और एसईजेड अधिनियमों और नियमों के तहत अनुमति के अनुसार कंपनियों को विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, भंडारण, व्यापार और सेवाएं आदि गतिविधियों के लिए आमंत्रित किया गया है। जेएनपीटी एसईजेड फेज 1 जून 2020 से प्रचालित है। पूर्ण प्रचालित होने पर, परियोजना से 57,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की अपेक्षा है।

साझेदारी के माध्यम से सामुद्रिक ज्ञान का संवर्धन

पत्तनों के सस्टेनेबल विकास में योगदान करने के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स (आईएपीएच) के नेतृत्व में वर्ल्ड पोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम, विश्व के कुछ प्रमुख पत्तन उद्योग संबंधी संगठनों के साथ साझेदारी में शुरु किया गया है।

17 सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के मध्य पारस्परिक तालमेल के उनके त्रिस्तरीय व्यवस्थित तरीके में से – "हायब्रिड" एक आधार है – जहां पूरे पत्तन पर कार्यक्रम, नकदी से परे व्यापक कौशलों और परिसंपत्तियों का लाभ उठाने को लक्षित होते हैं। लक्ष्य 17 में योगदान के लिए पत्तनों को संरेखित करना: "लक्ष्यों के लिए साझेदारी", "शैक्षिक/प्रशिक्षण के प्रयोजनों से अन्य पत्तनों से सहयोग" (अर्थात संयुक्त पत्तन प्रशिक्षण कार्यक्रम) रेखांकित किया गया एक प्रमुख बिंदु है।

भारत में 12 प्रमुख पत्तनों में ~29,000 कार्मिक हैं जिनमें लगभग 2800 अधिकारी और लगभग 26,000 समूह सी और डी के कर्मचारी हैं। जेएनपीटी–एपीईसी प्रशिक्षण केंद्र में श्रेणी I और श्रेणी II के अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें प्रारंभिक स्तर के अधिकारियों के लिए 25 दिन के अभिप्रेरण कार्यक्रम से लेकर मध्यस्तरीय, वरिष्ठ स्तरीय और बोर्ड स्तरीय अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र तक शामिल हैं जो संगठन के पदानुक्रम में उनको अगले कार्यात्मक स्तर के लिए तैयार करने के लिए होते हैं।

समुदाय

समावेशी विकास अनिवार्य है क्योंकि यह देश की समग्र वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रतिबिंबित करता है। अपने प्रचालन की शुरुआत से ही जेएनपीटी के लिए सामुदायिक विकास एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। इसका दृढ़ विश्वास है कि पत्तन की वृद्धि और विकास से इसके परिसर के आस-पास के समुदायों में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा मिलना चाहिए क्योंकि पत्तन की गतिविधियों का उन पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जेएनपीटी का ऐसा मानना है कि परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों (प्रचालन संबंधी और विकासात्मक गतिविधियों के कारण परियोजना संबंधित परिवर्तनों की वजह से भूमि अधिग्रहण, स्थानांतरण या आय की हानि से प्रभावित कोई व्यक्ति) की ज़रूरतों और चिंताओं के समाधान करना, संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए ज़रूरी है। पत्तन का मानना है कि स्थानीय समूहों और संगठनों के साथ जुड़कर अच्छे स्वास्थ्य, गुणवत्तापरक शिक्षा, सस्टेनेबल आजीविकाओं और सामुदायिक अवसंरचना पर जोर देने वाले लक्ष्य आधारित कार्यक्रम लागू करना, अच्छे संबंधों को मज़बूत बनाने के लिए आवश्यक है।

Compensation and Rehabilitation of Project Affected Persons (PAPs)

JNPT keenly involves in rebuilding the lives of project affected persons (PAPs) and at the same time, it provides support for development to nearby villages and townships through various developmental projects.

Under the rehabilitation programme, JNPT provides direct and indirect employment to around 2600 PAPs. Till now, about 907 PAPs have been given jobs at JNPT itself. Several indirect jobs in various other activities have been promised too. Additionally, a concession of 50% in school fee has been extended to the children of PAPs in the township. The Port has drawn up a list of 10,469 PAPs to assess and facilitate the allotment of developed plots of land as a package deal under the 12.5% land allotment scheme. The implementation is underway.

Local Community Relations

Through its corporate policy and philosophy, the Port has committed to social responsibility for the benefit of the surrounding communities and society at large. As part of its CSR initiatives, the Port targets specific areas, namely, Education, Soil & Water Conservation, Skill Development, Village Development, Sanitation and Public Health, and Promotion of Art and Culture. In FY2020–21, ₹ 19.32 crore was spent towards these CSR interventions.

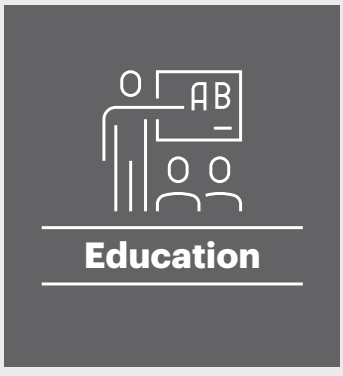

Support to Schools for Special Kids

JNPT supports Suhit Jeevan Trust which runs the "Sumangal School for "Mentally and Multiple Challenged Children" and "Light House Special Teachers Training Centre" at Taluka Pen in Raigad District of Maharashtra. JNPT lends its support to the school in carrying out awareness camps, thereby encouraging families in rural areas to enrol their children with disabilities or those with special needs in Sumangal School. JNPT assists in infrastructural development of sports grounds and classrooms in the school, and ensures provision of transport facility for the children from across the district to commute easily.

Concession in Fee for Children of PAPs

The two schools located in the port township offer pre-primary, primary, and secondary education in both English and Marathi medium. The schools cater to the needs of the children of the employees and the children of the PAPs, who reside in nearby villages. A concession of 50% in the fee is extended to the children of PAPs.v

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए मुआवजे और पुनर्वास

जेएनपीटी, परियोजनाओं प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के जीवन के पुनर्निर्माण में सक्रियतापूर्वक क्रियाशील है और इसके साथ ही यह आस-पास के गांवों और टाउनशिप के विकास के लिए, विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।

पुनर्वास कार्यक्रम के तहत, जेएनपीटी ने लगभग 2600 पीएपी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान किया है। अब तक करीब 907 पीएपी को जेएनपीटी में ही नौकरियां दी जा चुकी हैं। विभिन्न अन्य गतिविधियों में भी अनेक अप्रत्यक्ष नौकरियों का वादा किया गया है। इसके अतिरिक्त, टाउनशिप में पीएपी के बच्चों को स्कूली फीस में 50% की छूट दी गई है। पत्तन ने 12.5% भूमि आवंटन योजना के अंतर्गत पैकेज डील के रूप में विकसित भूखंडों के आकलन और आवंटन सुगमता के लिए 10,469 पीएपी की एक सूची तैयार की है। क्रियान्वयन किया जा रहा है।

स्थानीय समुदायों से संबंध

अपनी कॉर्पोरेट नीति और विचारधारा के माध्यम से पत्तन, आस-पास के समुदायों और व्यापक स्तर पर समाज के लाभ के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के साथ प्रतिबद्ध है। अपने सीएसआर कार्यक्रम के भाग के रूप में पत्तन, विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे कि शिक्षा, मृदा और जल संरक्षण, कौशल विकास, ग्राम विकास, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य और कला और संस्कृति को लक्षित करके बढ़ावा देता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में इन सीएसआर कार्यक्रमों पर, ₹ 19.32 करोड़ की राशि व्यय की गई।

विशेष बच्चों के स्कूलों को सहायता

जेएनपीटी सुहित जीवन ट्रस्ट का सहयोग करता है जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तालुका पेन में "मानसिक और बहुविकलांगता वाले बच्चों के लिए सुमंगल स्कूल" और "लाइट हाउस विशेष शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र" संचालित करता है। स्कूल को जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए जेएनपीटी सहयोग प्रदान करता है, जिनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को अपने विकलांग या विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को सुमंगल स्कूल में नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जेएनपीटी स्कूल में खेल के मैदानों और कक्षाओं के अवसंरचनात्मक के विकास में सहायता करता है और जिले भर के बच्चों के लिए आसान आवागमन के लिए परिवहन सुविधा का प्रावधान सुनिश्चित किया है।

पीएपी के बच्चों के लिए फीस में रियायत

पत्तन टाउनशिप में स्थित दो स्कूल, अंग्रेजी और मराठी माध्यमों में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ये स्कूल, कर्मचारियों के बच्चों और आस-पास के गांवों में रहने वाले पीएपी के बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पीएपी के बच्चों को फीस में 50% की रियायत दी जाती है।

Rainwater Harvesting, Conservation, and Groundwater Recharging

JNPT, in association with Sadbhavana Gramin Vikas Sanstha, Wardha, Maharashtra, took up a project for rainwater harvesting, conservation, storage, and groundwater recharge at Moti Nala, Village Mandwa in Wardha District. Under the project, widening of the waterbody was done without disturbing its natural course and silt was removed to increase the depth up to three metre. Additionally, structures were built upstream to prevent flooding and a plantation drive was carried out to prevent soil erosion and further silting of the waterbody. The initiative resulted in an increase in the total capacity of the Nala and the recharging of groundwater, which in turn, led to more land being brought under agriculture. The project aims to prevent annual flooding in the area. Through its implementation, an entire community was rehabilitated and the household income of the villagers also increased.

Soil and Water Conservation

Conservation of Khadakwasla Dam in Pune

JNPT has taken up the conservation of Khadakwasla Dam in Pune, in association with Green Thumb - a Pune-based non-governmental organization working on environmental protection and promotion of biodiversity.

Water Conservation in Drought-Affected Districts of Maharashtra

As part of CSR activity, JNPT contributed ₹ 5.6 crore toward Government of Maharashtra's Jalyukta Shivar Yojana for the drought-affected districts of Maharashtra, namely, Nandurbar, Solapur, Usmanabad, Washim, Jalna, and Yavatmal. The Jalyukta Shivar Yojana includes activities such as desilting, deep CCTs (Continuous Contour Trenches), widening and deepening of nalas/ rivers, hiring of machinery, etc. The work is carried out through the art of living (International Association for Human Values) and is supervised by the technical expert committee under the chairmanship of the district collector.

वर्षा जल संचयन, संरक्षण और भूजल पुनर्भरण

जेएनपीटी ने सद्भावना ग्रामीण विकास संस्था, वर्धा, महाराष्ट्र के सहयोग से वर्धा जिले के गांव मांडवा के मोती नाला में वर्षा जल संचयन, संरक्षण, भंडारण और भूजल पुनर्भरण के लिए एक परियोजना शुरू की। परियोजना के अंतर्गत, जलाशय के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित किए बिना चौड़ा किया गया और सिल्ट निकालकर गहराई को तीन मीटर तक बढ़ा दिया गया। इसके अतिरिक्त, बाढ़ को रोकने के लिए अपस्ट्रीम में संरचनाओं का निर्माण किया गया था और मृदा अपरदन रोकने और जलाशय में फिर से सिल्ट जमा होने से रोकने के लिए एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस पहल के परिणामस्वरूप नाले की कुल क्षमता में वृद्धि हुई और भूजल का पुनर्भरण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप, अधिक भूमि पर कृषि कार्य संभव हुआ। क्षेत्र में वार्षिक बाढ़ को रोकना इस परियोजना का उद्देश्य है। इसके क्रियान्वयन से एक पूरे समुदाय का पुनर्वास हुआ और ग्रामीणों की घरेलू आय में भी वृद्धि हुई।

मृदा और जल संरक्षण

पुणे में खडकवासला बांध का संरक्षण

जेएनपीटी ने पुणे स्थित एक गैर-सरकारी संगठन - ग्रीन थंब, जो कि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है, के साथ मिलकर पुणे में खडकवासला बांध के संरक्षण का दायित्व स्वीकार किया है।

महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों में जल संरक्षण

अपने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत जेएनपीटी ने, महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिलों, नंदुरबार, सोलापुर, उस्मानाबाद, वाशिम, जालना और यवतमाल के लिए महाराष्ट्र सरकार की जलयुक्त शिवर योजना के लिए ₹ 5.6 करोड़ का योगदान किया। जलयुक्त शिवर योजना में नालों/नदियों से सिल्ट निकालने, डीप सीसीटी (कंटीन्यूअस कंटूर ट्रेंचेज), चौड़ा करने और गहरा करने, मशीनरी किराए पर लेने आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यह काम आर्ट ऑफ लिविंग (इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज़) के माध्यम से किया जाता है और इसका पर्यवेक्षण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है।

Skill Development

CIDCO-JNPT Multi Skill Development Centre (CJMSDC) at Bokadvira Taluka in Uran

Providing livelihood through employment is one way to achieve financial stability and scope for growth for the community and JNPT has been working closely with the government to address the 'lack of skill' among the employable population in the local community. Under the Sagarmala initiative, the Ministry of Shipping intends to skill youth to fulfil the anticipated demand for the skilled labour force in the development of coastal economic zones that will further lead to port-based industrialization, coastal tourism, logistics parks, warehousing, and fisheries development (Table 12). The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE), through its stakeholders: National Skill Development Corporation (NSDC), Sector Skill Councils (SSCs), and the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), is collaborating with the major ports across the country to set up the state-of-the-art Pradhan Mantri Kaushal Kendras (PMKKs) to serve industry-driven courses in port and maritime logistics.

Table 12: Skill training at CJMSDC for the period 2019–21

Course / Year	2019–20		2020–21	
	Trained	Placed	Trained	Placed
HMV Driver	105	105	10	9
Warehouse Packer	0	0	40	23
Consignment Booking Assistant	135	83	160	74
Consignment Tracking Executive	57	31	130	63
Documentation Assistant	144	89	30	16
Inventory Clerk	85	53	70	31
Warehouse Picker	48	31	40	26
Total	574	392	480	242

Accordingly, the CIDCO-JNPT Multi Skill Development Centre (CJMSDC) – set up as a PMKK at Bokadvira Taluka in Uran – imparts training courses (residential and non-residential) to the PAPs, through its operating partner Allcargo, taking into account major forthcoming projects, namely, JNPT-SEZ, Navi Mumbai International Airport, Bharat Mumbai Container Terminal (PSA), etc.

The main objectives of CJMSDC are to: (1) skill youth in the port and logistics sector to make them employable; (2) enhance employability of students passing/graduating from regular academic courses by introducing additional skill acquisition programmes along with regular studies; and (3) empower youth with additional skill for building confidence and adding value to their current profile.

Skill Development Training in Raigad District

JNPT has partnered with Jan Shikshan Sansthan to conduct needs-based skill development training for beneficiaries from 15 villages in Raigad District. The project will benefit more than 450 beneficiaries in the area.

कौशल विकास

उरण में बोकडवीरा में सिडको-जेएनपीटी बहु कौशल विकास केंद्र (सीजेएमएसडीसी)

रोजगार के माध्यम से आजीविका प्रदान करना वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने का एक उपाय और समुदाय की वृद्धि की संभावना होता है और स्थानीय समुदाय में रोजगार योग्य जनसंख्या में 'कौशल की कमी' को दूर करने के लिए जेएनपीटी सरकार के साथ निकट सहयोग बनाकर काम कर रहा है। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत, पोत परिवहन मंत्रालय तटवर्ती आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए कुशल कार्मिकशक्ति की संभावित मांग को पूरा करने के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने का इच्छुक है जिससे पत्तन आधारित औद्योगीकरण, तटवर्ती पर्यटन, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउसिंग और मत्स्ययन विकास को बढ़ावा मिलेगा (तालिका 12)। पत्तन और सामुद्रिक लॉजिस्टिक्स में उद्योग प्रेरित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए देश भर में अत्याधुनिक प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) स्थापित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), अपने हितधारकों: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) , सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी) और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), के माध्यम से देश भर के प्रमुख पत्तनों के साथ आपसी सहयोग कर रहा है।

तालिका 12: 2019-21 की अवधि के लिए सीजेएमएसडीसी में कौशल प्रशिक्षण

पाठ्यक्रम / वर्ष	2019–20		2020–21	
	प्रशिक्षण	नियुक्त	प्रशिक्षण	नियुक्त
एचएमवी चालक	105	105	10	9
वेयरहाउस पैकर	0	0	40	23
कंसाइनमेंट बुकिंग असिस्टेंट	135	83	160	74
कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एक्जीक्यूटिव	57	31	130	63
दस्तावेज़ सहायक	144	89	30	16
इवेन्ट्री क्लर्क	85	53	70	31
वेयरहाउस पिकर	48	31	40	26
योग	574	392	480	242

तदनुरुप सिडको-जेएनपीटी बहु कौशल विकास केंद्र (सीजेएमएसडीसी) – जो कि उरण तालुका में बोकडवीरा में एक पीएमकेके के रूप में स्थापित है – यह प्रमुख आगामी परियोजनाओं, जैसे कि जेएनपीटी-एसईजेड, नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (पीएसए), आदि को दृष्टिगत रखते हुए अपने ऑपरेटिंग पार्टनर ऑलकार्गो के माध्यम से पीएपी के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (आवासीय और गैर-आवासीय) प्रदान करता है।

सीजेएमएसडीसी के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं: (1) पत्तन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशलविकास करना; (2) नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण/स्नातक कर रहे छात्रों के लिए, उनके नियमित अध्ययन के साथ अतिरिक्त कौशल अर्जन कार्यक्रम शुरु करके उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि करना; और (3) युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनके वर्तमान प्रोफ़ाइल को अधिक मूल्यवान बनाने के लिए उन्हें अतिरिक्त कौशल प्रदान करते हुए सशक्त बनाना।

रायगढ़ जिले में कौशल विकास प्रशिक्षण

रायगढ़ जिले के 15 गाँवों के लाभार्थियों के लिए आवश्यकता पर आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए जेएनपीटी ने जन शिक्षण संस्थान के साथ भागीदारी की है। इस परियोजना से इस क्षेत्र में 450 से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा।

Village Development

Support the Girl Child

Towards the adoption/construction of hostels (especially for children belonging to SC/ ST community and the girl child), as outlined in Schedule VII (Section 135) of the Companies Act, 2013, JNPT contributed an amount of ₹ 1.5 crore to Vanvasi Kalyan Ashram, Maharashtra for the construction of a girls hostel.

Promotion of Sports

To encourage rural sports, especially kabbadi in Vidarbha region in Maharashtra, JNPT contributed an amount of ₹ 5 lakh to Hanuman Krida Prasarak Va Bahuuddeshiya Mandal – an organization that has been organizing state-level kabbadi tournaments for more than seven decades.

Sanitation and Public Health

Contribution to Health and Family Welfare

JNPT organizes regular health camps for school students, contract workers, and truck drivers. JNPT is also the first major port to start the Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana at JNPT Hospital to provide quality medicines to common masses at an affordable cost. JNPT Hospital also conducts a pulse polio immunization programme with the help of the state health authority, as per the guidelines of the National Immunization Programme, achieving 100% immunization during every camp.

ग्राम विकास

बालिकाओं को समर्थन

छात्रावासों (विशेष रुप से एससी/एसटी समुदायों और बालिकाओं के लिए) गोद लेने/निर्माण कराने की दिशा में, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII (धारा 135) में उल्लेख किया गया है, जेएनपीटी ने बालिकाओं हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए ₹ 1.5 करोड़ की राशि का योगदान वनवासी कल्याण आश्रम, महाराष्ट्र को प्रदान किया।

खेलकूद को प्रोत्साहन

महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र में ग्रामीण खेलों, विशेष रुप से कबड्डी को प्रोत्साहित करने के लिए, जेएनपीटी ने हनुमान क्रीड़ा प्रसारक व बहुउद्देशीय मंडल को ₹ 5 लाख की राशि का योगदान दिया – यह एक ऐसा संगठन है जो सात दशकों से भी अधिक समय से राज्य स्तर पर कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन करता रहा है।

स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में योगदान

स्कूली छात्रों, संविदा कर्मियों और ट्रक चालकों के लिए जेएनपीटी नियमित रुप से स्वास्थ्य शिविर आयोजित करता है। जेएनपीटी ऐसा पहला प्रमुख पत्तन भी है जिसने आम जनता को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने जेएनपीटी अस्पताल में प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना शुरु की है। जेएनपीटी अस्पताल राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों की सहायता से एक पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिसमें प्रत्येक शिविर के दौरान 100% टीकाकरण किया जाता है।

Promotion of Art and Culture

Mega Tourism Project

Towards the promotion of art and culture, JNPT recently contributed a sum of ` 5 crore to Pune-based NGO Shiv Chatrapati Pratisthan. The organization is undertaking a mega tourism project comprising the exhibition of historical monuments and presentation of major incidents in the life and times of Chhatrapati Shivaji Maharaj – a brave and progressive ruler in the history of India, and the father of the freedom movement in Maharashtra – with the help of latest technology, thereby ensuring the sanctity of our heritage.

JNPT's Response to COVID-19 Crisis

Stepping up its community development efforts, JNPT has been going from village to village, carrying out disinfection and awareness drives. Additionally, it has also issued an infrared thermometer to nearby Gram Panchayats as a proactive measure to check everyone's temperature during the COVID-19 pandemic. During nationwide lockdown, food packets were distributed among truck drivers, cleaners, and other affected communities.

The Port set up a system in the OPD of JNPT Hospital ensuring isolation provision for patients who test positive for COVID-19. As a preventive measure to avoid any possible transmission of the virus, the paramedics screen the incoming patients before directing them to the OPD.

Every nook and corner of JNPT gets sanitized to ensure a healthy environment for the staff members. Sanitization efforts are carried out periodically in the neighbouring communities to ensure their safety and protection.

कला और संस्कृति को प्रोत्साहन

मेगा पर्यटन परियोजना

कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, जेएनपीटी ने हाल ही में पुणे स्थित एनजीओ शिव छत्रपति प्रतिष्ठान को ₹ 5 करोड़ की राशि का योगदान दिया। यह संगठन एक मेगा पर्यटन परियोजना पर काम कर रहा है जिसके अंतर्गत, भारत के इतिहास में प्रतिष्ठित एक वीर और प्रगतिशील शासक, व महाराष्ट्र में स्वतंत्रता आंदोलन के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक स्मारकों की प्रदर्शनी और उनके जीवन और समय की प्रमुख घटनाओं का नवीनतम प्रौद्योगिकी तकनीक की सहायता से प्रस्तुतिकरण किया जाना शामिल है, ताकि हमारी विरासत अक्षुण्ण बनी रह सके।

कोविड-19 संकट पर जेएनपीटी की प्रतिक्रिया

सामुदायिक विकास के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, जेएनपीटी ने गांवों तक पहुँचते हुए कीटाणुशोधन और जागरूकता अभियान संचालित किए हैं। इसके अलावा इसने, कोविड-19 महामारी के दौरान एक पूर्वसक्रिय उपाय के रूप में सभी लोगों के तापमान की जांच करने के लिए आस-पास की ग्राम पंचायतों को इन्फ्रारेड थर्मामीटर भी प्रदान किए। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, ट्रक ड्राइवरों, क्लीनरों और अन्य प्रभावित समुदायों में भोजन के पैकेट वितरित किए गए।

जांच में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों के लिए आइसोलेशन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पत्तन ने जेएनपीटी अस्पताल की ओपीडी में एक प्रणाली स्थापित की। वायरस के किसी भी संभावित प्रसार से बचाव के एक निवारक उपाय के रूप में, पैरामेडिक्स आने वाले रोगियों को ओपीडी में भेजने से पहले उनकी जांच करते हैं।

सभी स्टाफ सदस्यों के लिए एक स्वास्थ्यप्रद वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जेएनपीटी का कोना-कोना सैनेटाइज किया जाता है। आस-पास समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से सैनिटाइजेशन के कार्य किए जाते हैं।

Emergency Preparedness

As explained in the Maritime India Vision 2030, *"Emergency/disaster is an undesirable occurrence of events of such magnitude and nature that adversely affect operations, cause loss of human lives and property as well as damage to the environment."* JNPT recognizes that the Port region is vulnerable to both natural and technological hazards. A major emergency or disaster is characterized as an unforeseen or unexpected combination of circumstances that call for immediate and extraordinary actions. Emergencies, in the form of natural or man-made disasters, technological accidents, security threats, etc., can occur any time. Such emergency situations or disasters can lead to injury or loss of lives of port personnel as also of the people living in surrounding communities, cause damage to port infrastructure and property, or disruption of port operations.

Reducing and eliminating the risks posed by such emergencies and disasters form an integral part of JNPT's sustainability and management strategy. JNPT's first response to these possibilities is the development of a comprehensive Emergency Action Plan that describes the port wide policies to which the Port's chairman, heads of departments and senior management, and emergency response

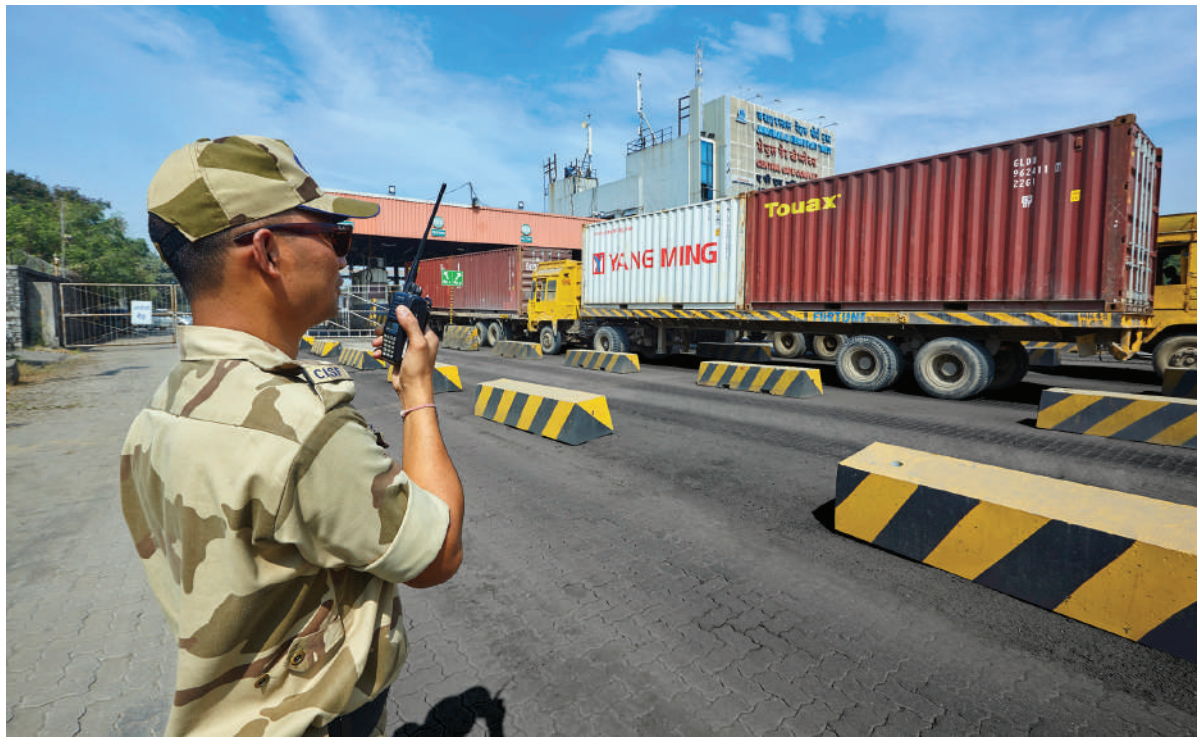

managers can refer on the event of a broad-based emergency. Developing and ensuring training and adherence to a disaster management plan that addresses safety risks, security issues, and direct negative impact to employees and assets at location due to disasters (cyclone, fire, disease etc.) can mitigate the effects of unforeseen emergencies and disasters.

JNPT's Disaster Management Plan exhibits its commitment to the safety of its employees by increasing safety awareness and defining the roles and actions necessary to prepare for and respond to any disaster situation in a coordinated manner. This plan will enable the Port to minimize or avoid the potential losses from hazards and disasters caused due to human error or natural phenomena in the Port and adjoining waters (Port limits), through the implementation of rapid, appropriate response procedures, and effective recovery. The Plan provides guidance to all the concerned departments

आपातकालीन तैयारियां

जैसा कि मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030 में उल्लेख किया गया है कि *"आपातस्थिति/आपदा ऐसे परिमाण और प्रकृति की घटनाओं के घटित होने का अवांछित क्रम होता है जो प्रचालनों को प्रतिकूल प्रभावित करती हैं, तथा मानव जीवन और संपत्ति को हानि पहुँचाने के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाती हैं।"* जेएनपीटी ऐसा समझता है कि पत्तन का क्षेत्र, प्राकृतिक और तकनीकी खतरों के प्रति असुरक्षित है। एक प्रमुख आपातस्थिति या आपदा को परिस्थितियों का ऐसा अभूतपूर्व या अप्रत्याशित संयोजन माना जाता है जो तत्काल और असाधारण कार्रवाई की मांग करता है। प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, तकनीकी दुर्घटनाओं, सुरक्षा खतरों आदि के रूप में आपातस्थितियां कभी भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी आपातकालीन स्थितियों या आपदाओं से पत्तन के कार्मिकों के अलावा आस-पास के समुदायों में रहने वाले लोगों को भी चोट या हानि पहुँच सकती है, पत्तन की अवसंरचना और संपत्ति को नुकसान हो सकता है या पत्तन के प्रचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है।

ऐसी आपातस्थितियों और आपदाओं से उत्पन्न जोखिमों को कम करना और समाप्त करना जेएनपीटी की सस्टेनेबिलिटी और प्रबंधन रणनीति का एक अभिन्न अंग है। इन संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी एक व्यापक आपातकालीन कार्य योजना का विकास, जेएनपीटी की पहली प्रतिक्रिया है जिसमें पत्तन की व्यापक नीतियों का वर्णन हो और जिसका किसी व्यापक आपातस्थिति के दौरान पत्तन के अध्यक्ष, विभागों के प्रमुख और वरिष्ठ प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधकों द्वारा संदर्भ लिया जा सके। आपदाओं

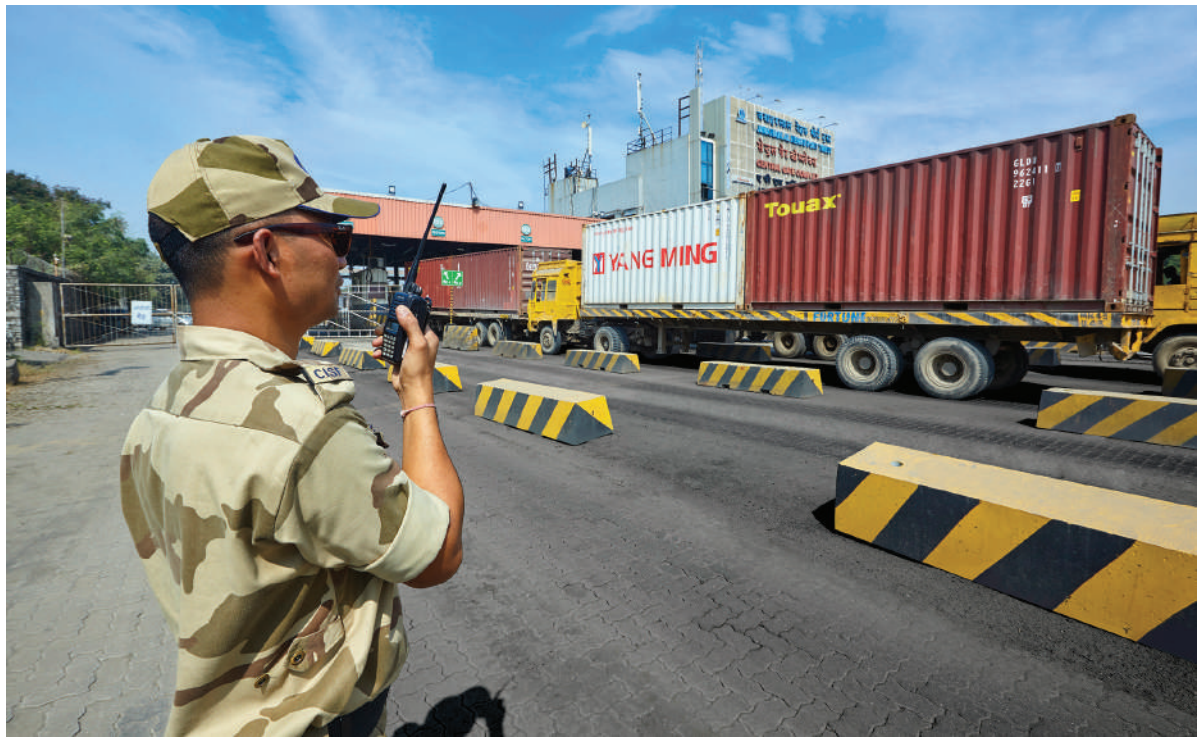

(चक्रवात, आग, बीमारी आदि) के कारण सुरक्षा जोखिमों, सुरक्षा मुद्दों, लोकेशन पर कर्मचारियों और संपत्तियों पर प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव का समाधान करने के लिए उपयुक्त आपदा प्रबंधन योजना का विकास प्रशिक्षण और पालन सुनिश्चित करना, अप्रत्याशित आपात स्थितियों और आपदाओं के प्रभावों को कम कर सकता है।

सुरक्षा संबंधी जागरूकता में वृद्धि करके और किसी आपदा वाली स्थिति के लिए पूर्वतैयारी करने और ऐसी घटना के दौरान समन्वित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए अनिवार्य भूमिकाओं और कार्यों को परिभाषित करते हुए जेएनपीटी की आपदा प्रबंधन योजना, अपने कर्मचारियों की संरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। त्वरित, उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं और प्रभावी पुनर्प्राप्ति के क्रियान्वयन के माध्यम से यह योजना मानवीय त्रुटियों के कारण या पत्तन और आस-पास के जल (पत्तन की सीमा में) में प्राकृतिक घटनाओं के कारण, हो सकने वाले खतरों और आपदाओं से संभावित नुकसान को कम करने या टालने में पत्तन को सक्षम बनाएगी।

with a general concept of potential emergency assignments before, during, and following emergency situations. The primary objectives of the Disaster Management Plan are as follows:

- Protect the lives of JNPT employees, contractors, stakeholders, visitors, and the neighbouring population
- Protect the environment
- Limit damages of port assets
- Ensure that JNPT responds according to the priorities as outlined in the action plan or those set by the chief incident controller (CIC) during response operation
- Safely restore operations back to normal as quickly as possible after occurrence of any accident
- Establish a robust response mechanism

JNPT conducts regular mock drills for various emergency scenarios in accordance with the district and state disaster management plans. The local tehsildar, police, and other concerned authorities are invited to the mock drill sessions to better prepare the local community on various emergency scenarios. Six full-scale International Ship & Port Facility (ISPS) drills were carried out during FY2020–21. The proceedings of mock drills are also publicized on various media platforms for generating awareness among the local population. The annual exercises are done at a much larger scale with more stakeholders and increased dissemination efforts.

Supply Chain

By maintaining a responsible supply chain, JNPT ensures that its suppliers and vendors comply with the (a) labour laws and standards, (b) safety requirements, (c) environmental norms.

All vendors and contractors are required to comply with the provisions of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act of 1970, Employees' State Insurance Act of 1948, the Employees Provident Fund & Misc. Provisions Act of 1952, the Payment of Wages Act of 1936, and other such laws as may be applicable.

All tenders floated by JNPT, inviting bids for service contracts, require the contractors and vendors to be paying at least the minimum wages as applicable under Central / State Government rules. As a prerequisite, the contractors must meet and ensure all statutory liabilities such as provident fund (PF), employee service scheme (ESI), and so on towards the workers they engage.

यह योजना, आपातकालीन स्थितियों से पहले, दौरान और बाद में संभावित आपातकालीन कार्यों की एक सामान्य अवधारणा के साथ सभी संबंधित विभागों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। आपदा प्रबंधन योजना के प्राथमिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- जेएनपीटी के कर्मचारियों, ठेकेदारों, हितधारकों, आगंतुकों और पड़ोसी निवासियों की जीवनरक्षा करना
- पर्यावरण का संरक्षण करना
- पत्तन की संपत्तियों के नुकसान को सीमित करना
- जेएनपीटी की प्रतिक्रियाएं, कार्य योजना में उल्लिखित प्राथमिकताओं के अनुसार या प्रतिक्रिया कार्यों के दौरान मुख्य दुर्घटना नियंत्रक (सीआईसी) द्वारा निर्धारित के अनुसार होना सुनिश्चित करना
- कोई दुर्घटना होने के बाद यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र प्रचालन को सुरक्षित रूप से सामान्य स्थिति में बहाल करना
- एक मज़बूत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करना

जिला और राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के अनुसार विभिन्न आपात स्थितियों के लिए जेएनपीटी, नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करता है। विभिन्न आपात स्थितियों के बारे में स्थानीय समुदायों को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए स्थानीय तहसीलदार, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों को मॉक ड्रिल वाले सत्रों में आमंत्रित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान पूरे विस्तार वाले कुल छह अंतर्राष्ट्रीय जहाज और पत्तन सुरक्षा संहिता (आईएसपीएस) अभ्यास किए गए। स्थानीय लोगों के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए मॉक ड्रिल की कार्यवाही का विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रचार-प्रसार भी किया जाता है। वार्षिक अभ्यास अधिक संख्या में हितधारकों के साथ, तथा व्यापक प्रसार के प्रयासों के साथ अधिक बड़े पैमाने पर किए जाते हैं।

आपूर्ति श्रृंखला

एक जवाबदेह आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखते हुए, जेएनपीटी सुनिश्चित करता है कि उसके आपूर्तिकर्ता और विक्रेता (क) श्रम कानूनों और मानकों, (ख) सुरक्षा अपेक्षाओं, (ग) पर्यावरणीय मानदंडों का पालन करें।

सभी विक्रेताओं और ठेकेदारों के लिए, ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, मजदूरियों का भुगतान अधिनियम 1936 और ऐसे ही अन्य कानून जो समय-समय पर लागू हो सकते हों, के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है।

सेवा अनुबंधों के लिए बोलियां आमंत्रित करते समय जेएनपीटी द्वारा जारी सभी निविदाओं में, ठेकेदारों और विक्रेताओं से केंद्र / राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत लागू न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। एक पूर्वापेक्षा के रूप में, ठेकेदारों को अपने द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी सेवा योजना (ईएसआई) आदि सभी वैधानिक देनदारियों को पूरा करना और सुनिश्चित करना चाहिए।

Annexures

Economic Performance

Direct Economic Value Generated and Distributed

Particulars		Amount (₹ in Crore)		
		2018–19	2019–20	2020–21*
Economic Value Generated	Revenue Generated	1989	1900	1921
Economic Value Distributed	Operating Costs	764	869	1020
	Employee Wages and Benefits	235	233	256
	Payments to Providers of Capital	113	120	67
	Payments to Government	525	703	378
	Community Investments	12	6	19
Economic Value Retained		340	(32)	181

*Note: Values of 2020–21 are provisional in nature; yet to be audited.

Defined Benefit Plan Obligations and Other Retirement Plans

Particulars	Amount (₹ in Crore)		
	2018–19	2019–20	2020–21
Gratuity (Liability as on Balance Sheet Date)	58.14	19.31	5.00
Provident Fund Contribution	26.28	30.29	45.85
Super Annuation Contribution	-	-	23.00
Total	84.42	49.6	73.85

Indirect Economic Impacts

Indirect Economic Impacts

YEAR	Significant Infrastructure Developments	Current or Expected Impacts on Communities and Local Economies	Nature and Extent of Impact (Positive or Negative)
2018-19	CSR in Communities	₹ 11.46 crore (contribution to education, hospital and research centres, etc.)	Positive – Financial assistance to village, panchayat, schools, etc.
2019-20	CSR in Communities	₹ 5.87 crore (contribution to education, hospital and research centres, etc.)	Positive – Financial assistance to village, panchayat, schools, etc.
2020-21	Special Economic Zone CSR in Communities	Direct and indirect employment opportunities to the tune of around 57,000 ₹ 19.32 crore (contribution to sports, girl child, schools for special kids, rainwater harvesting, etc.)	Positive – Financial boost to local economies Positive – Financial assistance to village, panchayat, schools, etc.

अनुलग्नक

आर्थिक निष्पादन

प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य सृजित और वितरित

विवरण		राशि (करोड़ रु. में)		
		2018–19	2019–20	2020–21*
आर्थिक मूल्य सृजित	अर्जित राजस्व	1989	1900	1921
आर्थिक मूल्य वितरित	प्रचालन व्यय	764	869	1020
	कर्मचारी वेतन और हितलाभ	235	233	256
	पूँजी प्रदाताओं को भुगतान	113	120	67
	सरकार को भुगतान	525	703	378
	समुदाय में निवेश	12	6	19
अवधारित आर्थिक मूल्य		340	(32)	181

*नोट: 2020–21 के मूल्य अनंतिम प्रकृति के हैं, जिनका लेखापरीक्षण होना अभी शेष है।

परिभाषित हितलाभ योजना दायित्व और अन्य सेवानिवृत्ति योजनाएं

विवरण	राशि (करोड़ रु. में)		
	2018–19	2019–20	2020–21
उपदान (तुलनपत्र तिथि के अनुसार देयता)	58.14	19.31	5.00
भविष्य निधि योगदान	26.28	30.29	45.85
अधिवर्षिता योगदान	-	-	23.00
योग	84.42	49.6	73.85

अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव

अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव

वर्ष	महत्वपूर्ण अवसंरचना विकास	समुदायों और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर वर्तमान या अपेक्षित प्रभाव	प्रभाव की प्रकृति और सीमा (सकारात्मक या नकारात्मक)
2018-19	समुदायों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व	₹ 11.46 करोड़ (शिक्षा, अस्पताल और अनुसंधान केंद्रों आदि में योगदान)	सकारात्मक – गांव, पंचायत, स्कूल आदि को वित्तीय सहायता।
2019-20	समुदायों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व	₹ 5.87 करोड़ (शिक्षा, अस्पताल और अनुसंधान केंद्रों आदि में योगदान)	सकारात्मक – गांव, पंचायत, स्कूल आदि को वित्तीय सहायता।
2020-21	विशेष आर्थिक क्षेत्र समुदायों के लिए निगमित सामाजिक दायित्व	लगभग 57,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर ₹ 19.32 करोड़ (खेल, बालिका, विशेष बच्चों के लिए स्कूल, वर्षा जल संचयन आदि में योगदान)	सकारात्मक – स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को वित्तीय बढ़ावा सकारात्मक – गांव, पंचायत, स्कूल आदि को वित्तीय सहायता।

Operational Efficiency

Key Performance Indicators	Unit	Reporting		
		2018–19	2019–20	2020–21
Average gross berth productivity	(moves/hr)	84.83	87.51	80.00
Average vessel turnaround time (container)	(in hr)	32.64	30.0	33.12
Average container dwell time (total – import and export)	(in hr)	—	—	44.80
Average ship daily output	(gross tonnage)	26,498	27,677	26,875

Energy

Type of Energy Used	Unit	Amount of Energy Usage		
		2018-19	2019-20	2020-21
Diesel	KL	1,594	817	947
Electricity	kWh	9,02,30,000	8,32,42,500	7,99,56,914
Electricity generated from Solar Roof-Top	kWh	22,22,827	22,14,237	21,39,714

Air Emissions

Parameters			Annual Average		
	Units	NAAQS	2018–19	2019–20	2020–21
PM10	µg/m^3	100	119	108	98
PM2.5	µg/m^3	60	51	44	43
SOx	µg/m^3	80	31	21	12
NOx	µg/m^3	80	36	18	28
CO2	ppm		347	267	196

Waste

Year	Waste Category / Name of Waste Stream	Weight of Waste Discharged (MT)	Nature of Waste – Hazardous/ Non-Hazardous	Waste Management Method
2018-19	Oily Waste as per Annex 1 of MARPOL 73/78	2362	Hazardous	Transported to Authorized Recycler by State Pollution Control Board (SPCB)
2019-20	Oily Waste as per Annex 1 of MARPOL 73/78	3516	Hazardous	Transported to Authorized Recycler by State Pollution Control Board (SPCB)
2020–21	Oily Waste as per Annex 1 of MARPOL 73/78	1586.44	Hazardous	Transported to Authorized Recycler by State Pollution Control Board (SPCB)

प्रचालन संबंधी कार्यदक्षता

प्रमुख कार्यप्रदर्शन संकेतक	इकाई	सूचना देना		
		2018–19	2019–20	2020–21
औसत सकल घाट उत्पादकता	(मूव्स/घंटे)	84.83	87.51	80.00
औसत जहाज टर्नअराउंड समय (कंटेनर)	(घंटे में)	32.64	30.0	33.12
औसत कंटेनर विश्राम समय (कुल – आयात और निर्यात)	(घंटे में)	__	__	44.80
औसत जहाज दैनिक आउटपुट	(सकल टनेज)	26498	27677	26875

ऊर्जा

प्रयुक्त ऊर्जा का प्रकार	इकाई	ऊर्जा उपयोग की मात्रा		
		2018-19	2019-20	2020-21
डीजल	किलोलीटर	1594	817	947
बिजली	किलोवाट घंटा	9,02,30,000	8,32,42,500	7,99,56,914
सोलर रुफ-टॉप से उत्पन्न बिजली	किलोवाट घंटा	22,22,827	22,14,237	21,39,714

वायु उत्सर्जन

मानदण्ड			वार्षिक औसत		
	इकाइयां	एनएएक्यूएस	2018–19	2019–20	2020–21
पीएम10	माइक्रोग्राम/मी^{3}	100	119	108	98
पीएम2.5	माइक्रोग्राम/मी^{3}	60	51	44	43
सल्फर ऑक्साईड	माइक्रोग्राम/मी^{3}	80	31	21	12
नाइट्रोजन ऑक्साईड	माइक्रोग्राम/मी^{3}	80	36	18	28
कार्बन डाइऑक्साईड	पीपीएम		347	267	196

अपशिष्ट

वर्ष	अपशिष्ट श्रेणी / अपशिष्ट प्रवाह का नाम	निस्सरित अपशिष्ट का भार (मीट्रिक टन)	अपशिष्ट की प्रकृति – खतरनाक/ गैर-खतरनाक	अपशिष्ट प्रबंधन की विधि
2018-19	मारपोल 73/78 के परिशिष्ट 1 के अनुसार तैलीय अपशिष्ट	2362	खतरनाक	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा प्राधिकृत रिसाइकिलर को भेजा गया
2019-20	मारपोल 73/78 के परिशिष्ट 1 के अनुसार तैलीय अपशिष्ट	3516	खतरनाक	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा प्राधिकृत रिसाइकिलर को भेजा गया
2020–21	मारपोल 73/78 के परिशिष्ट 1 के अनुसार तैलीय अपशिष्ट	1586.44	खतरनाक	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा प्राधिकृत रिसाइकिलर को भेजा गया

Employment

In Each Age Group	New Employees Hired			In Each Age Group	Employee Attrition		
	2018–19	2019–20	2020–21		2018–19	2019–20	2020–21
18 – 30	4	3	-	18 – 30	-	-	-
30 – 40	1	3	1	30 – 40	-	-	-
40 – 50	2	1	-	40 – 50	-	-	-
50 - Above	7	7	1	50 – Above	5	4	4

Training and Education

Employee Category	Number of Employees in Each Category			Total Hours of Training (Reporting Year)			Number of Employees Receiving Regular Performance and Career Development Review		
	2018–19	2019–20	2020–21	2018–19	2019–20	2020–21	2018–19	2019–20	2020–21
Senior Management	3	--	--	105	--	--	3	--	1
Middle Management	30	101	5	750	2100	150	26	17	--
Shopfloor Personnel	117	246	22	1800	3250	320	225	456	132

Diversity and Equal Opportunity

Age Group	Employees in the Organization as per Age Category		
	2018–19	2019–20	2020–21
18 – 30	7	7	6
30 – 40	51	42	39
40 – 50	220	215	201
50 – Above	1243	1209	1157

रोजगार

प्रत्येक आयु समूह में	नए नियुक्त कर्मचारी			प्रत्येक आयु समूह में	कर्मचारी क्षरण		
	2018–19	2019–20	2020–21		2018–19	2019–20	2020–21
18 – 30	4	3	-	18 – 30	-	-	-
30 – 40	1	3	1	30 – 40	-	-	-
40 – 50	2	1	-	40 – 50	-	-	-
50 - अधिक	7	7	1	50 – अधिक	5	4	4

प्रशिक्षण और शिक्षा

कर्मचारी की श्रेणी	प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की संख्या			प्रशिक्षण के कुल घंटे (रिपोर्टिंग वर्ष)			नियमित कार्यप्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या		
	2018–19	2019–20	2020–21	2018–19	2019–20	2020–21	2018–19	2019–20	2020–21
वरिष्ठ प्रबंधन	3	--	--	105	--	--	3	--	1
माध्यमिक प्रबंधन	30	101	5	750	2100	150	26	17	--
शॉपफ्लोर कार्मिक	117	246	22	1800	3250	320	225	456	132

विविधता और समान अवसर

आयु वर्ग	आयु वर्ग के अनुसार संगठन में कर्मचारी		
	2018–19	2019–20	2020–21
18 – 30	7	7	6
30 – 40	51	42	39
40 – 50	220	215	201
50 – अधिक	1243	1209	1157

GRI Content Index

GRI 101: Foundation 2016

GRI 102: General Disclosures 2016

Disclosures		Reference Page Number or Weblink	Omissions – Reasons and Explanations
Organizational profile			
102-1	Name of the organization	4	
102-2	Activities, brands, products, and services	12	
102-3	Location of headquarters	4,12	
102-4	Location of operations	14,16	
102-5	Ownership and legal form	26	
102-6	Markets served	12	
102-7	Scale of the organization	12,60,108,110	
102-8	Information on employees and other workers	108,110	
102-9	Supply chain	132	
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	NA	First Sustainability Report of JNPT
102-11	Precautionary Principle or approach	42,44,78,80,82,84,86,92,94 96,98,112,114,130	
102-12	External initiatives	92,120,122,124,126,	
102-13	Membership of associations	114	
Strategy			
102-14	Statement from senior decision-maker	6,8	
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	38,42,44	
Ethics and integrity			
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	26	
Governance			
102-18	Governance structure	26,28	
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental and social topics	26,30,32	
Stakeholder engagement			
102-40	List of stakeholder groups	36	
102-41	Collective bargaining agreements	102	
102-42	Identifying and selecting stakeholders	34,36	
102-43	Approach to stakeholder engagement	32,34,36	

Disclosures		Reference Page Number or Weblink	Omissions – Reasons and Explanations
102-44	Key topics and concerns raised	38	
Reporting practice			
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	4	
102-46	Defining report content and topic Boundaries	32,34,36,38	
102-47	List of material topics	38	
102-48	Restatements of information	NA	First Sustainability Report of JNPT
102-49	Changes in reporting	NA	First Sustainability Report of JNPT
102-50	Reporting period	4	
102-51	Date of most recent report	NA	First Sustainability Report of JNPT
102-52	Reporting cycle	4	
102-53	Contact point for questions regarding the report	4	
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	4	
102-55	GRI context index	140,141,142,143	
102-56	External assurance	NA	Report is not externally assured

GRI 200: Economic Topics

Disclosure		Reference Page Number or weblink	Omissions – Reasons and Explanations
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	38	
103-2	The management approach and its components	30,40,42,44,60, 78,80,82,96 98,114,116	
103-3	Evaluation of the management approach	10,54,56,58,60,62,63,68,69, 72,76, 94,134,136,138	
GRI 201: Economic Performance 2016			
201-1	Direct economic value generated and distributed	48,134	
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	96,98	
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	50,134	

Disclosure		Reference Page Number or weblink	Omissions – Reasons and Explanations
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016			
203-1	Infrastructure investments and services supported	50,122,124,126,128,134	
203-2	Significant indirect economic impacts	134	

GRI 300: Environmental Topics

Disclosure		Reference Page Number or weblink	Omissions – Reasons and Explanations
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	38	
103-2	The management approach and its components	30,40,42,44,60, 78,80,82,96 98,114,116	
103-3	Evaluation of the management approach	10,54,56,58,60,62,63,68,69, 72,76, 94,134,136,138	
GRI 302: Energy 2016			
302-1	Energy consumption within the organization	94,136	
302-5	Reductions in energy requirements of products and services	94,96	
GRI 303: Water and Effluents 2018			
303-1	Interactions with water as a shared resource	80	
303-5	Water Consumption	82	
GRI 304: Biodiversity 2016			
304-2	Significant impacts of activities, products, and services on biodiversity	88,90	
GRI 306: Waste 2020			
306-2	Management of significant waste-related impacts	82	
GRI 307: Environmental Compliance 2016			
307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	84,86	

GRI 400: Social Topics

Disclosure		Reference Page Number or weblink	Omissions – Reasons and Explanations
GRI 103: Management Approach 2016			
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	38	
103-2	The management approach and its components	30,40,42,44,60, 78,80,82,96 98,114,116	
103-3	Evaluation of the management approach	10,54,56,58,60,62,63,68,69, 72,76, 94,134,136,138	
GRI 401: Employment 2016			
401-1	New employee hires and employee turnover	138	
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	50,102,104,134	
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018			
403-1	Occupational health and safety management system	114	
403-9	Work-related injuries	114	
GRI 404: Training and Education 2016			
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	106,118	
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016			
405-1	Diversity of governance bodies and employees	104,138	
GRI 406:Non-Discrimination 2016			
406-1	Incidents of discrimination and corrective actions taken	102	
GRI 412: Human Rights Assessment 2016			
412-3	Significant investment agreements and contracts that include human rights clauses or that underwent human rights screening	102	
GRI 413: Local Communities 2016			
413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	124	
413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	120,122,124,126,128	
GRI 419: Socioeconomic Compliance 2016			
419-1	Non-compliance with laws and regulations in the social and economic area	114,116,130,132	

INDIA'S NO.1 CONTAINER PORT

Jawaharlal Nehru Port Trust,
Admin Building, Sheva, Uran,
Raigad - 400 707
Phone:+91 22 2724 4022
Fax:+91 22 2724 4020